● वर्ष-4
● अंक-104
रायपुर, मंगलवार
10 दिसंबर 2024
● पृष्ठ-8
● मूल्य-3 रु.

।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

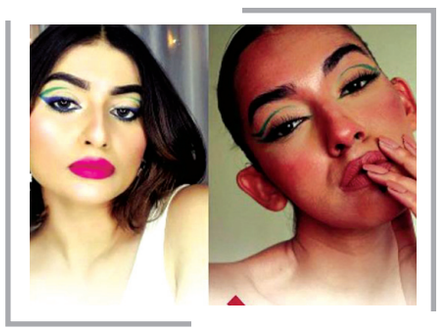

पेज-6» काजल के इन नए शेड्स

कुंभ मेले में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए खास व्यवस्था

प्रयागराज। दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में से एक, महाकुंभ 2025 को लेकर उत्तर प्रदेश अपनी तैयारी कर रहा है। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार मेले में आने वाले भक्तों की सटीक संख्या सुनिश्चित करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता-सक्षम कैमरे स्थापित करने की योजना बना रही है। सरकार ने बयान जारी कर कहा कि अब तक प्रयागराज में हर 6 साल में होने वाले कुंभ या हर 12 साल में होने वाले महाकुंभ में श्रद्धालुओं की सही संख्या गिनने की कोई सटीक तकनीक नहीं थी।

हालांकि, इस बार योगी आदित्यनाथ सरकार ने एआई के साथ-साथ कई अन्य प्रकार की तकनीकों से लैस विशेष कैमरों का सहारा लेने का फैसला किया है ताकि महाकुंभ में आने वाले प्रत्येक श्रद्धालु की गिनती की जा सके। सरकार ने इन तकनीकों के जरिए महाकुंभ में श्रद्धालुओं को ट्रैक करने की भी व्यवस्था की है। सरकार ने कहा कि सटीक हेडकाउंट डेटा सुनिश्चित करने के लिए एआई-सक्षम कैमरे बड़े पैमाने पर तैनात किए जा रहे हैं। बयान में कहा गया है कि ये उन्नत कैमरे हर मिनट वास्तविक समय अपडेट प्रदान करेंगे, जिसका प्राथमिक ध्यान घाटों पर भक्तों पर नज़र रखने पर होगा। प्रणाली सुबह 3 बजे से शाम 7 बजे तक सक्रिय रूप से काम करेगी, जो स्नान अनुष्ठानों के लिए सबसे व्यस्त समय है।

इसकी जानकारी देते हुए मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत ने बताया कि 2025 में होने वाले महाकुंभ में 40 करोड़ से ज्यादा लोगों के आने की उम्मीद है और यह अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड होगा. पंत के मुताबिक इतनी बड़ी संख्या में लोगों की गिनती और उन पर नजर रखने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने कहा कि मेला क्षेत्र के भीतर 200 स्थानों पर लगभग 744 अस्थायी सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, जबकि शहर भर में 268 स्थानों पर 1,107 स्थायी सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इसके अतिरिक्त, निर्बाध ट्रैकिंग और भीड़ प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए 100 से अधिक पार्किंग क्षेत्रों में 720 सीसीटीवी कैमरे तैनात किए जा रहे हैं।

हार पचा नहीं पा रहा इंडि गठबंधन

महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगा इंडिया गठबंधन

नई दिल्ली। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद दिल्ली में एनसीपी (एसपी) शरद पवार के आवास पर अहम बैठक हुई है। इस बैठक में दिल्ली के पूर्व सीएम और आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी बैठक समेत कई विपक्षी नेता शामिल हुए। इस बैठक में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों पर चर्चा हुई, इसके बाद गठबंधन के नेताओं ने ये फैसला लिया कि वे सभी इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे।वहीं इस बैठक में शामिल एनसीपी (एसपी) पुणे के अध्यक्ष प्रशांत सुदामराव जगताप ने कहा, %आज की बैठक में, हमने भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन को जिताने के लिए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में हुए घोटाले के संबंध में इंडिया गठबंधन के रूप में सुप्रीम कोर्ट में पेश होने का फैसला किया है। महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन के सभी दल अदालत जाएंगे। हमें सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है और हम उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट हमारे पक्ष में और घोटाले के खिलाफ फैसला सुनाएगा।%

चुनाव में महायुति और एमवीए

महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मुख्य मुकाबला महायुति और महा विकास अघाड़ी गठबंधनों के बीच था। जिसमें महायुति ने 288 विधानसभा सीटों में से 230 सीटों पर जीत हासिल की। इसमें भाजपा ने अकेले 132 सीट, एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने 57 और अजित पवार गुट की एनसीपी ने 41 सीटें जीती। महायुति गठबंधन के तीनों घटक दल भाजपा, शिवसेना और एनसीपी क्रमशः राज्य की शीर्ष तीन पार्टियां हैं। वहीं इसके उलट महा विकास अघाड़ी को 288 सीटों में से मात्र 46 सीटें ही मिली। इसमें उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी ने 20 सीट, कांग्रेस ने 16 और शरद पवार की एनसीपी-एसपी ने सिर्फ 10 ही सीटें जीती है।

चुनाव आयोग का इनकार

चुनाव आयोग ने मंगलवार को हाल ही में हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में वोटों के वीवीपैट सत्यापन में विसंगति के विपक्ष के आरोप से इनकार करते हुए कहा कि किसी भी वीवीपैट मतदाता पर्चियों में उनके ईवीएम नंबरों के साथ कोई बेमेल नहीं पाया गया। बयान में कहा गया है कि 23 नवंबर को मतगणना के दिन चुनाव आयोग ने कुल 1,445 वीवीपैट पर्चियों की गिनती की और किसी भी वीवीपैट पर्ची में उनके संबंधित ईवीएम नंबरों के साथ कोई मिलान नहीं पाया गया। 2 दिसंबर को, चॉकलिंगम ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) के साथ छेड़छाड़ के संबंध में झूठे दावे या आक्षेप फैलाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी थी। उनका यह बयान हाल ही में महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के दौरान ईवीएम में गड़बड़ी को लेकर महा विकास अघाड़ी नेताओं के लगातार आरोपों के बीच आया है। चोकलिंगम ने रेखांकित किया था कि इन मामलों को सनसनीखेज बनाने के किसी भी प्रयास से गंभीरता से निपटा जाएगा क्योंकि अधिकारी इस मुद्दे की जांच तेज कर देंगे। इससे पहले, महाराष्ट्र एनसीपी-एसपी प्रमुख जयंत पाटिल ने हाल के विधानसभा चुनावों में ईवीएम के इस्तेमाल पर चिंता जताई और शाम 5 बजे के बाद मतदान प्रतिशत में वृद्धि पर सवाल उठाया। उन्होंने चुनावी प्रक्रिया में जनता का विश्वास बहाल करने के लिए मतपत्रों की वापसी का आह्वान किया। इससे पहले, महाराष्ट्र एनसीपी-एसपी प्रमुख जयंत पाटिल ने हाल के विधानसभा चुनावों में ईवीएम के इस्तेमाल पर चिंता जताई और शाम 5 बजे के बाद मतदान प्रतिशत में वृद्धि पर सवाल उठाया। उन्होंने चुनावी प्रक्रिया में जनता का विश्वास बहाल करने के लिए मतपत्रों की वापसी का आह्वान किया। विशेष रूप से, हाल ही में हुए महाराष्ट्र चुनावों में महा विकास अघाड़ी (एमवीए) को बड़ा झटका लगा, जब कांग्रेस को 288 विधानसभा सीटों में से सिर्फ 16 सीटें मिलीं।

इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज के खिलाफ महाभियोग

नई दिल्ली। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने कहा कि वह और कुछ अन्य सदस्य विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) के एक कार्यक्रम में कथित मुस्लिम विरोधी नफरत भरा भाषण देने वाले इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश शेखर कुमार यादव पर महाभियोग चलाने के लिए एक प्रस्ताव पेश करेंगे। सिब्बल ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि मैंने दिग्विजय सिंह, विवेक तन्खा, मनोज झा, जावेद अली और जॉन ब्रिटास से बात की है। उन्होंने कहा कि हम जल्द ही मिलेंगे और जज के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाएंगे. और कोई रास्ता नहीं। यह शब्द के हर मायने में नफरत फैलाने वाला भाषण है।

उन्होंने कहा कि जो भी न्यायाधीश ऐसा बयान देता है, वह अपने पद की शपथ का उल्लंघन कर रहा है। यदि वह पद की शपथ का उल्लंघन कर रहा है, तो उसे उस कुर्सी पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है। सिब्बल की यह टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट द्वारा न्यायमूर्ति यादव द्वारा दिए गए भाषण पर संज्ञान लेने और इलाहाबाद उच्च न्यायालय को मामले का विवरण प्रदान करने का निर्देश देने से पहले आई है।

सिब्बल ने कहा कि यदि एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश इस तरह का भाषण दे सकता है तो सवाल उठता है कि ऐसे लोगों की नियुक्ति कैसे हो जाती है। सवाल यह भी उठता है कि उन्हें ऐसी टिप्पणी करने का साहस कैसे मिलता है।

क्या कहा न्यीयमूर्ति ने

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मौजूदा न्यायाधीश न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव ने प्रस्तावित यूसीसी के लिए समर्थन व्यक्त किया था, जिसमें विभिन्न धर्मों और समुदायों पर आधारित असमान कानूनी प्रणालियों को खत्म करके सामाजिक सद्भाव, लैंगिक समानता और धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देने की क्षमता पर प्रकाश डाला गया था। कार्यक्रम में बोलते हुए, न्यायमूर्ति यादव ने कहा था कि यूसीसी का उद्देश्य विभिन्न व्यक्तिगत कानूनों को प्रतिस्थापित करना है जो वर्तमान में विभिन्न धार्मिक समुदायों के भीतर व्यक्तिगत मामलों को नियंत्रित करते हैं, न केवल समुदायों के बीच बल्कि एक समुदाय के भीतर कानूनों की एकरूपता सुनिश्चित करना है। यह पहली बार नहीं है जब जस्टिस यादव के बयान पर बहस छिड़ी है. सितंबर 2021 में गोहत्या से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान उन्होंने गाय को भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित करने की वकालत की. उन्होंने उस समय कहा कि जब संस्कृति और आस्था को चोट पहुंचती है, तो देश कमजोर हो जाता है।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 10 दिसम्बर मंगलवार को छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद वीर नारायण सिंह के शहादत दिवस पर उनकी जन्मभूमि एवं कर्मभूमि सोनाखान में आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री साय सोनाखान स्थित शहीद स्मारक में शहीद वीर नारायण सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने शहीद वीर नारायण सिंह संग्रहालय का भी अवलोकन किया।

प्रमुख समाचार

180 साल पुराने नूरी जामा मस्जिद पर चला बुलडोजर

फतेहपुर। उत्तर प्रदेश के फ़तेहपुर जिले में 180 साल पुरानी नूरी जामा मस्जिद के एक बड़े हिस्से को जिला प्रशासन द्वारा नोटिस जारी करने के बाद मंगलवार को बुलडोज़र से ढहा दिया गया। एक अधिकारी ने कहा कि बांदा सागर रोड पर ललौली शहर में स्थित मस्जिद समिति द्वारा दो नोटिस जारी किए जाने के बाद भी अतिक्रमण हटाने में विफल रहने के बाद विध्वंस हुआ। जिस हिस्से को ढहाया गया, उसका निर्माण पिछले तीन वर्षों में बांदा-बहराइच रोड पर मस्जिद का विस्तार करने के लिए किया गया था, जिससे सड़क के प्रस्तावित चौड़ीकरण में बाधा उत्पन्न हुई। ध्वस्त खंड का निर्माण पिछले तीन वर्षों में बांदा-बहराइच रोड (राज्य राजमार्ग 13) पर मस्जिद का विस्तार करने के लिए किया गया था, जिससे सड़क के प्रस्तावित चौड़ीकरण में बाधा उत्पन्न हुई। मस्जिद को गिराने के लिए PWD विभाग ने एक महीने पहले नोटिस दिया था। यूपी सरकार ने कहा कि फतेहपुर जिले के बहराइच-बांदा मार्ग (एसएच-13) को चौड़ा करने के लिए पीडब्ल्यूडी सड़क किनारे अवैध निर्माण हटा रहा है।

इंडिया गठबंधन के नेताओं के बयान पर न करें टिप्पणी-राहुल

नई दिल्ली। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को अपनी पार्टी के सांसदों को कहा कि वे विपक्षी गठबंधन इंडिया के घटक दलों के नेताओं के बयानों पर टिप्पणी करने से परहेज करें क्योंकि अगर कोई मुद्दा है तो उसे पार्टी नेतृत्व देखेगा। सूत्रों के अनुसार पार्टी के लोकसभा सदस्यों के साथ बैठक में राहुल गांधी ने यह भी कहा कि सांसदों को जनहित से जुड़े मुद्दों को उठाते रहने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। राहुल गांधी की यह सलाह ऐसे समय में आई है, जब भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न नेता नेतृत्व के मुद्दे को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। वहीं तृणमूल कांग्रेस के नेता आक्रामक तरीके से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को विपक्षी गठबंधन का नेतृत्व सौंपने की वकालत कर रहे हैं। सूत्रों ने बताया कि राहुल गांधी ने मंगलवार सुबह पार्टी के लोकसभा सांसदों की बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने सांसदों से यह भी कहा कि वे सुनिश्चित करें कि संसद की बैठकों से पहले पार्टी के विरोध प्रदर्शन में भी सभी मौजूद रहें, खासकर तब जब कांग्रेस अध्यक्ष इसमें भाग ले रहे हों।

संभल में मृतकों के परिजनों से मिले राहुल और प्रियंका

संभल। संभल जामा मस्जिद सर्वे के दौरान हुए बवाल में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों ने दिल्ली पहुंचकर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मुलाकात की है। मुलाकात कर लौटे मृतकों के परिजनों ने बताया कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने हर संभव मदद करने का वादा किया है। साथ ही न्याय मिलने का भी भरोसा दिया है। यह मुलाकात करीब 15 मिनट की रही है। सरायतरीन निवासी बिलाल, हयातनगर निवासी रोमान, कोटगर्वी निवासी अयान, नईम और तुर्तीपुर इल्हा निवासी कैफ के परिजनों ने मुलाकात की है। मृतक बिलाल के भाई सलमान ने बताया कि वह मंगलवार की सुबह दिल्ली के लिए निकले थे। दोपहर में राहुल गांधी के आवास पर पहुंच गए थे। शाम को चार बजे सभी पीड़ित परिवारों से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने मुलाकात की। बताया कि कांग्रेस के प्रदेश सचिव सचिन चौधरी और मुरादाबाद के कांग्रेस से पूर्व विधायक रिजवान कुरैशी मुलाकात कराने के लिए लेकर पहुंचे थे। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने पूरी घटना की जानकारी ली है। साथ ही हर संभव मदद मिलने का भरोसा दिया है।

नहीं माने किसान, 14 दिसंबर को फिर से शुरू करेंगे मार्च

नई दिल्ली। किसानों ने सरकार की ओर से बातचीत के लिए निमंत्रण न मिलने का हवाला देते हुए 14 दिसंबर को एक बार फिर दिल्ली मार्च करने की योजना की घोषणा की है। किसान नेताओं ने कहा कि 101 किसानों का एक समूह इस विरोध प्रदर्शन के तहत दिल्ली जाएगा। इस कदम का उद्देश्य न्यूनतम समर्थन मूल्य और ऋण माफी के लिए कानूनी गारंटी सहित अपनी मांगों के लिए सरकार पर दबाव डालना है। किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने घोषणा की कि शंभू बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसान 14 दिसंबर को एक बार फिर दिल्ली की ओर मार्च करेंगे। पंधेर ने कहा कि उनके विरोध प्रदर्शन को अब 303 दिन हो गए हैं और न्याय की मांग को लेकर किसानों का अनशन 15वें दिन पर पहुंच गया है। पंधेर ने इस बात पर जोर दिया कि किसान हमेशा बातचीत के लिए खुले हैं, लेकिन उनके प्रयासों के बावजूद सरकार ने उनसे संपर्क नहीं किया है। उन्होंने कहा कि हमने हमेशा बातचीत का स्वागत किया है, लेकिन सरकार की ओर से किसी ने भी हमसे संपर्क नहीं किया है।

मोहम्मद अल-बशीर को अंतरिम सरकार के प्रमुख होंगे

नई दिल्ली। पश्चिम एशियाई देश सीरिया में विद्रोहियों ने मोहम्मद अल-बशीर को अंतरिम सरकार का प्रमुख नियुक्त किया है। खबरों में यह दावा किया जा रहा है। इस्लामी समूह हयात तहरीर अल-शाम (एचटीएस) के नेतृत्व में विद्रोहियों ने राजधानी दमिश्क पर कब्जा करने के बाद मोहम्मद अल-बशीर को अंतरिम सरकार का मुखिया चुना। बता दें कि विरोध बढ़ने के बाद राष्ट्रपति बशर अल-असद को देश छोड़कर भागने पर मजबूर होना पड़ा। अपदस्थ राष्ट्रपति असद को फिलहाल रूस ने राजनीतिक शरण दी है। इससे पहले सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल-असद के रूस भागने और देश पर विद्रोहियों का कब्जा होने के बाद राजधानी दमिश्क की सड़कों पर जबरदस्त जश्न मनाया गया। विद्रोहियों ने असद के शासन में कैद किए गए कई कैदियों को भी सोमवार तड़के कालकोठरियों से मुक्त कराया। असद परिवार के करीब 50 वर्षीय शासन को सिर्फ 10 दिनों में विद्रोहियों ने हमला बोलकर खत्म कर दिया और अब राजनीतिक कैदियों को आजाद कराने के लिए जेलों व सुरक्षा सुविधाओं में तोड़फोड़ की।

उपराष्ट्रपति के खिलाफ विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव का सफल होना मुश्किल

शिवेंद्र तिवारी

विपक्ष राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में है। कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्ष ने मंगलवार को जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए उच्च सदन को नोटिस दिया। इसमें सभापति पर %पक्षपातपूर्ण तरीके से काम करने% का आरोप लगाया गया है। नोटिस में विपक्षी समूह के 60 से ज्यादा सांसदों के हस्ताक्षर हैं। इस अविश्वास प्रस्ताव की तैयारी के बीच सत्ता पक्ष और विपक्ष में राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई है। भाजपा ने नोटिस का विरोध जताया है। वहीं, विपक्षी कांग्रेस ने कहा कि सभापति धनखड़ ने आसन की गरिमा को ठेस पहुंचाई है।

हमारे देश में राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति दूसरा सबसे बड़ा संवैधानिक पद है। उपराष्ट्रपति के कार्यकाल का जिक्र भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 में किया गया है। वह पांच साल के कार्यकाल के लिए पद पर रहते हैं। हालांकि, कार्यकाल खत्म होने के बावजूद अगला उपराष्ट्रपति बनने तक वह पद पर बने रह सकते हैं। संविधान में प्रावधान है कि राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति कार्य करेंगे। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंपकर पद से इस्तीफा दे सकते हैं।

अनुच्छेद 64 कहता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होंगे और वह किसी अन्य लाभ के पद पर नहीं होंगे। पांच वर्ष के कार्यकाल से पहले ही उपराष्ट्रपति के पद से हटने की केवल दो ही स्थितियां होती हैं। पहली स्थिति तब होगी जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति खुद अपना त्यागपत्र दे दें और दूसरी स्थिति तब होगी जब उन्हें पद से हटा दिया जाएगा। जिस प्रक्रिया के तहत उपराष्ट्रपति पद से हटा दिया जाएगा उसे अविश्वास प्रस्ताव कहते हैं।

अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया

संविधान के अनुच्छेद 67बी में उपराष्ट्रपति को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया का उल्लेख है। उपराष्ट्रपति पद से हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। संसद में प्रस्ताव लाने से पहले कम से कम 14 दिन पहले सदन को सूचित करना होता है। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रस्ताव पेश करने के लिए न्यूनतम आवश्यक संख्या 50 है। वहीं अभी 60 विपक्षी सांसदों ने नोटिस पर हस्ताक्षर किए हैं।

इस प्रस्ताव को राज्यसभा द्वारा पारित किया जाना चाहिए और उन्हें हटाने के लिए लोकसभा द्वारा उस पर सहमति होनी चाहिए। इसलिए, यदि राज्यसभा के सभापति धनखड़ के खिलाफ प्रस्ताव ऊपरी सदन में पारित हो जाता है, तो सफल होने के लिए इसे लोकसभा में साधारण बहुमत से पारित होना चाहिए। नियमों के अनुसार, मतदान करने वाले राज्यसभा सांसदों द्वारा प्रस्ताव को साधारण बहुमत से पारित किया जाना चाहिए। फिर इसे निचले सदन में भी इसी बहुमत से पारित होना चाहिए। चूंकि विपक्ष के पास स्पष्ट बहुमत नहीं है, इसलिए धनखड़ को हटाया जाना मुश्किल है।

अविश्वास प्रस्ताव क्यों

दरअसल, विपक्ष कई मुद्दों को लेकर धनखड़ से नाराज है। इसमें सबसे ताजा मामला यह है कि उन्होंने उच्च सदन में सत्ता पक्ष के सदस्यों को कांग्रेस-सोरोस संबंध का मुद्दा उठाने की अनुमति दी। कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह ने राज्यसभा के सभापति पर पक्षपात करने का आरोप लगाया था। इससे पहले इस साल अगस्त में भी विपक्षी गठबंधन की पार्टियों ने उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटाने के लिए प्रस्ताव पेश करने के लिए नोटिस देने पर विचार किया था।

कौन-कौन समर्थन में कौन विरोध में?

सूत्रों के मुताबिक, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी (आप), समाजवादी पार्टी (सपा) समेत विपक्षी गठबंधन के कई सदस्य इस प्रस्ताव को आगे बढ़ाने के लिए साथ हैं। हालांकि, तृणमूल कांग्रेस के रुख पर अब भी संशय नहीं बना हुआ है। इस बीच बीजू जनता दल के अध्यक्ष नवीन पटनायक ने कहा कि उनकी पार्टी राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के इंडिया ब्लॉक के कदम पर सोच-समझकर ही फैसला करेगी। राज्यसभा में बीजद इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि विपक्षी दलों के पास सदन में प्रस्ताव को पारित कराने के लिए अपेक्षित संख्या नहीं है।

सत्ता पक्ष की प्रतिक्रिया

भाजपा समेत एनडीए के दलों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया है। इस मामले पर केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, विपक्ष ने आसन की गरिमा का अनादर किया है, चाहे वह राज्यसभा हो या लोकसभा। कांग्रेस पार्टी और उनके गठबंधन ने लगातार आसन के निर्देशों का पालन न करके गलत व्यवहार किया है। उपाध्यक्ष जगदीप धनखड़ एक साधारण पृष्ठभूमि से आते हैं। वह संसद के अंदर और बाहर हमेशा किसानों और लोगों के कल्याण की बात करते हैं।

माता रुक्मणी आश्रम के 35 बच्चे बीमार

■ एक बच्ची की मौत, नौ आईसीयू में भर्ती

बीजापुर। बीजापुर के धनोरा में संचालित माता रुक्मणी आश्रम के 35 बच्चे एक साथ उल्टी, दस्त व बुखार कि पीड़ा से अचानक बीमार पैड गए। इन्हे फौरन जिला अस्पताल मे भर्ती कराया गया हैं। इलाज के दौरान एक बच्ची की गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे जगदलपुर रेफर किया गया था। लेकिन बच्ची की रास्ते मे ही मौत गई है। वही 9 बच्चो कि हालत ज्यादा खराब होने से उन्हें जिला अस्पताल के आईसीयू वार्ड मे भर्ती कर इलाज किया जा रहा हैं।

पीडियाट्रिक डॉक्टर मंगेश ने बताया कि फूड पॉयजनिंग से पीड़ित 34 बच्चों को अस्पताल लाया गया था, सुबह एक और बच्ची शिवानी तेलम की तबियत ज्यादा बिगड़ने पर उसे यहां लाया गया था। बच्ची की गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे जगदलपुर रेफर किया गया था। किंतु रास्ते मे ही बच्ची की मौत हो गई। डॉक्टर मंगेश ने बताया कि फूड पॉजिनिग की वजह से ही बच्चे बीमार हुए है। बता दें रोज कि तरह माता रुकमणी आश्रम में खाना खाने के बाद बच्चों की तबियत अचानक बिगडनें लगी। एक के बाद एक बच्चे उल्टी दस्त का शिकार होते गए।

तत्काल उन्हें जिला अस्पताल लाया गया। जहां उनका इलाज जारी शुरू किया गया।

छात्रा की मौत के मामले में कांग्रेस की सात सदस्यीय जांच दल गठित

बीजापुर के धनोरा स्थित माता रुकमणी आश्रम में की 35 छात्राओं की फूड पॉयजनिंग से तबियत बिगड़ने से इनमें से एक छात्रा की मौत हो गई। इस मामले में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने कांग्रेस की सात सदस्यीय जांच समिति का गठन किया है। जो जांच के बाद रिपोर्ट पीसीसी को सौपेगी। बीते दिनों माता रुकमणी आश्रम धनोरा में खाना खाने के बाद उल्टी दस्त व बुखार से 35 बच्चों की तबियत बिगड़ने से उन्हें जिला अस्पताल लाया गया। यहां बच्चो फूड पॉयजनिंग के लक्षण दिखने पर इलाज शुरू किया गया। इनमें एक बच्ची शिवानी तेलम की तबियत ज्यादा खराब होने से उसे आज सुबह जगदलपुर के लिए रेफर किया गया था। रास्ते में ही बच्ची की मौत हो गई। वहीं अब भी 4 बच्चों की तबियत ज्यादा खराब होने से उन्हें आईसीयू में रखा गया है।

इस मामले को गंभीरता से लेते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने बीजापुर विधायक विक्रम मंडावी के संयोजकत्व में सात सदयीय जांच समिति का गठन किया है। यह समिति प्रभावित आवासीय आश्रम का दौरा पीड़ित परिजन, अध्यनरत छात्राओं, आश्रम प्रशासन व ग्रामीणों से मिलकर चर्चा कर वस्तुस्थिति से अवगत होकर रिपोर्ट पीसीसी को सौपेगी। समिति में विधायक के अलावा जिला पंचायत अध्यक्ष शंकर कुड़ियम, लालू राठौर, नीना रावतिया, बोधी ताती, सोनू पोटाम व रमेश यालम शामिल हैं।

सतीशचंद्र वर्मा की अग्रिम जमानत याचिका पर हुई सुनवाई

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में मंगलवार को पूर्व महाधिवक्ता सतीशचंद्र वर्मा की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई हुई है। जस्टिस अग्रवाल के सिंगल बेंच ने सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। रायपुर के एसीबी कोर्ट में पूर्व महाधिवक्ता की अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो गई थी। एसीबी कोर्ट ने पूर्व महाधिवक्ता की अग्रिम जमानत याचिका को अत्यंत गंभीर मामला बताते हुए खारिज कर दिया था।

जिसके बाद एसीबी कोर्ट के फैसले को हाइकोर्ट में चुनौती दी गई है। पूर्व महाधिवक्ता ने यह याचिका वरिष्ठ अधिवक्ता किशोर भादुड़ी के माध्यम से लगाई है। देखना होगा कि पूर्व एजी को उच्च न्यायालय से राहत मिलती है या फिर निचली अदालत के फैसले को यथावत रखा जाएगा।

सालों से लंबित शासकीय भूमि पर अवैध कब्जे से ग्रामीण परेशान

सांकेतिक शव यात्रा निकालने से पहले जागा प्रशासन

महासमुंद। महासमुंद के ग्राम पंचायत खैरझिटी में आज आरक्षित शमशान घाट की भूमि पर अवैध कब्जे को हटाने ग्रामिणों ने कलेक्टोरेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। दरअसल, ग्रामिणों ने पुर्वजों के समय से शमशान घाट को आरक्षित किया हुआ है। लेकिन शासकीय भूमि पर बुधवंतिन, ईंद्रमन, छन्नुलाल, मन्नुलाल, जैलसिंग और शालोम मार्रिन हेमिटन पर अवैध कब्जा करने का आरोप है। जिससे अब गांव वालों को शव दफन करने में दिक्कतें हो रही है।

इस संबंध में पंचायत ने कई बार नोटिस भेजा। कोटवार ने नोटिस तामिल कराके वर्तमान उप राजस्व नायब तहसीलदार तुमगांव को कब्जा हटवाने के लिए आवेदन दिया। बावजूद आज तक कब्जा नहीं हटाया गया है।

मंगलवार को ग्रामिणों के सांकेतिक शव यात्रा निकालने की जानकारी प्रशासन को मिली, जिसके बाद एसडीओपी अजय शंकर त्रिपाठी और नायब तहसीलदार मोहित अमिना मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों को समझाइश दी, हालांकि ग्रामीण सांकेतिक शव यात्रा निकालने पर अड़े रहे।

नायब तहसीलदार ने कहा कि बुधवार को भूमि का सीमांकन किया जाएगा। अगर भूमि पर अवैध कब्जा पाया गया तो उसे हटाने की कार्रवाई की जाएगी। इस आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने शव न निकालकर पैदल रैली निकालकर कलेक्टोरेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा है।

जांजगीर-नैला गुड्स शेड को नई सुविधाओं के साथ विकसित किया जायेगा

बिलासपुर। मंडल के जांजगीर नैला रेलवे स्टेशन यार्ड में महत्वपूर्ण गुड्स शेड स्थित है। जहाँ से स्थानीय एवं बाहरी व्यापारियों द्वारा अपने माल को लोडिंग व अनलोडिंग कर बेहतर रूप से परिवहन कराया जाता है। रेल प्रशासन द्वारा इस गुड्स शेड के बुनियादी ढाँचे के विकास हेतु विभिन्न विकास कार्य निष्पादित किये जायेंगे, जिसमें नाली, डस्ट स्क्रीन, स्प्रिंकलर, अप्रोच रोड,आरसीसी ओवरहेड टेंक, फ्लोरिंग, हमालों व मजदूरों के आराम हेतु रूम, रेन बाथ, सोक पिट, पम्प हाउस एवं अन्य सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जायेगी। इन सभी अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित गुड्स शेड का निर्माण कार्य करवाया जाएगा। ये सभी प्रस्तावित विकास कार्य रेलवे द्वारा अनुमोदित डिजाइन के अनुसार किए जाएंगे तथा इनका निर्माण रेलवे के अनुमोदित मानकों और विनिर्देशों के अनुसार किया जाएगा। रेल प्रशासन द्वारा इन सभी प्रस्तावित विकास कार्यों हेतु

निविदा जारी कर दी गई है।

वरि.मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अनुराग कुमार सिंह ने बताया की गुड्स शेड के बुनियादी ढाँचे के विकास से न केवल माल परिवहन में तेजी आएगी, बल्कि क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। गुड्स शेड में आधुनिक सुविधाओं के विकास से स्थानीय व्यापारियों और उद्योगपतियों को भारी राहत मिलेगी, जो अपने माल के तेज और सुगम परिवहन के लिए इस गुड्स शेड पर निर्भर रहते हैं। इन सभी प्रस्तावित कार्यों के पूर्ण होने के बाद गुड्स शेड में हमारे मूल्यवान माल ग्राहकों को माल के लोडिंग व अनलोडिंग में आसानी होगी।

अग्निवीर भर्ती रैली में युवक की संदिग्ध मौत मामले को लेकर कांग्रेस आक्रामक

रायगढ़। रायगढ़ जिला मुख्यालय स्थित स्टेडियम में सेना की अग्निवीर भर्ती रैली में सोमवार रात एक युवक की संदिग्ध मौत हो गई। रायगढ़ स्टेडियम में 04 से 12 दिसंबर यहां आयोजन हो रहा है जिसमें प्रदेश के सभी जिलों से अभ्यर्थी यहां अलग-अलग दिनों में पहुंच रहे हैं। सोमवार रात एक अभ्यर्थी की मौत हो जाने के बाद मंगलवार को कांग्रेस ने इस पूरे मामले की जांच की मांग की है। साथ ही मृतक के परिजनों को 50 लाख मुआवजा तथा परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने पर जोर देते हुए यह भी कहा है कि अगर उनकी मांग नही मानी जाती तो वे सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेंगे।

मिली जानकारी के मुताबिक बोईरदादर स्टेडियम में जारी अग्निवीर भर्ती रैली के संबंध में, सेना के आयोजकों के माध्यम से प्राप्त प्राथमिक जानकारी अनुसार बीती रात मनोज कुमार साहू, पिता अनिल कुमार साहू, उम्र 20 वर्ष, निवासी ग्राम-खोरपा, जिला-रायपुर आर्मी भर्ती केन्द्र स्टेडियम रायगढ़ में प्रथम स्टेज 1600 मी. की दौड़ सफलता पूर्वक पूर्ण किया। प्रथम चरण पूर्ण करने के तत्काल पश्चात् अगले चरण में बायोमेट्रिक लगाने से पहले अचानक, मैदान में गिर गया। अभ्यर्थी को तत्काल स्टेडियम में मौजूद जिला स्वास्थ्य विभाग के मेडिकल टीम के द्वारा मौके पर ही जांच किया गया। जिसमें मौके पर मौजुद चिकित्सको द्वारा प्रारंभिक जांच पश्चात् पाया

गया कि अभ्यर्थी को सांस लेने में काफी दिक्कत हो रही थी।

अभ्यर्थी का ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल लगातार कम हो रहा था, जिसके कारण अभ्यर्थी सचेत परंतु डिसओरीयेंटेड पाया गया। उसे तत्काल मेडिकल ऑक्सीजन प्रदाय के साथ प्राथमिक चिकित्सा प्रदाय करते हुए एम्बुलेंस के माध्यम से जिला चिकित्सालय, रायगढ़ रिफर किया गया। जहां अभ्यर्थी बेहोश अवस्था में लाया गया जिसे इन्ट्यूबेट एवं स्टेबल करते हुए हायर सेंटर मेडिकल कॉलेज, रायगढ़ भेजा गया। जहाँ रायगढ़ मेडिकल कॉलेज के विशषज्ञो की टीम के द्वारा समुचित ईलाज किया गया। परंतु अभ्यर्थी की स्थिति अति गंभीर होने के कारण रात करीब 11:35 बजे उसकी मौत हो गई। परिजनो के कथनानुसार एवं चिकित्सको के जांच अनुसार यह पाया गया कि, अभ्यर्थी मनोज कुमाार साहू पूर्व से सिकलसेल बीमारी से ग्रसित था। मंगलवार सुबह परिजनो की उपस्थिति में मेडिकल कॉलेज के विशेषज्ञ चिकित्सको की टीम द्वारा पोस्टमार्टम किया गया, जिसके पश्चात् परिजन को शव सुपुर्द करके तहसीलदार एवं सीईओ जनपद के साथ गृह ग्राम खोरपा, तह-अभनपुर जिला रायपुर भेजा गया।

अग्निवीर भर्ती रैली में शामिल एक अभ्यर्थी की मौत हो जाने के बाद जिला प्रशासन ने अंतिम संस्कार हेतु आर्थिक सहयोग प्रदान किया गया। एवं मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान से भी 10 लाख रूपयें के आर्थिक सहयोग प्रदान किया जायेगा।

बीती रात रायगढ़ स्टेडियम में एक अभ्यर्थी की अचानक तबियत बिगड़ने और उसकी मौत हो जाने के बाद मंगलवार सुबह कांग्रेस नेता जिला कलेक्टर कार्यालय के सामने भारी नारेबाजी करते हुए कांग्रेसी नेताओं ने अग्निवीर भर्ती रैली में मनोज कुमार साहू की मौत पर नाराज होकर सड़को पर उतर गए हैं इनका आरोप है कि भर्ती रैली में अगर सही ढंग से चिकित्सा के इंतजाम रखे हुए होते तो यह मौत नही होती।

कांग्रेसियों का यह आरोप है कि भर्ती रैली में भाग लेने आये युवक की मौत दौड के दौरान हुई है और चुपचाप इस पूरे मामले को निपटाने का प्रयास पुलिस व प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। उनकी मांग है कि मृतक के परिवार के एक सदस्य की शासकीय नौकरी तथा 50 लाख का मुआवजा तत्काल प्रभाव से दिया जाए।

रामानुजगंज जल संसाधन विभाग में 9 करोड़ का गबन

■ तत्कालीन फरार एसडीओ गिरफ्तार

बलरामपुर/रामानुजगंज। रामानुजगंज पुलिस ने जल संसाधन विभाग में शासकीय पैसों के गबन के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने फरार चल रहे मुख्य आरोपी तत्कालीन एसडीओ को सोमवार को गिरफ्तार किया है। साल 2022 में तत्कालीन एसडीओ ने लगभग 9 करोड़ रुपये का गबन किया था।

रामानुजगंज पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक जल संसाधन विभाग के आरोपी तत्कालीन एसडीओ संजय ग्रायकर ने एक संगठित गिरोह बनाया। इसमें उनके कार्यालय के अन्य सहकर्मियों के साथ अपने पद के प्रभाव का दुरुपयोग करते हुए मार्च 2022 से मई 2022 तक भू-अर्जन की शासकीय राशि को निजी व्यक्तियों के खाते में गैर वित्तीय रूप से समायोजन किया गया था।

पुलिस ने इस मामले में मार्च 2023 में धारा 420 467 468 471 409 और 120 (बी) के तहत रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर की। विभिन्न विभागों से प्राप्त दस्तावेज और फर्मों से प्राप्त जानकारी के आधार पर जांच शुरू की गई। जिसके बाद मुख्य आरोपी संजय ग्रायकर फरार हो गया। आरोपी एसडीओ अलग-अलग जगहों पर छिपकर रह रहा था। आरोपी की खोजबीन करने पुलिस पतासाजी कर रही थी।

रामानुजगंज पुलिस टीम को मुखबिर के जरिए सूचना मिली कि करोड़ों रुपए के गबन का आरोपी संजय ग्रायकर रायगढ़ में छिपकर रह रहा है। जिसके बाद रामानुजगंज पुलिस टीम रायगढ़ पहुंची और आरोपी एसडीओ को गिरफ्तार किया।

एसडीओपी याकूब मेमन ने कहा साल 2022-23 में रामानुजगंज जल संसाधन विभाग के तत्कालीन एसडीओ संजय ग्रायकर और अन्य आरोपियों ने कूट रचित दस्तावेज के जरिए शासकीय पैसों का गबन किया। मुख्य आरोपी एसडीओ घटना के बाद से ही फरार चल रहा था। जिसे रायगढ़ से गिरफ्तार किया गया है। विवेचना जारी है।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

नक्सली बंद के दौरान वाहन में लगाई आग, चालक फरार

जगदलपुर। बीजापुर और तेलंगाना सीमा से लगे गांव में नक्सलियों के द्वारा बंद के दौरान एक वाहन में आग लगा दिया गया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुँची, लेकिन मौके पर ड्राइवर नहीं मिला है। मामले के बारे में बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले बीजापुर और तेलंगाना सीमा से सटे इलाके में पुलिस और नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ हो गया। इस घटना में पुलिस ने सात नक्सलियों को मार गिराया था। घटना के बाद नक्सलियों ने अपने साथियों के मौत के बाद 9 दिसंबर को बंद का आव्हान किया था, जिसके चलते 9 दिसंबर को नक्सलियों ने इलाके से गुजर रहे कार को रोककर उसे आग के हवाले कर दिया। घटना की जानकारी लगते ही चितुर पुलिस मौके पर आ पहुंची। पुलिस ने इस मामले में कार चालक को देखा, लेकिन वह घटनास्थल में दिखाई नही दिया। पुलिस इस मामले को लेकर जांच करने की बात कह रही है।

कलेक्टर ने विकास कार्यों के अद्यतन स्थिति की समीक्षा की

मोहला। कलेक्टर श्रीमती तुलिका प्रजापति ने गत दिवस मानपुर के सामुदायिक मंगल भवन में ग्राम पंचायतों में चल रहे एलडब्ल्यूई सैचुरेशन सर्वे के संबंध में समस्त सर्वेयर एवं नोडल अधिकारियों की बैठक ली। कलेक्टर ने सर्वेक्षण का कार्य 15 दिसंबर तक पूर्ण करने निर्देशित किया। सर्वेक्षण के दौरान निर्धारित विभिन्न योजनाओं को आमजनो तक आसान पहुंच बनाने निर्देशित किया। उन्होंने योजनाओं के क्रियान्वयन में आ रही समस्या को सूचीबद्ध करने निर्देशित किया गया। जिससे इन बाधाओं को दूर कर हितग्राहियों को लाभान्वित किया जा सके। जिससे सैचुरेशन की स्थिति प्राप्त किया जा सके। सभी तरह की ऑनलाइन एंट्री का कार्य समय सीमा में पूर्ण करने निर्देशित किया गया। सर्वे टीम से चर्चा के समय जिनका सर्वे पूर्ण नहीं हुआ है, उन्हें पूर्ण करने निर्देशित किया। बैठक में परियोजना निदेशक श्री हेमंत ठाकुर, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मानपुर श्री अमित नाथ योगी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत मानपुर श्री मोहम्मद हनीश एवं समस्त सर्वेयर उपस्थित रहे।

सहायक शिक्षक दहेज प्रताड़ना के आरोप में गिरफ्तार

खैरागढ़। ठेलकाडीह पुलिस ने मोहारा प्राइमरी स्कूल का सहायक शिक्षक लोमस वर्मा ने शादीशुदा होने के बावजूद एक सरकारी स्कूल की शिक्षिका से शादी करने के बावजूद नवविवाहिता को दहेज के लिए प्रताड़ित करने के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। मोहारा प्राइमरी स्कूल में सहायक शिक्षक के पद पर कार्यरत लोमस वर्मा पर शादीशुदा होने के बावजूद दूसरी शादी करने व नवविवाहिता पत्नी को दहेज के लिए प्रताडित करने की ठेलकाडीह थाना में शिकायत हुई थी। पुलिस ने जांच के पश्चात शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया है। शिक्षिका पत्नी का आरोप है कि सहायक शिक्षक वर्मा 2020 में एक अन्य लडकी से विवाह कर चुके थे। अप्रैल 2024 में उन्होंने दोबारा शादी की। शादीशुदा होने की जानकारी को आरोपी द्वारा छुपाया गया। जिसकी जानकारी हाल ही में सामने आई है। वहीं दूसरी शादी करने के बाद पत्नी को लगातार आरोपी अलग-अलग शारीरिक कारणों का हवाला देकर अपने से दूर रखता था।

सूर्या मॉल के मैनेजर पर बाप-बेटों ने जमकर मारपीट की

दुर्ग। भिलाई के स्मृति नगर स्थित टीआई सूर्या मॉल के मैनेजर की मॉल के ही दुकान संचालक और उसके पिता, भाई ने मिलकर पिटाई कर दी। तीनों ने मैनेजर को लात घूंसों और चप्पल से बुरी तरह मारा। मैनेजर की शिकायत पर स्मृति नगर चौकी पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों को हिरासत में लिया है। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। स्मृति चौकी प्रभारी गुरविंदर संधू ने बताया कि विनोद सिंह (43 वर्ष) ने मारपीट की शिकायत दर्ज कराई है। वो सूर्या मॉल में मैनेजर के पद पर कार्यरत है। शनिवार को जब वो अपनी ड्युटी पर मॉल का निरीक्षण कर रहे थे तो उसी दौरान उनके ऊपर वहां स्थित रंगोली बैंगल्स दुकान के संचालक प्रशांत गुप्ता ने हमला कर दिया। उन्होंने बताया कि वो मॉल के फर्स्ट फ्लोर का सुबह करीब 11.30 बजे निरीक्षण कर रहे थे। वो वहां स्थित रंगोली बैंगल्स दुकान के पास जैसे ही पहुंचे दुकान संचालक प्रशांत गुप्ता उन्हें मारने दौड़ा।

रायपुर से जगदलपुर जा रही बस पलटी, 3 लोग घायल

धमतरी। नेशनल हाईवे 30 पर सड़क हादसों का सिलसिला जारी है। आज रायपुर से जगदलपुर जा रही महिंद्रा ट्रेवल्स की बस पलट गई। इस हादसे में तीन यात्री घायल हो गए, जबकि अन्य यात्री सुरक्षित बताए जा रहे हैं। बस पलटते ही यात्रियों में हड़कंप मच गया। यह घटना बालोद जिले के बालोदगहन के पास हुई है। जानकारी के अनुसार, बस (सीजी 07 ई 1484) रायपुर से जगदलपुर की ओर जा रही थी। इस दौरान बालोदगहन के पास ढाबे के आगे बाइक को बचाने की कोशिश करते हुए सड़क से फिसलकर पेड़ से टकरा गई और पलट गई। इस हादसे में तीन यात्री घायल हो गए, जबकि अन्य यात्री सुरक्षित बताए जा रहे हैं। हादसे की सूचना मिलते ही पुरूर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को उपचार के लिए धमतरी भेजा गया है। थाना प्रभारी शिशुपाल सिन्हा ने बताया कि दुर्घटना में तीन यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिन्हें रक्तदान एंबुलेंस के माध्यम से धमतरी अस्पताल भेजा गया। बाकी यात्री सुरक्षित रहे, उन्हें दूसरी बस से आगे की यात्रा के लिए भेज दिया गया।

नौकरी लगाने के नाम पर लाखों ठगे, भाई-बहन को पकड़ा

कोरबा। नौकरी लगाने के नाम पर लोगों से ठगी करने वाले भाई-बहन को दीपका पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दोनों ने कोर्ट में बाबू का नौकरी दिलाने के नाम पर दो लोगों से साढ़े चार लाख की ठगी की थी। प्रार्थी के शिकायत के बाद दीपका पुलिस ने कड़ी कार्यवाही करते हुए दोनों भाई बहन को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़ी गई युवती खुद को वकील बताती थी। अधिकारियों और नेताओं से ऊंची पहुंच का धौंस जमाकर लोगों से ठगी करती थी।

दीपका थाना प्रभारी प्रेम चंद साहू ने बताया कि 7 दिसंबर को प्रार्थी संजय दास द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया गया था कि आरोपीया

सुमन सिंह द्वारा अपने भाई जय सिंह के साथ मिलकर प्रार्थी और उसके दोस्त का सरकारी नौकरी लगाने के नाम पर धोखाधड़ी कर 4 लाख 50 हज़ार रुपए वसूल लिए हैं। उक्त रिपोर्ट पर थाना दीपका में अपराध क्रमांक 415/2024 धारा 420,34 भा द वि पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। मामले में आरोपियों की तलाश की जा रही थी। दोनों आरोपियों को जांजगीर चांपा और बिलासपुर से गिरफ़्तार कर किया गया है। दोनों आरोपी रिश्ते में भाई बहन लगते हैं। जय सिंह और सुमन सिंह दोनों जांजगीर के रहने वाले हैं। भाई-बहन ने इनके अलावा कई लोगो को ठगी का शिकार बनाया है।

पीड़ित की माने तो उसकी मुलाकात युवती से रायपुर में हुआ इस दौरान उसने कहा कि कोर्ट में बाबू का पद खाली है उस पर सरकारी नौकरी लगा सकता हु और उसने झांसे में लेकर ठगी की जब नौकरी नही लगी तब उसने पैसे वापस भी मांगे लेकिन देने को तैयार नही थी उसने भाई को भी अपने साथ रखा था दोनो ने ठगी की है। बताया जा रहा है कि भाई बहन ने और भी कई लोगो से ठगी की है पुलिस इस बारे में जानकारी एकत्रित कर रही है। फिलहाल, पुलिस ने दोनों भाई बहन को गिरफ्तार कर लिया है और मामले में आगे जांच की जा रही है।

विस अध्यक्ष रमन की पहल से राजनांदगाँव विस को मिली विकास कार्यों को मंजूरी

■ सिंह ने मुख्यमंत्री साय व राजस्व मंत्री वर्मा का जताया आभार

राजनांदगांव। विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को साकार करते हुए विधानसभा अध्यक्ष व राजनांदगांव विधायक डॉ. रमन सिंह के अथक प्रयासों से राजनांदगाँव के विकास के लिए राज्य शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में अधोसंरचना विकास एवं पर्यावरण निधि से कुल 8 करोड़ 60 लाख 10 हजार रुपए की लागत के 113 विकास कार्यों को प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है।

इन कार्यों में राजनांदगांव के शहरी क्षेत्रों/वार्डों के अंतर्गत विभिन्न क्षत्रों में सीसी रोड निर्माण, नाली निर्माण, शेड निर्माण, गार्डन सौंदर्यीकरण और जिम सामग्री के लिए 5 करोड़ 63 लाख 80 हजार रुपए की राशि

स्वीकृत दी गई है। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायतों में सीसी रोड, छत निर्माण, सांस्कृतिक मंच और नाली निर्माण जैसे कार्यों के लिए 2 करोड़ 63 लाख 30 हजार रुपए तथा अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में भवन निर्माण, सामुदायिक भवन, मंच और अन्य निर्माण कार्यों के लिए 33 लाख रुपए राशि की स्वीकृति प्रदान की गई है।

शासन के इस निर्णय पर राजनांदगांव विधायक व विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री टंकराम वर्मा का आभार और धन्यवाद व्यक्त करते हुए कहा कि इन विकास कार्यों से न केवल राजनांदगांव के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत संरचना को मजबूती मिलेगी, बल्कि यहां के निवासियों की जीवनशैली में भी सकारात्मक बदलाव आएगा। इसके साथ ही राजनांदगांव के नागरिकों ने इन विकास कार्यों की स्वीकृति पर विधायक एवं विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह जी का आभार व्यक्त किया और उनकी विकास के प्रति प्रतिबद्धता की सराहना की।

केन्द्रीय राज्यमंत्री साहू ने मंत्री उरांव से मुलाकात कर रखी अपनी मांगे

आदिवासी समुदायों के लिए शैक्षिक बुनियादी ढांचे में सुधार के उद्देश्य से कई प्रमुख पहलों पर हुई चर्चा

नई दिल्ली-रायपुर। केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के राज्य मंत्री श्री तोखन साहू ने मंगलवार को नई दिल्ली में छत्तीसगढ़ में आदिवासी समुदायों के लिए शैक्षिक बुनियादी ढांचे में सुधार के उद्देश्य से कई प्रमुख पहलों पर चर्चा करने के लिए केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री श्री जुएल उरांव से मुलाकात की। चर्चा में अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्र बेलगहना में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय के निर्माण के साथ-साथ मुंगेली के लोरमी में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में बहुत जरूरी विकास और आदिवासी छात्रों की उच्च शिक्षा के लिए मुंगेली में पोस्ट-मैट्रिक छात्रावास खोलने पर ध्यान केंद्रित किया गया।

श्री साहू ने बिलासपुर जिला मुख्यालय से लगभग 60 किलोमीटर दूर स्थित बेलगहना में प्रस्तावित एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय के निर्माण के बारे में जानकारी दी। इस क्षेत्र में मुख्य रूप से अनुसूचित जनजातियाँ निवास करती हैं, और इस विद्यालय की

स्थापना से यह सुनिश्चित होगा कि क्षेत्र के छात्र, विशेष रूप से विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के छात्र, उच्च-गुणवत्ता वाली शिक्षा प्राप्त कर सकें। श्री साहू ने इस बात पर जोर दिया कि विद्यालय के निर्माण के लिए पर्याप्त भूमि उपलब्ध है, और उन्होंने आशा व्यक्त की कि नया संस्थान क्षेत्र के आदिवासी छात्रों के भविष्य को आकार देने में मदद करेगा।

बेलगहना परियोजना के अलावा, श्री साहू ने मुंगेली के लोरमी में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय की तत्काल आवश्यकताओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने आदिवासी मंत्री को विद्यालय की चल रही आवश्यकताओं के बारे में बताया, जिसमें एक ओवरहेड सीमेंट कंक्रीट जल भंडारण टैंक, 35 कंप्यूटरों के साथ एक कंप्यूटर लैब, एक जनरेटर (डीजी सेट), भाषा और कला शिक्षा के लिए समर्पित कमरे, और विज्ञान और भूगोल प्रयोगशालाएँ जैसी आवश्यक सुविधाओं का निर्माण शामिल है। इसके अलावा, श्री साहू ने अनुरोध किया कि जनजातीय मामलों का मंत्रालय संबंधित अधिकारियों को भारत के संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के तहत इन जरूरतों को पूरा करने का निर्देश दे ताकि विद्यालय का कुशल संचालन सुनिश्चित हो सके।

श्री साहू ने मुंगेली में पोस्ट-मैट्रिक छात्रावास की अनुपस्थिति का मुद्दा भी उठाया, जो पिछले 40 वर्षों से लंबित है। परिणामस्वरूप, क्षेत्र के कई आदिवासी छात्र उच्च शिक्षा के अवसरों से वंचित हो रहे हैं। राज्य भर में ऐसी सुविधाओं की महत्वपूर्ण आवश्यकता को पहचानते हुए, श्री साहू ने आदिवासी मंत्री से छत्तीसगढ़ में विशेष रूप से मुंगेली में लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रावासों की स्थापना को प्राथमिकता देने का आग्रह किया, ताकि आदिवासी छात्रों को आगे की शिक्षा प्राप्त करने में सहायता मिल सके।

केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री श्री जुएल उरांव ने इन पहलों के लिए अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त किया और श्री साहू को आश्वासन दिया कि संबंधित अधिकारी इन परियोजनाओं पर तुरंत काम करेंगे। श्री साहू ने आदिवासी समुदायों को शिक्षा और बुनियादी ढाँचा प्रदान करने के महत्व को स्वीकार करने के लिए आदिवासी मंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया और इन महत्वपूर्ण परियोजनाओं के त्वरित कार्यान्वयन के लिए आवश्यक कदम उठाने की प्रतिबद्धता जताई।

संक्षिप्त समाचार

मुख्यमंत्री आज पखांजूर आएंगे, विकास कार्यों का करेंगे लोकार्पण व शिलान्यास

कांकेर। प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय बुधवार 11 दिसम्बर को कांकेर जिले के पखांजूर में आयोजित सुशासन का एक साल कार्यक्रम में शामिल होकर विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास करेंगे। प्राप्त जानकारी के अनुसार उक्त कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री साय पखांजूर स्थित नेताजी सुभाषचन्द्र बोस स्टेडियम में दोपहर 01 बजे शिरकत करेंगे। उक्त कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के तौर पर उप मुख्यमंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री श्री अरूण साव, कांकेर लोकसभा क्षेत्र के सांसद श्री भोजराज नाग, विधायक अंतागढ़ श्री विक्रम उसेण्डी, कांकेर विधायक श्री आशाराम नेताम, भानुप्रतापपुर श्रीमती सावित्री मनोज मण्डावी मौजूद रहेंगी। साथ ही जिला पंचायत अध्यक्ष श्री हेमन्त ध्रुव, जनपद पंचायत कोयलीबेड़ा की अध्यक्ष श्रीमती देवली नुरूटी, नगर पंचायत पखांजूर की अध्यक्ष श्रीमती मोनिका साहा सहित जिला पंचायत, जनपद पंचायत, नगरीय निकाय के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्य भी उक्त कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे।

आईपीएस जीपी सिंह की बहाली का रास्ता साफ, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका

रायपुर। आईपीएस जीपी सिंह की बहाली का रास्ता साफ हो गया है। कैट के आदेश को चुनौती देने वाली केंद्र सरकार की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब जीपी सिंह को बहाल करना केंद्र सरकार की मजबूरी है। बता दें कि आय से अधिक सपंत्ति और राजद्रोह के आरोपों में गिरफ्तारी के बाद केंद्र सरकार ने 21 जुलाई 2023 को जीपी सिंह को अनिवार्य सेवानिवृत्ति देते हुए सेवा से बाहर कर दिया था। जीपी सिंह ने केंद्र सरकार के फैसले को कोर्ट में चुनौती दी थी।

राज्यपाल से उत्तरप्रदेश के समाज कल्याण राज्य मंत्री गोंड ने सौजन्य भेंट की

रायपुर। राज्यपाल श्री रमेन डेका से राजभवन में उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति, जनजाति कल्याण विभाग एवं समाज कल्याण राज्य मंत्री श्री संजीव कुमार गोंड ने सौजन्य भेंट की। श्री गोंड ने उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्य नाथ की ओर से राज्यपाल श्री डेका को प्रयागराज में आयोजित महाकुम्भ 2025 के लिए न्यौता दिया।

मच्छरों के बढ़ते प्रकोप को लेकर कांग्रेसियों ने घेरा जोन 5 कार्यालय

रायपुर। मंगलवार को आम जनता की समस्याओं को लेकर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के सचिव प्रदीप देवांगन के नेतृत्व में कांग्रेसजनों के साथ ही आम नागरिकों ने टैक्स वसूली, मच्छरों के बढ़ते प्रकोप, आवारा कुत्तों के आतंक, मवेशियों के कारण हो रही दुर्घटनाओं, लाइट, पानी, बिजली जैसी समस्याओं को लेकर जोन क्रमांक 5 कार्यालय का घेरा करते हुए इन समस्याओं को जल्द से जल्द करने की मांग को लेकर जोन अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपा।

निलंबित आईएएस रानू साहू और माया वारियर को कोर्ट से नहीं मिली राहत

रायपुर। छत्तीसगढ़ के चर्चित डीएमएफ घोटाला मामले में आज निलंबित आईएएस रानू साहू और माया वारियर को कोर्ट में पेश किया गया। दोनों आरोपियों को ईडी की विशेष कोर्ट में पेश किया गया। एक बार फिर रानू साहू और माया वारियर की मुश्किलें बढ़ गई है। कोर्ट ने दोनों की न्यायिक रिमांड बढ़ा दी है। 17 दिसंबर तक दोनों की न्यायिक रिमांड बढ़ गई है। वहीं निलंबित आईएएस रानू साहू के कथित सहयोगी मनोज द्विवेदी को भी आज कोर्ट में पेश किया गया। मनोज द्विवेदी पर रानू साहू के साथ मिलकर एनजीओ के माध्यम से डीएमएफ के करोड़ों रुपए गबन का आरोप है। बता दें कि रानू साहू जून 2021 से जून 2022 तक कोरबा में कलेक्टर थीं। इसके बाद फरवरी 2023 तक वह रायगढ़ की भी कलेक्टर रहीं। इस दौरान माया वारियर भी कोरबा में पदस्थ थीं। कलेक्टर रानू साहू से करीबी संबंध होने के कारण कोयला घोटाले को लेकर माया वारियर के दफ्तर और घर में ईडी ने छापा मारा था। डीएमएफ की बड़ी राशि आदिवासी विकास विभाग को प्रदान की गई थी, जिसमें घोटाले का आरोप है। इसका प्रमाण मिलने के बाद ईडी ने माया वारियर को भी गिरफ्तार किया गया है।

साय कैबिनेट की बैठक आज, कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा

रायपुर। साय सरकार की कैबिनेट बैठक 11 दिसंबर को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में होगी। बैठक सुबह 11 बजे से महानदी भवन मंत्रालय में आयोजित होगी, जिसमें कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जाएगी।

चरगढ़ जलाशय परियोजना के कार्य के लिए 4.61 करोड़ स्वीकृत

रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन ने राज्य के बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के अंतर्गत राजपुर की चरगढ़ मध्यम जलाशय परियोजना के सर्वेक्षण कार्य के लिए 4 करोड़ 61 लाख 76 हजार रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। जल संसाधन विभाग मंत्रालय महानदी भवन ने परियोजना का सर्वे कार्य कराने के लिए मुख्य अभियंता हसदेव गंगा कछार जल संसाधन विभाग को प्रशासकीय स्वीकृति जारी की है।

सेन्टम ठेका कंपनी की मनमानी से शिक्षकों को नहीं मिल रही सैलरी

शिक्षा विभाग से कर रहे कार्रवाई की मांग

रायपुर। छत्तीसगढ़ में सेन्टम ठेका कंपनी द्वारा नियमों और एमओयू की अनदेखी करने की शिकायतें तेज हो गई हैं। पिछले तीन महीनों से कंपनी ने व्यवसायिक शिक्षकों को सैलरी नहीं दी है, जिससे वे मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं और उधारी में कर्ज लेने को मजबूर हैं। शिक्षकों का कहना है कि घर का किराया, बच्चों की स्कूल फीस, दवाइयां और रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना उनके लिए मुश्किल हो गया है। सैलरी न मिलने से परेशान शिक्षक राज्य के समग्र शिक्षा विभाग में शिकायत करने पहुंचे हैं और कंपनी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।

शिक्षकों ने अपनी समस्याएं बताते हुए कहा कि हर साल एक महीने की सैलरी दी जाती है और फिर चार-पांच महीने तक भुगतान लंबित रहता है। उन्होंने सेन्टम कंपनी से सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के वेतन की मांग की है, जो अभी तक नहीं मिला है। इसके साथ ही, पूर्व में एम पॉवर प्रगति दिल्ली की कंपनी द्वारा तीन माह का बोनस और औद्योगिक भ्रमण का पैसा लेकर भाग जाने का भी आरोप लगाया गया, जिसके लिए उन्होंने कार्रवाई की अपील की है।

शिक्षकों का कहना है कि वेतन न मिलने के कारण गेस्ट लेक्चरर और औद्योगिक भ्रमण आयोजित करना भी असंभव हो गया है। साथ ही, सेन्टम कंपनी द्वारा बिना पूर्व सूचना के उन्हें अपग्रेड कंपनी में मर्ज कर दिया गया है, जिससे उनके भविष्य को लेकर चिंता और बढ़ गई है। शिक्षकों ने सवाल उठाया कि इस कंपनी पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई है और अधिकारियों को कटघरे में खड़ा किया है।

वहीं, सेन्टम ठेका कंपनी के स्टेट कोआर्डिनेटर इद्रिस अंसारी का कहना है कि शिक्षकों को कुछ ही दिनों में भुगतान कर दिया जाएगा और रिम्बर्समेंट की प्रक्रिया के बाद उनका बकाया चुकता किया जाएगा।

शहर कांग्रेस कमेटी ने 10 जोन मुख्यालयों का किया घेराव

जनता की समस्याओं को लेकर सौंपा ज्ञापन

रायपुर। मंगलवार को शहर कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में राजधानी के सभी 10 जोन मुख्यालयों का घेराव किया गया। नगर निगम से संबंधित आ रही समस्याओं के निराकरण के लिए ज्ञापन सौंपा गया।

ज्ञापन में मांग की गई कि आवास सर्वे में धरसा, अस्थाई पट्टा, नहरपार, तालाबपार के निवासियों को लाभ मिलेगा की नहीं, बड़े कॉम्पलेक्स, बड़े मकान के टैक्स छोड़कर गरीब और मध्यम वर्ग पर गलत टैक्स लगाने और दबाव बनाने जैसी समस्या, गौठान एवं गोबर खरीदी बंद करने से सैंकड़ों गाय मरने की रिपोर्ट, भाजपा के नेताओं द्वारा अवैध निर्माण, अवैध प्लाटिंग को बचाने की बात, पार्षदनिधि की समस्त वार्डों में पिछले साल से भाजपा सरकार बनने के बाद भी अभी तक राशि ना दे पाने का विरोध, भूमिपूजन की ड्रामेबाजी करने बाद अभी तक अधिकांश काम सभी वार्डों में प्रारंभ नहीं करने और भाजपा नेताओं के ठेकों में बंदरबांट होने का विरोध, विधायकों एवं सांसद द्वारा नगर निगम के रोजाना कार्यों में अनावश्यक हस्तक्षेप करने का विरोध, भाजपा सरकार के बनने के बाद बढ़ते अवैध निर्माण पर नियंत्रण ना कर पाने का विरोध कर कांग्रेस पार्टी ने सभी जोन मुख्यालयों में जाकर ज्ञापन सौंपा।

आज के इस विरोध प्रदर्शन में पूर्व विधायक विकास उपाध्याय के साथ शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गिरिश दुबे भी शामिल हुए।

नगर निगम के खिलाफ भाजपा ने खोला मोर्चा

पानी की मांग को लेकर बीजेपी पार्षद दल ने रायपुर नगर निगम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे के नेतृत्व में वार्ड 44 की महिलाओं ने मटकी लेकर चक्काजाम किया और महापौर एजाज ढेबर हाए-हाए के नारे लगाए। भाजपा पार्षदों ने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्षदों के वार्डों में पानी की सप्लाई की जा रही है। कई क्षेत्रों में लोगों को पानी नहीं मिल रहा। भाजपा पार्षदों का कहना है कि 500 मीटर के अंदर पानी टंकी होने के बाद भी लोगों को पानी नहीं मिल रहा। अमृत मिशन की पाइपलाइन बिछने के बाद पानी की सप्लाई प्रभावित होने का आरोप भी लगाया।

सीएम साय ने बलिदान दिवस पर प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को किया नमन

कहा- वीर नारायण सिंह छत्तीसगढ़ महतारी के सच्चे सपूत थे

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अमर शहीद वीरनारायण सिंह के बलिदान दिवस पर राजधानी रायपुर के जयस्तंभ चौक पहुंच कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने शहीद वीर नारायण सिंह की प्रतिमा पर मल्यार्पण कर उन्हें नमन किया।

उप मुख्यमंत्री अरुण साव, आदिमजाति विकास मंत्री रामविचार नेताम, वन मंत्री केदार कश्यप, विधायक पुरन्दर मिश्रा सहित अनेक जनप्रतिनिधिगण इस अवसर पर उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री साय ने शहीद वीर नारायण सिंह के मातृभूमि के प्रति योगदान को याद करते हुए कहा कि स्वतंत्रता के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर देने वाले आदिवासी जन-नायक वीर नारायण सिंह छत्तीसगढ़ महतारी के सच्चे सपूत थे। वे सोनाखान के ज़मींदार परिवार से थे लेकिन उन्होंने आदिवासियों, किसानों और गरीबों के लिए लड़ाई लड़ी। उन्होंने सन् 1856 के भीषण अकाल के दौरान गरीबों को भूख से बचाने के लिए अनाज गोदाम से अनाज निकालकर गरीबों में बांट दिए। उन्होंने सन् 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ की जनता में देश भक्ति का संचार किया। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि शहीद वीर नारायण सिंह के संघर्ष, मातृभूमि के प्रति समर्पण और बलिदान को हमेशा याद किया जाएगा। गरीबों और किसानों के रक्षक के रूप में उनकी गौरवगाथा सदैव अमर रहेगी।

भाजपा सरकार के एक साल पूरे होने पर भूपेश बघेल ने कसा तंज

■ **कहा- रिपोर्ट कार्ड में दो चीज होगी, एक 3100 में धान खरीदी, जो किसानों को नहीं मिल रहा, दूसरा महतारी वंदन, जिससे कई महिलाएं वंचित**

रायपुर। 13 दिसंबर को भाजपा जनता के समक्ष अपने एक साल का रिपोर्ट कार्ड रखने जा रही है। इस पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तंज कसा है। उन्होंने कहा, केवल दो ही चीज भाजपा की रिपोर्ट कार्ड में होगी। पहले 3100 सौ धान खरीदी का मूल्य देने की, जिसमें अव्यवस्थाएं हैं। दूसरा महतारी वंदन, जिसकी राशि कई महिलाओं को नहीं पहुंच रही है। नवविवाहित महिलाएं इस योजना से जुड़ नहीं पा रही है। इनका पोर्टल एक बार बंद हो जाता है तो दोबारा नहीं खुलता।

ममता बेनर्जी को इंडिया गठबंधन की कमान सौंप देना चाहिए, लालू यादव के इस बयान पर भूपेश बघेल ने कहा, यह पार्टी के बड़े स्तर के लोगों की बातें है। वह

सब तय करते हैं। मैं इस पर कुछ बोलने के लिए आथराइज व्यक्ति नहीं हूं। प्रदेश में हो रही धान खरीदी को लेकर पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा, मैं खुद किसान हूं। किसान मजदूर महंगाई से परेशान हैं। किसानों को खाद लेने, धान बेचने में भी परेशानी हो रही है। प्रदेश में पहली बार उद्योगपतियों को धरना देना पड़ा। इससे समझा जा सकता है। निकाय, पंचायत चुनाव के आरक्षण पर भूपेश बघेल ने कहा, 50% आरक्षण देने की बात पोस्टर में लिखी गई है। पोस्टर में 50% आरक्षण के लिए सीएम का आभार है। छत्तीसगढ़ में एसटी, एससी को मिलाकर 45% आरक्षण है। अगर ओबीसी को 50% दें तो 95% आरक्षण हो जाएगा, सरकार बताए क्या इस तरीके से कोई अध्यादेश जारी हुआ है। हम लोगों ने जो प्रस्ताव पारित करने भेजा था वह 76% था, 95% कब सरकार ने कर दी, इसका होर्डिंग लगातार देख रहे हैं।

सीएम योगी ने मुख्यमंत्री साय को भेजा महाकुंभ का आमंत्रण

छत्तीसगढ़ के श्रद्धालुओं के लिए लगाया जाएगा विशेष पंडाल

रायपुर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय को प्रयागराज के पवित्र संगम में वर्ष 2025 में आयोजित हो रहे महाकुंभ में शामिल होने का आमंत्रण भेजा है। उन्होंने सभी छत्तीसगढ़ वासियों को भी महाकुंभ में आमंत्रित किया है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की ओर से उनका आमंत्रण लेकर उत्तर प्रदेश के आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री सुनील कुमार शर्मा और समाज कल्याण राज्य मंत्री संजय गोंड ने मुख्यमंत्री साय से सौजन्य मुलाकात की और उन्हें आमंत्रण पत्र, पवित्र गंगा जल और कुंभ का प्रतीक चिन्ह सौंप कर उन्हें महाकुंभ में आमंत्रित किया। मंत्री सुनील कुमार शर्मा ने मुख्यमंत्री से यह भी आग्रह किया कि कुंभ स्थल पर छत्तीसगढ़ का

भी एक पंडाल लगाया जाए।

मुख्यमंत्री साय ने छत्तीसगढ़ के पंडाल के लिए स्थान उपलब्ध कराने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम एक पत्र मंत्रीद्वय को सौंपा। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि पंडाल में छत्तीसगढ़ से कुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं के ठहरने और भोजन की व्यवस्था रहेगी। मुख्यमंत्री साय ने मंत्री द्वय का छत्तीसगढ़ में आत्मीय स्वागत करते हुए आमंत्रण के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के प्रति आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा कि महाकुंभ में शामिल होना सौभाग्य का विषय है। वे पहले भी कुंभ में शामिल होते रहे हैं, लेकिन इस बार का कुंभ विशेष है। आमंत्रण देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दो-दो मंत्रियों को भेजा है। हम महाकुंभ में जरूर आएंगे।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि मैंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से अनुरोध किया है कि छत्तीसगढ़ प्रयागराज महाकुंभ 2025 के अवसर पर महाकुंभ में आने वाले देश-विदेश के श्रद्धालुओं को इस प्रदेश की संस्कृति, विकास और उपलब्धियों से परिचित कराने के लिए उत्सुक है। छत्तीसगढ़ से महाकुंभ के दर्शन के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं के भोजन एवं रहने-ठहरने की व्यवस्था हेतु महाकुंभ क्षेत्र में छत्तीसगढ़ के लिए भूमि आरक्षित करने का अनुरोध भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से किया है।

उपमुख्यमंत्री साव के प्रयासों से लोरमी क्षेत्र को मिला विकास कार्यों की सौगात

■ **छत्तीसगढ़ में सुशासन और विकास के नए आयाम**

रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य में विकास और सुशासन के नए आयाम गढ़े जा रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व और उप मुख्यमंत्री एवं लोरमी विधायक अरुण साव के विशेष प्रयासों से सरकार ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए बड़े कदम उठा रही है। हाल ही में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के प्रस्तावों पर मुहर लगाते हुए 253 नए विकास कार्यों के लिए 1823.85 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। यह राशि ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने और स्थानीय जरूरतों को पूरा करने के लिए खर्च की जाएगी। इन कार्यों के तहत सीसी सड़क निर्माण, सामुदायिक भवन, पुलिया निर्माण, मुक्तिधाम निर्माण, प्रतीक्षालय शेड

निर्माण, सिंचाई कूप निर्माण, आंगनवाड़ी भवन निर्माण, रंगमंच निर्माण, नाली निर्माण और मरम्मत एवं उन्नयन कार्यों को प्राथमिकता दी गई है।

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने इन परियोजनाओं को ग्रामीण क्षेत्रों में जीवनस्तर सुधारने और बुनियादी सुविधाओं को सुदृढ़ करने का माध्यम बताया है। इन प्रयासों से न केवल ग्रामीण जनता को लाभ मिलेगा, बल्कि राज्य के सामाजिक और आर्थिक विकास को भी मजबूती मिलेगी।

लोरमी क्षेत्र में स्वास्थ्य, सड़क और बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए विशेष ध्यान दिया गया है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एवं एमसीएच अस्पताल की मरम्मत और उन्नयन के लिए 20 लाख की स्वीकृति दी गई है। इसी प्रकार, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लालपुर के लिए 10 लाख और उप-स्वास्थ्य केंद्र डोंगरीगढ़ के लिए 8 लाख की राशि मंजूर की गई है। ये कार्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को उन्नत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हैं।

प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और लोरमी विधायक अरुण साव के प्रयास से सड़क निर्माण के क्षेत्र में लोरमी क्षेत्र को बड़े पैमाने पर विकास कार्यों की सौगात मिली है। ग्राम सिलतरा (गाड़ाटोला), डिंडौरी (चि.), फुलवारी कला, गुरुवाईनडबरी, बघनीभांवर, बघर्रा और जमुनाही जैसे गांवों में सीसी सड़कों के निर्माण के लिए कुल करोड़ों रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। इनमें से गुरुवाईनडबरी में नाली निर्माण के लिए भी 10 लाख की अतिरिक्त राशि आवंटित की गई है। इन प्रयासों से न केवल आवागमन सुविधाजनक होगा.

कार्यालय कार्यपालन अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड, दन्तेवाड़ा
(फोन/फैक्स नं. 07856-252362, ई-मेल eedan-phe-cg@nic.in)

निविदा सू. क्र./52-53/ले.शा./का.अ./ लो.स्वा.यां./2024 दन्तेवाड़ा, दिनॉक- 05/12/2024

// निविदा आमंत्रण सूचना //

एकीकृत पंजीयन व्यवस्था प्रणाली अंतर्गत सक्षम श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से प्रपत्र ए प्रतिशत दर पर निम्नलिखित कार्य हेतु (Online) निविदा आमंत्रित की गयी है।

कार्य का नाम- नलकुप खनन का कार्य ।

क्रं.	सिस्टम टेण्डर क्रमांक	कार्य का विवरण	निविदा आमंत्रण	अनुमानित लागत (लाख में	अमानत राशि (रू. में
1.	162505	रिस्क एंड कॉष्ट विकासखण्ड कटेकल्याण में 38 नग नलकुप खनन	चतुर्थ काल	43.20	32400.00
2.	162506	रिस्क एंड कॉष्ट विकासखण्ड कुआकोण्डा में 27 नग नलकुप खनन	चतुर्थ काल	29.67	22260.00
		कुल योग		72.87	

निविदा की सामान्य शर्तें एवं अन्य जानकारी वेबसाईट पोर्टल http://eproc.cgstate.gov.in पर दर्शित है।

टीप- निविदा डाउनलोड करने की अंतिम तिथि दिनाँक 20.12.2024 है।

कार्यपालन अभियंता
जी- 242504428/4 लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खंड, दंतेवाड़ा

ईवीएम को लेकर विपक्ष का सेलेक्टिव रवैया कितना उचित

विनोद पाठक

भारत में विपक्ष चुनाव में अपनी हार स्वीकार करने को तैयार नहीं दिखता। जब उसकी हार होती है तो वो तुरंत इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) पर सवाल खड़े करने लगता है, लेकिन इस बार महाराष्ट्र में बात इससे आगे बढ़ती दिख रही है। शिवसेना (उद्धव ठाकरे) के विधायकों ने विधानसभा में शपथ का बहिष्कार कर दिया है। वो ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं। राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी (शरद पवार) के सुप्रीमो शरद पवार ईवीएम के विरोध को लेकर आयोजित विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। आखिर भारतीय विपक्ष किस दिशा में जा रहा है? चुनाव आयोग क्यों विपक्ष को ईवीएम को लेकर विश्वास नहीं दिला पा रहा है? क्या ईवीएम को लेकर विपक्ष का सेलेक्टिव रवैया उचित है? एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए यह बेहद गंभीर बात है। कुछ माह पहले हरियाणा में विधानसभा चुनाव हुए थे। मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस अपनी जीत को लेकर पूरी तरह आश्वस्त नजर आ रही थी, लेकिन जब परिणाम आए तो भारतीय जनता पार्टी ने जीत की हैट्रिक लगाते हुए पहले से अधिक सीटों पर जीत दर्ज की। कांग्रेस ने ईवीएम में गड़बड़ी को लेकर चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर सवाल उठाने में एक क्षण नहीं लगाया। हालांकि, चुनाव आयोग ने कांग्रेस को न केवल फटकारा, बल्कि कार्यवाही की चेतावनी भी दी। अब महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव हुए तो महाराष्ट्र में महायुति, जिसमें भाजपा, शिवसेना (शिंदे) और राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी (अजीत पवार) ने एकतरफा जीत दर्ज की। झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में इंडी गठबंधन ने सत्ता में पहले से अधिक बहुमत के साथ वापसी की। झारखंड की जीत को लेकर न तो ईवीएम पर कोई सवाल खड़े हुए और न चुनाव में गड़बड़ी की बात कही गई, लेकिन महाराष्ट्र का नतीजा विपक्ष खारिज करने में जुटा है। साफ है, भारत में विपक्ष दोहरे मापदंड अपना रहा है। जहां-जहां उसकी हार होती है, वहां-वहां ईवीएम पर सवाल उठाना एक फैशन हो गया है। पश्चिम बंगाल, तेलंगना, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में जब विपक्षी दल जीते तो एक भी सवाल चुनाव प्रक्रिया पर नहीं उठाया गया। क्या यही विपक्ष का असली चेहरा है? लोकतंत्र में हार-जीत होती रहती है, लेकिन पूरी चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाना कितना जायज है? शरद पवार कह रहे हैं कि महायुति की जीत को लेकर लोगों में उत्साह नजर नहीं आ रहा है। आखिर उत्साह का पैमाना क्या है? यह भी शरद पवार जैसे वरिष्ठ नेता को बताना चाहिए। इसी साल गर्मियों में जब लोकसभा चुनाव हुए थे तो 400 सीटों पर जीत का दावा कर रही भाजपा 240 सीटें ला सकी थी। इंडी गठबंधन ने 233 सीटों पर जीत हासिल की थी। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनाई। विपक्ष आज तक लोकसभा चुनाव के नतीजों को भी स्वीकार करने को तैयार नहीं है। क्या यह देश के वोटरों के साथ धोखा नहीं है? क्या विपक्ष को 233 सीटें ईवीएम में पड़े वोटों से नहीं मिलीं? ऐसा नहीं है, आज का विपक्ष ईवीएम पर सवाल उठा रहा है। ईवीएम हमेशा से विपक्ष के लिए एक राजनीतिक हथियार रही है। वर्ष 2009 के लोकसभा चुनाव में पहली बार भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार लालकृष्ण आडवाणी और तत्कालीन जनता पार्टी के अध्यक्ष सुब्रमण्यम स्वामी ने ईवीए के जरिए चुनाव में धांधली की बात कही थी। स्वामी तो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम में वीवीपैट के उपयोग का निर्देश दिया था। चुनाव आयोग अक्सर ईवीएम को हैक करने की चुनौती देता है, लेकिन आज तक कोई भी विशेषज्ञ या नेता ईवीएम को हैक करने के लिए नहीं पहुंचा है। एलन मस्क ने कुछ दिन पहले भारत में मतगणना को लेकर तारीफ की थी और उन्होंने यहां तक कहा था कि भारत में एक दिन में 64 करोड़ मतों को गिन लिया गया, जबकि अमेरिका जैसे विकसित देश में भी यह संभव नहीं है। ईवीएम पर भले राजनीतिक दल सवाल उठा रहे हैं, लेकिन यह कागज के इस्तेमाल से बेहद सस्ता उपाय है। बैलेट पेपर से चुनाव होने के दुष्परिणामों को देश पहले देख चुका है। किस तरीके से बूथ कैप्शन होती थी। लोग बैलेट बाक्स लेकर भाग जाते थे। मतों की गणना में कई दिन लगते थे। विपक्ष का हार स्वीकार न करना और पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर सवाल उठाना उचित प्रतीत नहीं होता।

मारकडवाडी की 'प्रोटेस्ट मॉकड्रिल' में निहित सवाल

अजय बोकिल

चुनाव नतीजे अगर पक्ष में हो तो जनादेश और विपरीत हों तो ईवीएमादेश बताने के नैरेटिव का एक बेहद नाटकीय लेकिन चिंताजनक प्रसंग महाराष्ट्र के मारकडवाडी गांव में परिणामों को नकार कर फिर से मतपत्रों के जरिए चुनाव कराने की मॉक ड्रिल का है। इससे चौंके प्रशासन ने सख्ती के साथ इस मुहिम को फेल कर दिया, लेकिन आने वाले समय में हर नापसंद चुनाव परिणाम पर सवालिया निशान लगाकर इस तरह बैलेट पेपर से मतदान कराने की मांग की प्रवृत्ति जोर पकड़ सकती है।

मारकडवाडी के ग्रामीणों का कहना है कि वहां भाजपा प्रत्याशी को जितने वोट मिले, वह संभव ही नहीं था, क्योंकि यह गांव राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार) का गढ़ है। हालांकि यह चुनाव राकांपा (शरद) के उत्तमराव जानकर ने ही जीता, लेकिन सवाल इस बात पर उठाया गया कि हारे हुए भाजपा प्रत्याशी को भी इतने ज्यादा मत कैसे मिल गए? इसका दूसरा अर्थ यह है कि ईवीएम को मैनेज किया गया। लेकिन इसी के साथ यह सवाल भी नत्थी है कि जब ईवीएम को 'मैनेज' ही किया जाना था तो 'पूरी तरह' क्यों नहीं किया गया ताकि भाजपा प्रत्याशी राम सातपुते जीत ही जाते।

मजे की बात यह है कि एक सुनियोजित राजनीतिक एजेंडे के तहत विजयी उम्मीदवार जानकर ने त्यागी मुद्रा में कहा कि यदि चुनाव आयोग मारकडवाडी में बैलेट पेपर से फिर से चुनाव कराने पर सहमत होता है तो मैं जीतकर भी विधायक पद से इस्तीफा देने को तैयार हूं। (अगर सही में चुनाव नतीजे संदेहास्पद थे तो उन्हें सशर्त इस्तीफे की पेशकश करने के बजाए सीधे इस्तीफा दे देना था)

इसी नरेटिव के तहत ग्रामीणों ने एक प्रस्ताव पारित कर गांव में मतपत्रों के जरिए फिर से वोटिंग का ऐलान कर दिया, जबकि चुनाव कराने का अधिकार सिर्फ निर्वाचन आयोग का है। कुल मिलाकर यह संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि हमें ईवीएम तो क्या चुनाव आयोग पर ही भरोसा नहीं है। इसी के तहत राकांपा नेता शरद पवार 8 दिसंबर को मारकडवाडी पहुंचे और ईवीएम पर संदेह दोहराया।

उधर कांग्रेस ने मारकडवाडी में लोकतंत्र की शहादत बता कर इस 'गांव की पवित्र मिट्टी' दिल्ली में राजघाट में बापू की समाधि पर अर्पित करने का ऐलान किया। यह मिट्टी गांव से एकत्रित कर कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सौंपी जाएगी।

दरअसल, मारकडवाडी सोलापुर जिले की माळशिरस विधानसभा सीट के अंतर्गत आने वाला आदिवासी बहुल गांव है। माळशिरस अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट है। हाल में राज्य में हुए विस चुनाव में इस सीट पर राकांपा(शरद) के उम्मीदवार उत्तमराव जानकर ने जीत हासिल की थी। नतीजों से चौंके मारकडवाडी के लोगों ने दावा किया कि उन्होंने तो जानकर को वोट दिए थे। लेकिन ईवीएम के आंकड़े बीजेपी प्रत्याशी को ज्यादा यानी 1003 वोट दिखा रहे हैं, जबकि राकांपा उम्मीदवार को 843 वोट। ये गलत है।

गांव वालों का दावा था कि बीजेपी प्रत्याशी को 100-150 वोट से ज्यादा नहीं मिल सकते। लिहाजा उन्होंने स्थानीय प्रशासन से बैलट पेपर से फिर से मतदान की अपील की और कहा कि वो इसका खर्च उठाने को तैयार हैं। साथ ही गांव वालों ने मॉक पोलिंग के लिए 3 दिसंबर की तारीख भी तय कर दी। इससे घबराए प्रशासन ने सख्ती करते हुए निषेधाज्ञा लागू कर दी। मॉक पोलिंग रोकी और दो सौ लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की।

मारकडवाडी की तर्ज पर अकोला जिले के दो गांवों तुलजापुर और बेलतला गांव में भी ईवीएम नतीजों को खारिज करते हुए फिर से मॉक पोल की मांग उठी। हालांकि इस मॉक पोल में मत पत्रों की जगह 'महायुति' व 'महाविकास आघाडी' लिखी दो मतपेटियां रखी जानी थी। इस मॉक पोल की पहल एक स्थानीय समाचार पत्र समूह के मालिक ने की थी।

यह भी एक ड्रामा ही था। प्रशासन ने उसे भी रुकवा दिया। लेकिन असंतोष के इन सुरों के बीच अगर कुछ सच्चाई है तो चुनाव आयोग को उस पर भी ध्यान देना चाहिए। क्योंकि चुनाव आयोग की सक्षमता, पारदर्शिता और प्रामाणिकता पर दूसरे कोणों से भी सवाल उठते रहे हैं। इसका जवाब भी चुनाव आयोग को ही देना होगा।

ईवीएम को लेकर चुनाव आयोग पहले भी स्पष्टीकरण दे चुका है। लेकिन लगता है हमारे यहां ईवीएम अब मतदान की मशीन न होकर पराजित पक्ष के लिए हार के स्थाई ठीकरे के रूप में तब्दील होती जा रही है। मारकडवाडी की ही बात करें तो वहां राकांपा (शरद) के उत्तम जानकर ने भाजपा के राम सातपुते को कुल 13 हजार 147 वोटों से हराया था। जीत का यह अंतर काफी है। जानकर को ये वोट पूरे विधानसभा क्षेत्र से मिले थे। ऐसे में केवल मारकडवाडी गांव के मतदान को मुद्दा बनाकर मॉक पोलिंग करवाने की बात गले नहीं उतरती।

इस बीच चुनाव नतीजों से शुरू में हताशा में डूबे शरद पवार भी मारकडवाडी पहुंचे और उन्होंने कांग्रेस की तर्ज पर चुनाव ईवीएम के बजाए बैलट पेपर से कराने की मांग दोहराई। उन्होंने कहा कि जब दुनिया के बाकी लोकतांत्रिक देशों में मत पत्रों के जरिए मतदान हो रहा है तो भारत में क्या दिक्कत है। उन्होंने यह भी दावा किया कि महाराष्ट्र के चुनाव नतीजों से राज्य की जनता खुश नहीं है। इस बयान के पीछे कई चुनाव लड़ चुके शरद पवार की यह पूर्वाग्रह है कि मतदाता जो मानस लोकसभा चुनाव में बनाता है, वही विधानसभा चुनाव नतीजों में भी परिलक्षित होता है। हकीकत में ऐसा हो, जरूरी नहीं है। विधानसभा चुनाव के मुद्दे और तकाजे अलग अलग होते हैं। दोनो में हमेशा एक से नतीजे आएं, यह जरूरी नहीं है।

महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के चार माह पहले देश के साथ राज्य की 47 लोकसभा सीटों पर हुए चुनाव में इंडिया गठबंधन ने 30 सीटें जीतकर भारी कामयाबी हासिल की थी। लेकिन विधानसभा चुनाव आते-आते पवार के प्रति सहानुभूति लहर और इंडिया गठबंधन के पक्ष में बना माहौल हाशिए पर चला गया। शरद पवार की पार्टी विस चुनाव में मात्र 10 सीटें ही जीत पाई।

यहां दिलचस्प बात यह है कि लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के घटक राकांपा(शरद) ने 8 सीटें जीतने से गदगद पवार ने पीएम नरेंद्र मोदी पर तीखा कटाक्ष करते हुए कहा था कि मोदी के धुआंधार प्रचार के कारण ही हम शानदार जीत हासिल कर पाए। तब पवार के हिसाब से ईवीएम भी बढ़िया काम कर रही थी। लेकिन विधानसभा चुनाव में हार के लिए उन्होंने मोदी को श्रेय देने की जगह हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ा। गोया लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए ईवीएम अलग-अलग ढंग से मैनेज की गई हों।

इन चुनावों में अगर शरद पवार की पार्टी के परफार्मेंस की ही बात की जाए तो उन्हें इस साल हुए लोकसभा चुनाव में 10.27 फीसदी वोट मिले थे और चार माह बाद हुए विधानसभा चुनाव में 11.28 प्रतिशत वोट मिले। यानी करीब एक फीसदी ज्यादा। अजित पवार गुट के अलग होने के बाद शरद पवार के पास 14 विधायक बचे थे। अब चुनाव बाद भी उनके 10 विधायक हैं। यानी कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। अब शरद पवार अपनी निराशा को जनता की हताशा के रूप में पेंट करना चाहते हैं तो यह भी एक थकी हुई चाल ही है।

अगर महाराष्ट्र के चुनाव नतीजे सच में जनाकांक्षा के पूरी तरह विपरीत आते तो जनता ही सड़कों पर उतर आती। वैसा कहीं कुछ नहीं दिखा। ईवीएम खारिज करने को लेकर जो राजनीतिक प्रतिरोध हो रहा है, उसे भी आम जनता कौतूहल के साथ देख रही है। अलबत्ता हर चुनाव में मारकडवाडी जैसी 'प्रोटेस्ट मॉक ड्रिल' हर जगह होने लगेगी तो हमारे समूचे चुनाव सिस्टम पर गंभीर सवाल उठने लगेगा। इससे कोई समाधान शायद ही निकले, लेकिन अवांछित अराजकता जरूर फैलेगी। सुविधानुसार ईवीएम को खारिज करने और निर्वाचन प्रक्रिया को कटघरे में खड़ा करते रहने की जगह अगर पराजित पार्टियां आत्मावलोकन कर आंतरिक सुधार करें तो लोकतंत्र ज्यादा मजबूत होगा।

पुराण दिग्दर्शन .... तीसरा अध्याय

वेदों में अष्टादश पुराणों के नाम

गतांक से आगे...

अर्थात-[प्रो0 राजाराम कृत भाषार्थ (भुत्रनज्ञानं) भुवन का ज्ञान (सूयें) सूर्य में (संयमात्) संयम से होता है। भाष्य- सूर्य के प्रकाश में साक्षात्कार करने से योगी को सारे मण्डलों (भुवनों कुर्सी) का यथावत् ज्ञान होता है।

सो यदि वेदव्यास जी ने योगशस्ति से अमेरिका-स्थित पुरुषों के इस दुर्व्यसन को जानकर और भविष्य में भारत में भी लोगों के इस इल्लत में फँस जाने की सम्भावना से, सर्वसाधारण को इसके प्रति सावधान कर दिया हो तो इसमें विस्मयजनक क्या बात हुई?

प्रतिवादी के शब्दों में धूम्रपान आदि श्लोक में हुक्का पीने वाले ब्राह्मण को दान देने की मनाही की गई है और उस ब्राह्मण को निन्दित बताया है। हम पूछते हैं कि यह उपदेश भला है या बुरा? हमारे विचार में तो यदि शङ्कालु महाशय पुराण के इस अकेले श्लोक का प्रचार करते तो देश का अर्थों रुपया स्वाहा होने से बच जाता! और करोड़ों भारतीयों की खुल्लखुल का खात्मा हो जाता!! आयुर्वेद स्वयं इस दुर्व्यसन को हानिप्रद बताता है तथा प्रत्यक्ष में भी तमाखूनोशी से कई प्रकार की हार्दिक बीमारियों का लगाव होना देखा जाता है, यथा- तस्यैव धूम्रपानं तु विशेषाद् हृदि शुक्रहत्। (योगरत्नाकर पृ0 14)

अर्थात्- तमाखू का घूंआ पीने से विशेषतया हृदय का ह्रास हो जाता है। आजकल इसी दुर्व्यसन से हार्टफेल रोग की वृद्धि हो रही है। इसलिए व्यास जी की हितकर शिक्षा को आधुनिक बताना तभाखू पीने वालों की पीठ ठोंक कर उन्हें दुर्व्यसन में प्रवृत्त करना है। वेद स्मृति में तो स्पष्टतया इसका निषेध नहीं मिलता और पुराण के निषेध को आधुनिक बता कर उड़ाने की चेष्टा की जाती है। ऐसी दशा में इस तपेदिक की भाँति उपेक्षितप्रायः - किन्तु भयंकर - व्यसन को किस आधार पर हटाया जा सकता है। **क्रमशः ...**

अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस

विकास

हर साल 11 दिसंबर को पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया जाता है। इसका मकसद यही है कि लोग पहाड़ों पर रहने वालों की समस्याओं से वाकिफ हों। जलवायु और भूमिगत परिवर्तनों के कारण पर्वतों की भूगोलिक स्थिति में परिवर्तन आ रहा है इसलिए इन क्षेत्रों का विकास और संरक्षण हो। साथ ही इसका उद्देश्य इसकी समृद्ध जैव विविधता के बारे में लोगों को जागरूक करना है। इसी के मद्देनजर हर साल इसका आयोजन किया जाता है।

अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस की थीम हर साल अलग-अलग होती है, जो सतत पर्वतीय विकास के विभिन्न पहलुओं पर केंद्रित होती है। यह दिन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को पर्वतीय क्षेत्रों में टिकाऊ प्रथाओं को बढ़ावा देने, इन पारिस्थितिक तंत्रों के सामने आने वाले खतरों और चुनौतियों का समाधान करने और वैश्विक सतत विकास के संदर्भ में पहाड़ों के महत्व को पहचानने के लिए प्रोत्साहित करता है।

आज के समय में जब जलवायु और भूमिगत परिवर्तनों की वजह से पर्वतों की भूगोलिक स्थिति में बदलाव आता जा रहा है। वनों को नष्ट किए जाने की घटनाएं सामने आ रही हैं, तो पृथ्वी और मानव जीवन के लिए गंभीर विषय है। ऐसे में जरूरी है कि लोग पर्वतों के प्रति अपने दायित्वों को समझें। इसीलिए लोगों को इसके प्रति जागरूक करने के लिए हर साल अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ (यूएन) ने इंसानों के जीवन में पहाड़ों के महत्व और अहम भूमिका को पहचानने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस को मनाने की परंपरा की शुरुआत की। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस के बहाने पर्यावरण में पहाड़ों की भूमिका के बारे में बताया जाता है। साल 1992 में संयुक्त राष्ट्र की ओर से एक प्रस्ताव सामने लाया गया। इसमें पहाड़ों पर रहने वालों की ओर ध्यान दिलाया गया। वहीं पहाड़ के महत्व को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2002 को संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय पर्वत वर्ष घोषित किया। इसके बाद 11 दिसंबर, 2003 से अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया जाने लगा। तब से ही यह हर साल मनाया जाता है। पर्वत पृथ्वी की लगभग 27 प्रतिशत भूमि को कवर करते हैं और दुनिया के लगभग आधे जैव विविधता वाले हॉटस्पॉट की मेजबानी करते हैं। वे अनुमानित आधी मानवता को ताज़ा पानी भी उपलब्ध कराते हैं। वे पौधों और जानवरों की एक असाधारण श्रृंखला और विभिन्न भाषाओं और परंपराओं वाले कई सांस्कृतिक रूप से विविध समुदायों का भी घर हैं। फिर भी, पहाड़ जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से पीड़ित हैं। इसलिए, अंतर्राष्ट्रीय समुदायों को उनकी जैव विविधता की सुरक्षा के लिए उपाय करने की याद दिलाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाना महत्वपूर्ण है। यह दिन पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए बेहद ही खास है। आज के दिन अलग-अलग मंचों पर कई प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती है जिससे वहां रह रहे लोगों को जागरूक किया जा सके।

सीरिया, तख्तापलट और गैस का खेल...

दीपक वोहरा

सीरिया में बशर अल-असद की सत्ता का पतन हो गया है और अपदस्थ शासक भाग खड़े हुए हैं। लेबनान में उतरने की अनुमति नहीं मिलने पर उनका विमान यू-टर्न लेता हुआ रूसी बेस टार्टस की ओर बढ़ गया और तभी से वह वाणिज्यिक रडार से गायब है। आशंका यह भी है कि तुर्किये द्वारा उपलब्ध कराई गई अमेरिकी मिसाइल से उन्हें मार गिराया गया हो। उनका परिवार कुछ दिन पहले ही रूस चला गया था।

दरअसल, जिहादी समूह हयात तहरीर अल-शाम (एचटीएस) की अगुवाई में विद्रोहियों ने नवंबर के अंत में बड़ा संघर्ष छेड़ा और सीरिया के सबसे बड़ शहर अलेप्पो समेत कई प्रमुख शहरों पर कब्जा करने के बाद आठ दिसंबर को राजधानी दमिश्क को भी अपने कब्जे में ले लिया। सेना के अधिकारी इराक भाग गए, जो कभी तानाशाह सद्दाम हुसैन के अधीन उनके सबसे बड़े हितैषी थे। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस मामले में कहा कि सीरिया हमारा दोस्त नहीं है और वहां जो कुछ भी हो रहा है, उससे हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि यह हमारी लड़ाई नहीं है। कभी अलकायदा से संबद्ध रहा जभात अल-नुसरा, जिसे हयात तहरीर अल-शाम के नाम से जाना जाता है, ने पहले तुर्किये से सटे इदलिब प्रांत में जबर्दस्त हमला किया। इसके बाद अलेप्पो पर कब्जा करने समेत 72 घंटे में ही राजधानी दश्मिक पर चढ़ाई कर दी। एक विद्रोही नेता ने खुलासा किया है कि वे इसके लिए बीते पांच वर्षों से तुर्किये में ट्रेनिंग ले रहे थे।

सीरियाई सरकार के सबसे बड़े सहयोगी ईरान, रूस और लेबनानी लड़ाके हिजबुल्ला थे, जबकि विद्रोहियों को अमेरिका, तुर्किये, सऊदी अरब, कतर, ब्रिटेन, फ्रांस, इस्त्राइल और नीदरलैंड से राजनीतिक और सैन्य समर्थन मिला। तहरीर अल-शाम के चालाक नेता अबू मोहम्मद अल-जोलानी ने सीएनएन को दिए साक्षात्कार में कहा कि हमें बशर अल-असद को उखाड़ फेंकने का काम सौंपा गया था और यही हमारा भी मकसद था। अल-जोलानी कट्टर इस्लामवादी है, जिसने इराक में अमेरिका के खिलाफ अलकायदा के लिए लड़ाई लड़ी थी और 2018 में अमेरिका ने एचटीएस को विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित कर उस पर एक करोड़ डॉलर का इनाम रखा था। अल-जोलानी ने कहा कि ईरानियों ने समय लेकर शासन को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया और रूस ने इसे आगे बढ़ाने की कोशिश की। रूस के सबसे सुरक्षित चार सैन्य अड्डे सीरिया में हैं। सीरिया का बड़ा हिस्सा अमेरिका समर्थित कुर्द लड़ाकों और तुर्किये समर्थित सुन्नी गुट के नियंत्रण में था और पूर्वी सीरिया को अमेरिका नियंत्रित कर रहा था। इस्त्राइल ने जब जरूरी समझा, तभी हवाई हमले किए। इससे आईएस हार गया, लेकिन वह छिप कर धावा करने की शैली वाले हमले करता रहा।

सवाल यह है कि सीरिया में 2011-2012 में गृहयुद्ध क्यों शुरू हुआ? दरअसल, यह सब मामला गैस का है। अमेरिका और उसके सहयोगी कतर की गैस को तुर्किये के रास्ते सऊदी अरब, जॉर्डन और सीरिया से होते हुए यूरोप तक पाइपलाइन से ले जाना चाहते रहे हैं, ताकि यूरोप की रूसी प्राकृतिक गैस पर निर्भरता खत्म हो जाए, विशेषकर सर्दियों के दिनों में। रूस और उसके सहयोगी 5,600 किलोमीटर पाइपलाइन ईरान-इराक-सीरिया के रास्ते बनाना चाहते थे, जो रूस के सहयोगियों को मजबूत करने के साथ ही ईरानी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देती। वर्तमान में जो भी फसाद हुआ है, उसके पीछे की असल वजह पाइपलाइन ही है।

बशर अल-असद ने वर्ष 2010 में कतर द्वारा दिए गए दस अरब डॉलर की गैस पाइपलाइन के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। वह यूरोप में रूस के वाणिज्यिक गैस हितों की रक्षा करना चाहते थे। वर्ष 2019 में लीक हुए दस्तावेजों से पता चलता है कि सीआईए ने सीरिया में गृहयुद्ध को भड़काने के लिए फंडिंग की और बशर अल-असद पर इस्तीफा देने के लिए दबाव बनाया, ताकि अमेरिकी समर्थक को राष्ट्रपति पद पर बैठाकर अपने हिसाब से समझौते करवाए जाएं। इसलिए तथाकथित रूप से वर्ष 2011 में अरब स्प्रिंग (सरकारों के खिलाफ विद्रोह) पूरे क्षेत्र में फैल गया, ट्यूनीशिया, मिस्र और लीबिया में तानाशाहों को उखाड़ फेंका तथा यमन, बहरीन और सीरिया में महंगाई, भाई-भतीजावाद, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को लेकर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए। फ्री सीरियन आर्मी जैसे विद्रोही समूहों को पश्चिम और तुर्किये की खुफिया एजेंसियों का साथ मिला। सीरिया के सहयोगी ईरान, लेबनान का हिजबुल्ला और रूस उसके बचाव में उतर आए।

पश्चिम पूरी तरह से विद्रोहियों के साथ था, क्योंकि वे बशर को पसंद नहीं करते थे। बराक ओबामा के समय अमेरिका की विदेश मंत्री रहीं हिलेरी क्लिंटन ने वर्ष 2012 में घोषणा कर दी थी कि बशर अब कुछ ही दिन के राष्ट्रपति हैं। क्लिंटन ने इस्तांबुल में फ्रेंड्स ऑफ द सीरियन पीपुल के एक सम्मेलन में भाग लेने के बाद कहा था, 'असद को जाना ही होगा।' लेकिन वर्ष 2015 में रूस ने उनकी सत्ता बचा ली थी। रूस ने इस बार भी विद्रोहियों पर बमबारी की, लेकिन वे आगे बढ़ते गए, जिसने वर्ष 2014 के इस्लामिक स्टेट (आईएस) के मार्च की याद दिला दी। वर्ष 2017 में इस्लामिक खलीफा के अमीर अबू बक्र अल-बगदादी ने खुद को उड़ा लिया था। इस्त्राइल ने पश्चिमी सीरिया में हिजबुल्ला और ईरानी सेनाओं पर बार-बार हमले किए हैं। अगस्त 2016 में तुर्किये ने उत्तरी सीरिया पर बहुआयामी हमले किए। अक्तूबर 2019 में डोनाल्ड ट्रंप ने अल-बगदादी के खात्मे के बाद उत्तर-पूर्वी सीरिया से तत्काल अमेरिकी फौजों को बुला लिया था, लेकिन तुर्किये को चेतावनी दी थी कि उसके फैसले का?गलत लाभ न उठाया जाए, अन्यथा तुर्किये की अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया जाएगा।

सीरियाई संघर्ष में दस लाख से अधिक लोगों की मौत हुई, जो 21वीं सदी में द्वितीय कांगो युद्ध के बाद दूसरा सबसे बड़ा घातक संघर्ष बन गया। वर्ष 2023 की अंकारा बमबारी के जवाब में तुर्किये की सेना ने वर्ष 2023 के अंत में सीरियाई डेमोक्रेटिक सेना को लक्षित कर उत्तर-पूर्वी सीरिया में हवाई और जमीनी हमले किए। हालांकि यह भी सच है कि बशर द्वारा मुक्त बाजार नीतियों में तेजी लाने के बाद से सामाजिक और आर्थिक असमानता काफी बढ़ गई थी। इन नीतियों की वजह?से देश की अल्पसंख्यक आबादी को लाभ पहुंचा, जो सरकार के साथ जुड़ी थी। देश उच्च युवा बेरोजगारी का सामना कर रहा था। इसलिए कुछ तो होना ही था। इसका नतीजा यही हुआ जो आप देख रहे हैं।

आज का इतिहास

1944 ब्रिटिश की आठवीं सेना ने इटली के लैमोन पर चढ़ाई की।
1962 सजायाफ्ता हत्यारे रोनाल्ड टर्पिन और आर्थर लुकास कनाडा में निष्पादित होने वाले दो व्यक्ति थे।
1964 संयुक्त राष्ट्र के युनिसेफ़ की स्थापना हुई। यह संगठन 150 से अधिक देशों में सक्रिय है। इसका केंद्र न्यूयार्क में है।
1972 अपोलो 17 (प्रतीक चिन्ह), अंतिम अपोलो चंद्रमा मिशन, चंद्रमा पर उतरा।
1972 अपोलो 17, अंतिम अपोलो चंद्रमा मिशन, चंद्रमा पर उतरा।
1981 साल्वाडोरन सिविल वॉर-लगभग 900 नागरिकों को गुरविला विरोधी सशस्त्र बलों द्वारा एक गुरिल्ला-विरोधी अभियान में मार दिया गया।
1986 वैज्ञानिकों ने स्पेन में पिछले सितंबर के दौरान होने वाली पक्षियों की बड़ी संख्या के कारण का पता लगाया है। यह पाया गया कि कीटनाशकों ने स्पेन के चावल उगाने वाले क्षेत्र में 5,000-10,000 पक्षियों को जहर दिया।
1994 रुस के दक्षिण पश्चिमी गणराज्य चेचनिया पर रुसी सेना ने आक्रमण आरंभ किया।
1997 जापान के क्योटो में आयोजित एक सम्मेलन में 50 देशों द्वारा ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को नियंत्रित करने के उपायों पर चर्चा की गई और सहमति व्यक्त की गई। इसका उद्देश्य वातावरण में ग्रीनहाउस गैस सांद्रता के स्थिरीकरण को एक स्तर पर प्राप्त करना है जो जलवायु प्रणाली के साथ खतरनाक मानवजनित हस्तक्षेप को रोक देगा।
2005 कोरिया में चल रही हड़ताल ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों कोरियाई वायु को प्रभावित किया है, जिससे यह बंद हो गया है।
2005 स्थानीय लोगों के प्रति हालिया हिंसा के खिलाफ क्रोनुल्ला, न्यू साउथ वेल्स में ऑस्ट्रेलियाई लोगों द्वारा किया गया एक प्रदर्शन एक दंगे में बदल गया।
2006 डिस्कवरी, नासा का स्पेस शटल अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन के साथ सफलतापूर्वक डॉक करता है। अंतरिक्ष स्टेशन को फिर से चलाने के लिए चालक दल को एक सप्ताह बिताने की उम्मीद है।
2006 मैक्सिकन ड्रग युद्ध में पहली कार्रवाई राष्ट्रपति फेलिप काल्डेरोन के रूप में हुई, जिसमें मैक्सिकन सेना और संघीय पुलिस यूनियनों को मिसेकान राज्य में आदेश दिया गया।
2007 उत्तर व दक्षिण कोरिया के मध्य 50 वर्ष बाद रेल सेवा पुनः प्रारम्भ।

भाजपा में मोदी युग के बाद का नेतृत्व तैयार करने में जुटा संघ

विनोद अग्निहोत्री

पहले हरियाणा में हार को जीत में बदल कर तीसरी बार सरकार बनाने और फिर महाराष्ट्र में आशा के विपरीत एकतरफा तूफानी बहुमत हासिल करके भारतीय जनता पार्टी और उसके नेतृत्व वाले गठबंधन एनडीए ने लोकसभा चुनावों में मिले खासे झटके के सदमे को नए हौसले में बदल दिया है। हालांकि, इसी दौर में जम्मू कश्मीर और झारखंड में विपक्षी इंडिया गठबंधन की भी जीत हुई है, लेकिन हरियाणा और महाराष्ट्र की जीत के जश्न और शोर में इन दोनों राज्यों में भाजपा की नाकामयाबी की चर्चा दब गई है।

भाजपा की इस जीत का श्रेय यूं तो हर बार की तरह पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता और गृह मंत्री अमित शाह की रणनीति को दे रही है, लेकिन दूसरी तरफ इन दोनों राज्यों की सफलता को भाजपा के मातृ संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) ने अपने हजारों स्वयंसेवकों की मेहनत का नतीजा बताया है। आमतौर पर संघ पर्दे के पीछे रहकर ही काम करता है और चुनावी सफलता का श्रेय संघ कभी सीधे नहीं लेता है, लेकिन पहली बार उसने खुलकर इसका श्रेय अपने स्वयंसेवकों को दिया है। इसके साथ ही संघ अब मोदी युग के बाद भाजपा के नेतृत्व को गढ़ने में जुट गया है।

संघ के इस रुख के कई संकेत हैं। पहला ये कि लोकसभा चुनावों में जब भाजपा के 370 और एनडीए के चार सौ पार के नारे की हवा निकली और भाजपा बमुश्किल 240 सीटें ही जीत पाई और तीसरी बार उसे अपनी सरकार बनाने के लिए सहयोगी दलों के समर्थन पर निर्भर होना पड़ा है। तब संघ की तरफ से यह संदेश दिया गया कि ऐसा इसलिए हुआ कि लोकसभा चुनावों में आरएसएस के स्वयंसेवक उदासीन हो गए और संघ ने इन चुनावों को पूरी तरह मोदी शाह और भाजपा के भरोसे छोड़ दिया था। नतीजा ये कि भाजपा को अपने बलबूते बहुमत के आंकड़े के भी लाले पड़ गए। यह एक तरह से चुनावों के बीच में एक अखबार को दिए गए इंटरव्यू में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के बयान कि भाजपा अब अपने पैरों पर खडी हो गई है और उसे अब संघ के सहारे की जरूरत नहीं है,का संघ की तरफ से दिया गया जवाब भी माना जा सकता है।

लोकसभा चुनावों के झटके के बाद भाजपा ने हरियाणा महाराष्ट्र और झारखंड के चुनावों के लिए संघ की तरफ देखा और संघ ने इस मौके को हाथ से जाने नहीं दिया। संघ के हजारों स्वयंसेवक इन राज्यों में फैल गए। बताया जाता है कि अकेले हरियाणा में संघ ने छोटी बड़ी सब मिलाकर करीब बीस हजार बैठकें कीं। यह संख्या महाराष्ट्र में और भी ज्यादा थी। इन विधानसभा चुनावों के पूरे सियासी विमर्श को संघ ने ही गढ़ा। सबसे पहले उत्तर प्रदेश में संघ के चहेते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नया नारा दिया बटेंगे तो कटेंगे जो लोकसभा चुनावों में विपक्ष द्वारा सामाजिक न्याय के नाम पर किए गए जातीय ध्रुवीकरण की काट के तौर पर दिया गया था। योगी के इस नारे पर संघ प्रमुख सर संघ चालक मोहन भागवत ने मुहर लगाई और फिर नारा विधानसभा चुनावों में भाजपा का चुनावी नारा बन गया। महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे थोड़ा परिष्कृत करके कहा एक हैं तो सेफ हैं। इन दोनों नारों का संदेश साफ था कि हिंदुओं जातियों में न बंट कर एकजुट होकर भाजपा के लिए मतदान करो। हरियाणा में जहां इस नारे के जरिए जाटों के वर्चस्व के जवाब में गैर जाटों का

भाजपा के पक्ष में ध्रुवीकरण किया गया वहीं महाराष्ट्र में विपक्ष के मुस्लिम और जातीय ध्रुवीकरण के जवाब में यह नारा हिंदू ध्रुवीकरण का मंत्र बन गया। कोशिश झारखंड में भी की गई लेकिन वहां हेमंत सोरेन के आदिवासी ध्रुवीकरण ने बटेंगे तो कटेंगे को बेअसर कर दिया।

इस नारे से बने चुनावी विमर्श और उससे आए महाराष्ट्र के नतीजों ने भाजपा पर संघ की पकड़ को फिर से मजबूत कर दिया है, जो 2019 के बाद धीरे धीरे कमजोर हो चली थी। इसका सबसे बड़ा परीक्षण महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के चयन सामने आया जब करीब दो सप्ताह तक चली भारी कशमकश के बाद आखिरकार देवेंद्र फडणनवीस के नाम पर ही पार्टी ने मुहर लगाई। हालांकि, लोकसभा चुनावों में महाराष्ट्र में भाजपा को मिली करारी हार से देवेंद्र फडणनवीस के करिश्मे पर भी ग्रहण लग गया था और उन्होंने अपनी जिम्मेदारी लेते हुए उप मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे के पेशकश भी की थी, लेकिन उसे नामंजूर करते हुए पार्टी ने उन्हें विधानसभा चुनावों के लिए जुट जाने को कहा और देवेंद्र फडणनवीस ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में भाजपा नीत महायुति गठबंधन की जीत के लिए रणनीति बनाने से लेकर प्रत्याशी चयन,सीटों के बंटवारे और प्रचार अभियान का नेतृत्व करते हुए जी तोड़ मेहनत की और महायुति की महाजीत का श्रेय भी सबसे ज्यादा उन्हें ही मिला। इसलिए जब मुख्यमंत्री के नाम पर अटकलें लगीं तो सबसे ऊपर उनका ही नाम था। इसके बावजूद करीब 13 दिनों तक भाजपा उनके नाम की घोषणा इसलिए नहीं कर सकी, क्योंकि पार्टी में ही एक धड़ा उनका विरोध कर रहा था और फडणनवीस के विरोधियों ने निवर्तमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तक को भी इसके लिए इस्तेमाल किया कि फडणनवीस का रास्ता रोका जा सके, लेकिन आखिरकार विरोधी नाकाम हुए और संघ के आशीर्वाद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन ने देवेंद्र फडणनवीस को फिर से महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री पद सौंप दिया।

लोकसभा चुनावों के बाद घटे इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम ने भाजपा की राजनीति में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को फिर सत्ता के एक निर्णायक केंद्र की भूमिका में ला दिया है। संघ का अगला मिशन भाजपा के संगठन को फिर अपने प्रभाव में लेने का है, जो पिछले कुछ वर्षों में उसके हाथ से काफी हद तक फिसल गया था। इसके लिए अब संघ भाजपा अध्यक्ष पद पर किसी ऐसे नेता को बिठाने की कवायद में है जो संघ निष्ठ होने के साथ साथ पार्टी संगठन को भी संघ के विचारों संस्कारों और कार्यशैली में ढाल सके।

हालांकि, अपनी इस कवायद में संघ अपने परिवार के सबसे लोकप्रिय चेहरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी नाराज और अनदेखा नहीं कर सकता है, इसलिए उसकी कोशिश है कि अध्यक्ष पद पर किसी ऐसे नेता के नाम को आगे बढ़ाया जाए जिस पर मोदी को भी कोई खास एतराज न हो, लेकिन साथ ही संघ की कोशिश है कि अध्यक्ष भले ही प्रधानमंत्री के साथ तालमेल बिठाकर चले लेकिन वह पूरी तरह सरकार और उसके सत्ता केंद्रों के आगे नतमस्तक भी नहीं होना चाहिए।

संघ अब भारतीय जनता पार्टी में मोदी के आगे के युग की तैयारी में जुट गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी भाजपा के सर्वोच्च नेता हैं और जब तक वह प्रधानमंत्री हैं वही सर्वोच्च रहेंगे, लेकिन उनकेक पंक्ति संघ तैयार कर रहा है। इन नेताओं में प्रमुख रूप से गृह मंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ ही अब नया नाम महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणनवीस का भी जुड़ गया है।

जहां तक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की भूमिका का सवाल है तो संघ के मुताबिक ये मोदी युग के ही महारथी हैं। संघ को 2029 के लोकसभा चुनावों और उसके बाद की राजनीति के लिए भाजपा नेतृत्व विकसित करना है। ऐसे में भाजपा अध्यक्ष की भूमिका खासी अहम होगी और जो भी नया अध्यक्ष होगा उसे भी भाजपा की अगली पंक्ति के नेता के रूप में देखा जाएगा और उसकी जिम्मेदारी होगी कि वह पार्टी को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार कर सके।संघ वैसी गलती दोहराना नहीं चाहती है जैसी कि अटल बिहारी वाजपेयी सरकार जाने के बाद हुई और पार्टी लाल कृष्ण आडवाणी मुरली मनोहर जोशी जैसे पुराने दिग्गजों के भरोसे ही ही रही और दस साल तक उसे केंद्रीय सत्ता से वंचित रहना पड़ा।

बांग्लादेश में हद पार हो रही है...

दीपक कुमार शर्मा

शेख हसीना के कार्यकाल में भारत के विश्वसनीय पड़ोसी रहे बांग्लादेश में हिंदुओं और अल्पसंख्यकों पर हमले तो छात्र आंदोलन के बहाने हुए तख्तापलट के बाद से ही हो रहे हैं, लेकिन अब जिस मध्ययुगीन तौर-तरीकों से वहां मंदिरों को तहस-नहस किए जाने और मूर्तियों को जलाए जाने की घटनाएं रोके नहीं रुक रहीं, वे वाकई बेहद चिंतित करने वाली हैं।

बांग्लादेश की आजादी के बाद से वहां इस तरह की घटनाएं होती रही हैं, लेकिन इतने लंबे समय तक अस्थिरता रही हो, ऐसा 1971 के बाद से नहीं देखा गया। बांग्लादेश सरकार का इन घटनाओं पर आंखें मूंदे रहना भी चौंकाता है। पांच अगस्त को शेख हसीना के अपदस्थ होने के बाद पहले तीन सप्ताह में ही अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा की दो हजार से भी ज्यादा घटनाएं दर्ज की गईं थीं, लेकिन हैरत की बात है कि अंतरिम सरकार के प्रमुख इसे गंभीर मुद्दा नहीं मानते।

दरअसल, मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार का रवैया पूरी तरह से भारत विरोधी है, जो उनके फैसलों में भी दिखता है। धर्मगुरु चिन्मयदास की गिरफ्तारी के विरोध में ढाका समेत कई इलाकों में बड़े प्रदर्शन हुए, तो दूसरी तरफ, भारत ने भी धर्मगुरु की गिरफ्तारी के मामले को निष्पक्षता से देखने की अपील की थी। लेकिन इसकी प्रतिक्रिया में बांग्लादेश की ओर से कहा गया कि यह उसका अंदरूनी मामला है। यह जानते हुए भी कि शेख हसीना से पहले खालिदा जिया के कार्यकाल में बांग्लादेश किस तरह से पाकिस्तानी

आतंकियों का ठिकाना बन गया था और पाकिस्तानी सेना के अत्याचारों से मुक्ति दिलाने के लिए भारत कभी एक मित्र के रूप में सामने आया था, अगर यूनुस सरकार भारत के बजाय उसी पाकिस्तान के साथ अपने संबंधों पर जोर दे रही है, तो इससे क्या समझा जाए। ऊपर से यूनुस का यह दावा कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के अधिकार शेख हसीना सरकार की अपेक्षया अंतरिम सरकार के कार्यकाल में ज्यादा सुरक्षित हैं, जो हालात दिख रहे हैं, उनसे बिल्कुल उलट है।

बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध अमेरिका के शिकागो व वाशिंगटन जैसे शहरों में प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन भारत के प्रमुख विपक्षी दलों की चुप्पी अखरती है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक वर्ग ने जिस एकजुट ढंग से पलायन के बजाय विरोध का रास्ता आख्तियार किया है, वह वाकई काबिले तारीफ है। भारत बांग्लादेश के साथ करीब चार हजार किलोमीटर लंबी सीमारेखा साझा करता है और बांग्लादेश में कट्टरपंथी सरकार के दौर में आतंकी किस तरह से राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन गए थे, उससे भी भारत अच्छे से वाकिफ है। ऐसे तनाव के दौर में, विदेश सचिव के बांग्लादेश दौरे की अहमियत और बढ़ जाती है।

सुखबीर बादल पर जानलेवा हमले से उपजे कई सवाल...

बलबीर पुंज

गत दिनों अमृतसर स्थित श्री?हरिमंदिर साहिब में शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर बादल पर जानलेवा हमला हुआ। इसमें वह पुलिस सतर्कता से बाल-बाल बच गए। उन पर गोली तब चलाई गई, जब वह 2007-17 के बीच अपनी सरकार के दौरान हुई 'गलतियों' के लिए 'तनखैया' घोषित किए जाने के बाद अकाल तख्त की 'सजा' पर स्वर्ण मंदिर में सेवादार की भूमिका निभा रहे थे। 68 वर्षीय हमलावर नारायण सिंह चौड़ा घोषित खालिस्तान समर्थक है और उस पर 20 से अधिक आपराधिक मामले हैं।

अकाली दल दावा करता है कि वह पंथिक संगठन है और सिखों का प्रतिनिधित्व करता है। वहीं हमलावर चौड़ा, जोकि पाकिस्तान भी जा चुका है-सुखबीर को पंथ का 'गद्दार' मानता है। इस जघन्य कांड के मूल में एक विशेष मानसिकता है। कौन सिख है, कौन नहीं और कौन सच्चा सिख है, कौन 'गद्दार'- आखिर इसका निर्णय कौन और कैसे करेगा?

बादल पर हमले के केंद्र में 150 वर्ष पुराना 'खालिस्तानी नैरेटिव' है। ब्रितानी 1857 विद्रोह की पुनरावृत्ति नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने 'बांटो-राज करो' की विभाजनकारी नीति अपनाई। इसके अंतर्गत उन्होंने भारतीय समाज की कमजोर कड़ियों को ढूंढकर उस पर बौद्धिक-शैक्षणिक काम किया। इसमें हिंदू-मुस्लिम विवाद सबसे सरल रहा, क्योंकि तब दोनों समुदायों में 600 वर्षों का शत्रुभाव था। यही कारण है कि मुस्लिमों में अलगाव पैदा हेतु अंग्रेजों को सैयद अहमद खां आसानी से मिल भी गए, जिनके 'दो राष्ट्र सिद्धांत' ने इस्लाम के नाम पर भारतीय उपमहाद्वीप में पाकिस्तान को जन्म दे दिया।

अंग्रेजों के लिए सबसे कठिन हिंदू-सिख संबंधों में कड़वाहट घोलना था-क्योंकि 15वीं शताब्दी में सिख पंथ के जन्म से ही देश का प्रत्येक हिंदू, सिख गुरुओं के प्रति श्रद्धा का भाव रखता था और प्रत्येक सिख अपनी गुरु परपंरा के अनुरूप स्वयं को धर्मरक्षक मानता था। तब अंग्रेजों ने आयरलैंड में जन्मे अपने एक अधिकारी मैक्स आर्थर मैकॉलीफ को चुना, जिसने स्वयं के सिख पंथ अपनाने का दावा किया।

मैकॉलीफ का एजेंडा, सिखों में अंग्रेजों के प्रति विद्रोह को भी रोकना था। इसलिए उसने भाई काहन सिंह नाभा की सहायता से 'श्री गुरुग्रंथ साहिब' का अंग्रेजी में विकृत अनुवाद

किया और छह खंडों में 'द सिख रिलीजन-इट्स गुरु, स्केयर्ड राइटिंग्स और ऑथर' पुस्तक की रचना की। फिर नाभा ने मैकॉलीफ से प्रेरणा लेकर 1897-98 में 'हम हिंदू नहीं' नाम से प्रकाशन निकाला। 'खालिस्तान' ब्रितानी षड्यंत्र का सह-उत्पाद है, जिसे सिख पंथ का एक वर्ग आत्मसात करके अपनी मूल जड़ों से कट गया है। स्वतंत्रता के बाद मृत 'खालिस्तान' विचार को कांग्रेस ने 1977-78 में अपने क्षुद्र राजनीतिक स्वार्थ और सत्ता हथियाने की लालसा में पुनर्जीवित किया। इसका उल्लेख गैर-राजनीतिक, पूर्व आईपीएस अधिकारी और भारतीय खुफिया एजेंसी 'रिसर्च एंड एनालिसिस विंग' (रॉ) में वर्षों जुड़े रहने के बाद सेवानिवृत्त हुए गुरबख्श सिंह सिद्धू?ने अपनी पुस्तक 'द खालिस्तान कांस्पीरेसी' में किया है। उनका खुलासा इसलिए भी महत्व रखता है, क्योंकि वह कांग्रेस के दिग्गज नेता दिवंगत सरदार स्वर्ण सिंह के दामाद भी हैं।

अपनी पुस्तक में गुरबख्श लिखते हैं, 'वर्ष 1977 के पंजाब (विधानसभा) चुनाव में प्रकाश सिंह बादल के नेतृत्व में अकाली दल-जनता पार्टी गठबंधन से कांग्रेस हार गई थी। इसके तुरंत बाद, मुझे पूर्व मुख्यमंत्री ज्ञानी जैल सिंह और संजय गांधी द्वारा जरनैल सिंह भिंडरावाले के समर्थन से अकाली दल के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार को अस्थिर करने के प्रयासों की जानकारी मिली।' बकौल सिद्धू, 'ज्ञानी जैल सिंह ने संजय गांधी को सलाह दी कि पंजाब में अकाली दल-जनता पार्टी गठबंधन सरकार को अस्थिर किया जा सकता है, यदि उनकी उदारवादी नीतियों पर...एक उपयुक्त सिख संत द्वारा लगातार हमला किया जाए।' इसके लिए तत्कालीन कांग्रेस नेतृत्व ने जरनैल सिंह भिंडरावाले को चुना और उसे 'संत' कहकर संबोधित किया। इसी विभाजनकारी राजनीति का परिणाम रहा कि भिंडरांवाले ने श्री हरिमंदिर साहिब को अपना अड्डा बना लिया। चूंकि खालिस्तान की प्रकल्पना विदेशी है और इसे अधिकांश भारतीय सिखों का समर्थन नहीं मिलता, इसलिए तब भिंडरावाले के निर्देश पर मासूम हिंदुओं के साथ देशभक्त सिखों को भी चिह्नित करके मौत के घाट उतारा जाने लगा। सैन्य अभियान 'ऑपरेशन ब्लूस्टार' के बाद पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उनके दो सिख सुरक्षाकर्मियों ने नृशंस हत्या कर दी। इसके तत्काल बाद दिल्ली सहित देश के कई हिस्सों में कांग्रेस समर्थित असामाजिक तत्वों ने हजारों निरपराध सिखों का नरसंहार किया, जिसे न्यायोचित ठहराते हुए राजीव गांधी ने कहा था, 'जब भी कोई बड़ा पेड़ गिरता है, तो धरती थोड़ी हिलती है।'

वास्तव में, सुखबीर बादल को 'पंथ का गद्दार' मानना उसी विदेशी असहिष्णु चिंतन से प्रेरित है, जिसमें केवल 'मैं सच्चा, शेष झूठे' मानने की अवधारणा है। इसी विचारगर्भ से पाकिस्तान जन्मा, जिसकी बुनियाद ही बहुलतावादी, समरस और सह-अस्तित्व आधारित भारतीय जीवनशैली का विरोध है। यही चिंतन उसे भीतर से झुलसा भी रहा है। सदियों से जारी शिया-सुन्नी संघर्ष की लपटें बीते दिनों पाकिस्तान के खैबरपख्तूनख्वा प्रांत स्थित कुर्रम तक जा पहुंचीं, जहां 22 नवंबर से शुरू हुई हिंसा में अपने सहबंधुओं के हाथों 130 से अधिक मुस्लिमों की मौत हो चुकी है। वर्ष 2001 से 2018 के बीच मजहबी घटनाओं में 4,847 शियाओं की सुन्नी कट्टरपंथी हत्या कर चुके हैं। पाकिस्तान घोषित इस्लामी राष्ट्र है। फिर भी उसका 'तहरीक-ए-तालिबान' नामक आतंकी संगठन सैकड़ों हमले करके हजारों पाकिस्तानी नागरिकों-सैनिकों को इसलिए मौत के घाट उतार रहा है, क्योंकि वे उनके मुताबिक खालिस शरीयत प्रेरित व्यवस्था को नहीं अपना रहे हैं। यही स्थिति अफगानिस्तान में तालिबान और आईएस-खुरासन के बीच भी है, जो इस्लाम के प्रति वफादार होते हुए भी एक-दूसरे का विरोध करते हैं।

पाकिस्तान और कनाडा कथित 'खालिस्तान' आंदोलन के सबसे बड़े पोषक बने हुए हैं। भारत और विशेषकर पंजाब की भलाई इसी में है कि वे सिख गुरुओं के तप, त्याग, परिश्रम और आपसी-भाईचारे के मार्ग पर चलें। अकाल तख्त द्वारा एक पूर्व उपमुख्यमंत्री को 'सजा' देने पर सवाल उठता है कि जनमत से चुनी हुई सरकार की जवाबदेही किसके प्रति होनी चाहिए-मतदाता और विधायिका के या फिर किसी मजहबी संस्था के?

जो बाइडेन द्वारा अपने बेटे को क्षमादान

कल्याणी शंकर

संयुक्त राज्य अमरीका में राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान अक्सर विवादास्पद रहा है। फिर भी, राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा अपने बेटे हंटर को क्षमादान देने जैसे कुछ निर्णयों ने अन्य की तुलना में अधिक आलोचना की है।क्षमादान का अर्थ है कि हंटर को उसके अपराधों के लिए सजा नहीं दी जाएगी और वह जेल नहीं जाएगा। उसके मामलों को संभालने वाले न्यायाधीश संभवत: बंदूक मामले के लिए 12 दिसंबर और कर मामले के लिए 16 दिसंबर को निर्धारित सजा सुनवाई को रद्द कर देंगे।

संवैधानिक रूप से, राष्ट्रपति क्षमादान दे सकते हैं; पिछले राष्ट्रपतियों ने इस शक्ति का उपयोग किया है। परंपरागत रूप से, अमरीकी राष्ट्रपति पद छोड़ते समय क्षमादान देते हैं। हालांकि, जो बाइडेन द्वारा अपने बेटे को 'पूर्ण और बिना शर्त' क्षमादान देने से इस मुद्दे में जटिलता और सार्वजनिक जांच की एक परत जुड़ गई है। यह समझना आवश्यक है कि जो बाइडेन ने ऐसा क्यों किया। वह अपने बेटे को बचाने और सार्वजनिक आलोचना के बीच फंस गए थे। हर कोई जानता है कि वह अपने परिवार के प्रति वफादार हैं। उन्होंने महत्वपूर्ण व्यक्तिगत चुनौतियों का सामना किया है। उनकी छोटी बेटी और पहली पत्नी की कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई, जिसमें उनके बेटे ब्यू और हंटर भी घायल हो गए। हंटर बाइडेन को भी अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है।

बाइडेन चाहते थे कि ब्यू राष्ट्रपति बनें, लेकिन दुर्भाग्य से 2015 में ब्यू की ब्रेन कैंसर से मृत्यु हो गई। बाइडेन परिवार के संघर्षों पर इस फोकस का उद्देश्य जनता से सहानुभूति पैदा करना है। अमरीकी मीडिया के अनुसार, बाइडेन की पत्नी ने जो को अंतिम निर्णय लेने के लिए राजी किया। बाइडेन की क्षमा के प्रति जनता की प्रतिक्रिया आलोचनात्मक और सहायक दोनों है। जबकि कुछ लोग इसे उचित मानते हैं, अन्य इसे उचित नहीं मानते हैं। अमरीकी मीडिया भी इसी तरह की मिश्रित प्रतिक्रिया प्रदर्शित करता है। बाइडेन के समर्थक इसे उचित ठहराते हैं, हालांकि उनकी पार्टी के कुछ सहयोगी नाराज हैं।

दोनों दलों के राष्ट्रपतियों ने अपनी क्षमा शक्ति का इस्तेमाल किया है, जिसने लोगों को चौंका दिया है। जॉर्ज वाशिंगटन ने कुछ लोगों को क्षमा करने के लिए शक्ति का इस्तेमाल किया। 1992 के अंत में, राष्ट्रपति जॉर्ज एच. डब्ल्यू. बुश ने ईरान-कॉन्ट्रा मामले

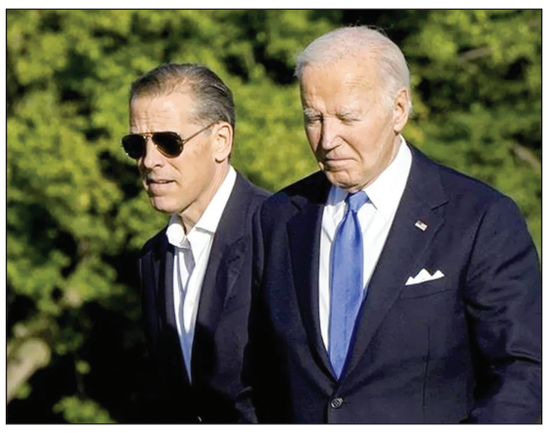

में फंसे 6 लोगों को माफ कर दिया, जिनमें पूर्व रक्षा सचिव वेनबर्गर भी शामिल थे। बिल क्लिंटन, जिन्होंने यह कहने के बावजूद कि वे ऐसा नहीं करेंगे, अपने सौतेले भाई रोजर को पिछले कोकीन के आरोपों के लिए माफ कर दिया।

इसी तरह, डोनाल्ड ट्रम्प ने अपने दामाद जेरेड कुशनर के पिता को कर चोरी और सहयोगी गवाह के खिलाफ जवाबी कार्रवाई के लिए माफ कर दिया। दोनों ने पहले ही अपनी जेल की सजा काट ली थी। अपने पहले कार्यकाल के उत्तरार्ध के दौरान, ट्रम्प ने गलत काम करने वाले विभिन्न व्यक्तियों को माफी जारी की। राहत महसूस कर रहे हंटर ने एक बयान में कहा, ''मैंने अपनी लत के सबसे बुरे दिनों के दौरान अपनी गलतियों को स्वीकार किया है और उनकी जिम्मेदारी ली है ऐसी गलतियां जिनका इस्तेमाल मुझे और मेरे परिवार को राजनीतिक खेल के लिए सार्वजनिक रूप से अपमानित करने और शर्मिंदा करने के लिए किया गया है।''

हंटर बाइडेन के खिलाफ मामला कई सालों तक चला, जिसमें कर अपराधों और बंदूक की बाड़ के आरोप शामिल थे। उन्हें जून में दोषी ठहराया गया और सितंबर में कर चोरी के लिए दोषी ठहराया गया।बाइडेन ने कहा कि हंटर पर 'चुड्क्षनदा और अनुचित तरीके से मुकद्दमा चलाया गया' और बताया कि आरोप राजनीति से प्रेरित थे। माफी का तत्काल प्रभाव यह है कि बाइडेन की माफी से डैमोक्रेट के लिए ट्रम्प की आलोचना करना मुश्किल हो जाता है। राष्ट्रपति-चुनाव में ट्रम्प ने 6 जनवरी की घटनाओं के लिए आरोपित लोगों को माफ करने की योजना बनाई है।

बाइडेन ने हंटर को माफ न करने की घोषणा करने के बाद अपने मन में जो बदलाव किया, उसके पीछे उनके अपने कारण थे। उनमें से एक उनकी पत्नी थीं, जिन्होंने बाइडेन को ऐसा करने के लिए राजी किया। उन्होंने कहा कि हंटर को सिर्फ इसलिए चुना गया क्योंकि हंटर उनका बेटा था। विश्लेषकों का यह भी दावा है कि इससे अमरीकी लोकतांत्रिक व्यवस्था कमजोर हो सकती है। राष्ट्रपति अक्सर अपने मित्रों और सहयोगियों के लिए अपनी क्षमा शक्तियों का उपयोग करते हैं। एक विवादास्पद मामला पूर्व राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन का था, जिन्हें गेराल्ड फोर्ड ने 8 सितंबर, 1974 को माफ कर दिया था। निक्सन को वाटरगेट कांड के लिए संभावित अभियोजन का सामना करना पड़ा।

राष्ट्रपति बाइडेन ने 25 व्यक्तियों को माफ किया है, जिनमें से कोई भी सीधे तौर पर उनसे जुड़ा नहीं है। आम तौर पर, राष्ट्रपति अपने कार्यकाल के अंत में कई क्षमादान अनुरोधों को मंजूरी देते हैं। फिर भी, क्षमादान राष्ट्रपति पद पर जनता के विश्वास को नुकसान पहुंचाता है। राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने 20 जनवरी, 2001 को अपने कार्यकाल के अंतिम दिन 140 क्षमादानों पर हस्ताक्षर किए। कई विधिनिर्माता भविष्य के लिए संभावित खराब मिसाल के बारे में चिंतित हैं। समस्या को हल करने का एक तरीका संविधान में संशोधन करना हो सकता है। फिर भी, यह एक लंबी प्रक्रिया है, और किसी भी पार्टी के पास कांग्रेस में इसे पारित करने के लिए पर्याप्त संख्या नहीं है।

आलोचकों का तर्क है कि यह एक खतरनाक मिसाल कायम कर सकता है और न्याय प्रणाली में जनता के विश्वास को खत्म कर सकता है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों ने राष्ट्रपति को पद पर रहते हुए की गई कार्रवाइयों के लिए आरोपित करना अधिक कठिन बना दिया है। वे क्षमादान शक्ति के किसी भी संभावित दुरुपयोग के लिए राष्ट्रपति को जवाबदेह ठहराने के रास्ते सीमित करते हैं। हंटर की याचिका के बाद, राष्ट्रपति बाइडेन अपने सहयोगियों और अधिकारियों की सुरक्षा के लिए व्यापक क्षमादान देने पर विचार कर रहे हैं। व्हाइट हाऊस की प्रैस सचिव कैरिन जीन-पियरे ने कहा कि व्हाइट हाऊस छोडने से पहले, बाइडेन अतिरिक्त क्षमादान जारी करने की योजना बना रहे हैं। हालांकि बाइडेन की टीम विचार कर रही है जिन व्यक्तियों की जांच या आरोप नहीं लगाया गया है, उन्हें क्षमा प्रदान करना।

अब किसानों के नाम पर फिर राजनीति और सड़क की लड़ाई

आलोक मेहता

कांग्रेस सहित कई राजनैतिक पार्टियां किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी, मुआवजे, मुफ्त बिजली इत्यादि की मांगों को लेकर नया तूफान खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। किसानों को उनके खेतों की उपज का उचित मूल्य मिलना निश्चित रूप से जरूरी है। लेकिन देश की आवश्यकता के अनुसार अनाज, तिलहन के उत्पादन की प्राथमिकताएं तय होने पर ही सही दाम मिल सकते हैं। इसी तरह भारत के फल, सब्जी का निर्यात करने के लिए सड़क, रेल, हवाई सुविधाओं और आर्थिक संसाधन सरकार और प्राइवेट क्षेत्र को बड़े इंतजाम करने होंगे। एक बार फिर संयुक्त किसान मोर्चा (गैरराजनीतिक) एवं किसान मजदूर मोर्चा के बैनर तले किसानों ने 6 दिसंबर को अपनी मांगों के समर्थन में दिल्ली कूच आंदोलन तेज कर दिया। इस बार किसानों के दिल्ली कूच में वह मरजीवड़ा जत्था है, जो शख्स किसी मकसद के लिए खुद को कुर्बान कर देता है। बताया जाता है कि श्री गुरु तेग बहादुर साहिब ने मरजीवड़ा जत्था (दल) बनाया था और इसमें भाई मतीदास, सतीदास और भाई दयाला को भी शामिल किया था। मतलब राजनीति के साथ धार्मिक भावना जोड़ दी है। दूसरी तरफ संसद में कांग्रेस और अन्य प्रतिपक्षी दल हमलावर हुए हैं। संगरूर के खनौरी बॉर्डर पर किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाला ने किसानों की मांगों को लेकर उपराष्ट्रपति धनखड़ को चिट्ठी भी लिखी। इस पर धनकड़ इतने भावुक और उत्तेजित हो गए कि मुंबई में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के शताब्दी समारोह में कृषि मंत्री शिवराज सिंह को कहने लगे, ''एक-एक पल आपका भारी है। कृपया करके मुझे बताइए कि किसानों से क्या वादा किया गया था? उनसे किया गया वादा क्यों नहीं निभाया गया? वादा निभाने के लिए हम क्या कर रहे हैं? गत वर्ष भी आंदोलन था, इस वर्ष भी आंदोलन हो रहा है। कालचक्र घूम रहा है, हम कुछ कर नहीं रहे हैं। पहली बार मैंने भारत को बदलते हुए देखा है। पहली बार मैं महसूस कर रहा हूं कि विकसित भारत हमारा सपना नहीं लक्ष्य है। दुनिया में भारत कभी इतनी बुलंदी पर नहीं था। जब ऐसा हो रहा है तो मेरा किसान परेशान और पीड़ित क्यों है?'' उपराष्ट्रपति ने अपने पद का उल्लेख करते हुए शिवराज सिंह चौहान पर सवालों की बौछार कर दी। देश भर में पार्टियों, जातियों, देसी-विदेशी चंदे से चलने वाले संगठनों के अनेकानेक नेता हैं। तभी तो भारत सरकार दो महीने से किसानों के दावेदार नेताओं से कई बैठक कर चुकी है और आज भी बातचीत को तैयार है। सिंधु बॉर्डर पर पुलिस से थोड़े टकराव के बाद प्रदर्शनकारी नेताओं ने तात्कालिक स्थगन कहकर बातचीत के लिए सहमति अवश्य दिखाई है, लेकिन मांगों की लंबी सूची होने के कारण क्या जल्दी समझौता संभव होगा या राजनीतिक दांव-पेंच चलते रहेंगे?

कीवी में

छिपा है पोषक तत्वों का भंडार

पोषक तत्वों से भरपूर फल स्वास्थ्य के लिए बेहद ज़रूरी होते हैं। हर फल की अपनी खासियत और फायदे होते हैं। स्वाद में खट्टा-मीठा लगने वाला कीवी भी अपने बेजोड़ फायदों के लिए जाना जाता है। इसका खट्टा मीठा स्वाद लोगों को बेहद पसंद आता है। कीवी में पोटेशियम, फाइबर, विटामिन सी, फोलिक एसिड, विटामिन ई और पॉलीफेनॉल्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। कीवी में कैलोरी कम मात्रा में होती है इसलिए वजन कम करने वालों के लिए यह फल अमृत समान है। चलिए बताते हैं इस फल का सेवन करने से कौन सी परेशानियां दूर होंगी और इसका सेवन किस समय करना चाहिए?

आंखों की रोशनी बढाए

विटामिन ए से भरपूर कीवी आंखों की रौशनी को तेजी से बढ़ाता है। ल्यूटिन और ज़ेक्सैंथिन से भरपूर यह फल एंटीऑक्सिडेंट का बेहतरीन सोर्स है। यह फल आंखों के स्वास्थ्य का समर्थन करते हैं।

इम्यूनिटी बनाए मजबूत

जिन लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती उन लोगों को अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए आप कीवी का सेवन करना चाहिए। इसमें मौजूद विटामिन-सी कमजोर इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद करते हैं।

बुखार में फायदेमंद

एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन सी और फाइबर जैसे कई पोषक तत्वों से भरपूर कीवी डेंगू जैसे बुखार में लाभकारी होता है। में प्लेटलेट्स तेजी से कम होने लगता है जिसमें कीवी इन प्लेटलेट्स को बढ़ाने में मदद करती है।

स्किन के लिए फायदेमंद

कीवी में मौजूद विटामिन सी और ई जैसे एंटीऑक्सीडेंट त्वचा को ऑक्सीडेटिव डैमेज से बचाते हैं। साथ ही कोलेजन को बढ़ावा देते हैं, और युवा त्वचा को बनाए रखने में मदद करते हैं।

हृदय के लिए लाभकारी

कीवी में मौजूद पोटेशियम ब्लड प्रेशर को नियंत्रित कर हृदय संबंधी कार्य को बनाए रखने में मदद करता है, जिससे हृदय रोग का खतरा कम हो जाता है।

कब्ज करे दूर

अगर आप कब्ज के मरीज हैं तो रोज़ाना 2 से 3 कीवी का सेवन करें। कब्ज की समस्या को दूर करने में कीवी लाभकारी है।

कब करें कीवी का सेवन?

कीवी का सेवन दोपहर या शाम की बजाय सुबह 10 से 12 के बीच करें। कीवी में भरपूर मात्रा में पोषक तत्व पाए जाते हैं जो सेहत की बेहतरीन देखभाल करते हैं। आप इसे खाली पेट भी खा सकते हैं। हालांकि, खाली पेट खट्टा फल खाने से आपको एसिडिटी की समस्या हो सकती है तो इसे खाली पेट खाने की बजाय कुछ नाश्ता कर खाएं।

काजल के इन नए शेड्स

से बेस्ट आई मेकअप लुक पाएं, ब्लैक के अलावा ट्राई करें ये रंग

काजल एक ऐसा मेकअप प्रोडक्ट है जो हर महिला के मेकअप बैग का जरूरी हिस्सा बन चुका है। यह आंखों को आकर्षक और बड़ी दिखाने के लिए बेहद फायदेमंद है, लेकिन क्या आप सिर्फ ब्लैक काजल तक ही सीमित हैं? अगर हां, तो अब समय है अपने आई मेकअप रूटीन में कुछ नया जोड़ने का। इस लेख में हम आपको काजल के कुछ ऐसे डिज़ाइंस और शेड्स के बारे में बताएंगे, जिन्हें आप अपनी वैनिटी में जरूर शामिल करना चाहेंगी।

डबल कलर काजल

डबल कलर काजल लुक आजकल बेहद पॉपुलर है। यह काजल का डिज़ाइन ना सिर्फ आंखों को आकर्षक बनाता है, बल्कि बहुत ही कूल और स्टाइलिश भी लगता है। इस लुक को आप दोनों आंखों में अलग-अलग रंगों के काजल का इस्तेमाल करके प्राप्त कर सकती हैं। उदाहरण के लिए, आप एक आंख में ग्रीन काजल और दूसरी आंख में पिंक काजल लगा सकती हैं। इस डिज़ाइन को आप वेस्टर्न ड्रेस के साथ बेहद आराम से कैरी कर सकती हैं और किसी पार्टी या फंक्शन में यह आपको खास आकर्षण का केंद्र बना सकता है। इसके अलावा, आप इसके साथ मैचिंग आई शैडो भी यूज कर सकती हैं, ताकि लुक और भी खूबसूरत बने।

ब्रॉड ब्लैक काजल

ब्रॉड ब्लैक काजल एक क्लासिक लुक है, जिसे आप किसी भी अवसर पर पहन सकती हैं। यह लुक आंखों को गहरा और एक्सप्रेसिव बनाता है। आमतौर पर ब्लैक काजल को पतला लगाया जाता है, लेकिन जब इसे ब्रॉड तरीके से लगाया जाता है, तो यह ज्यादा ड्रामेटिक और ग्लैमरस दिखता है। यह खासतौर पर पारंपरिक ड्रेस जैसे साड़ी, सलवार-कुर्ता या किसी भी प्रकार के इंडियन आउटफिट के साथ बहुत अच्छा लगता है। इस लुक को बेहतर बनाने के लिए आप सिल्वर ज्वेलरी और न्यूड बेज लिपस्टिक का इस्तेमाल कर सकती हैं, जो आपके लुक को बैलेंस और एलीगेंट बनाए रखेगी।

कैट आई काजल

कैट आई काजल लुक एक ट्रेंडी और ग्लैमरस डिज़ाइन है, जिसे कई सेलेब्स और स्टाइलिश महिलाएं अपने लुक को एलेवेट करने के लिए अपनाती हैं। इस लुक में काजल को आंखों के बाहरी कोने तक फैलाया जाता है, जिससे आंखों का आकार और ज्यादा बड़ा और सेक्सी नजर आता है। इस लुक के लिए आप ग्रीन, ब्लू या रेड काजल का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। कैट आई काजल के साथ न्यूड लिप्स और हल्के आई शैडो का इस्तेमाल करें ताकि काजल और लुक दोनों को पूरी तरह से हाईलाइट किया जा सके। यह लुक खासकर वेस्टर्न कपड़ों के साथ बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसे पारंपरिक ड्रेस के साथ भी अपनाया जा सकता है।

स्मोकी काजल

स्मोकी काजल लुक एक और खूबसूरत और सेक्सी आई मेकअप स्टाइल है। इसमें काजल को आंखों के बाहरी कोने से अंदर की ओर अच्छे से स्मज किया जाता है, जिससे एक स्मोकी और ड्रामेटिक लुक मिलता है। यह लुक नाइट पार्टीज, डेट नाइट्स या किसी खास अवसर के लिए परफेक्ट होता है। इस लुक को आप ब्लैक, ब्राउन या पर्पल काजल के साथ बना सकती हैं। इसके बाद हल्के आई शैडो से स्मज करें और वॉटरप्रूफ मस्कारा लगाएं, जिससे आपका लुक पूरे दिन सही रहे।

कलर्ड काजल

आजकल मार्केट में बहुत सारे कलर्ड काजल उपलब्ध हैं, जैसे पिंक, गोल्ड, पर्पल, ब्लू और ग्रीन। कलर्ड काजल न सिर्फ आंखों को फ्रेश और यंग लुक देता है, बल्कि यह आपके लुक को भी एक अलग ही डिमेंशन देता है। आप इस काजल को न केवल अपनी आंखों के पानी की लाइन में, बल्कि आंखों के नीचे भी लगा सकती हैं, जिससे आपको एक अलग और यूनिक लुक मिलता है। कलर्ड काजल को आप वेस्टर्न और इंडियन दोनों ही ड्रेस के साथ कैरी कर सकती हैं, और यह किसी भी पार्टी में आपकी आंखों को आकर्षक बना सकता है।

स्मूद और नैचुरल काजल

यदि आप एक नैचुरल लुक चाहती हैं, तो स्मूद और हल्का काजल बेहतर विकल्प हो सकता है। इसे हल्के हाथों से अपनी वाटरलाइन पर लगाकर अपनी आंखों को थोड़ी सी डिफिनिशन दे सकती हैं। यह लुक खासतौर पर उन महिलाओं के लिए है जो एक डेली वियर लुक चाहती हैं, जिसमें बहुत ज्यादा मेकअप न हो। यह काजल हर दिन के लुक के लिए परफेक्ट होता है और इसे किसी भी सादा ड्रेस के साथ कैरी किया जा सकता है।

इन सभी काजल डिज़ाइनों के साथ आप अपने आई मेकअप को नया और ट्रेंडी बना सकती हैं। हर लुक को अपनी पसंद और अवसर के हिसाब से चुनें और अपनी आंखों को और भी खूबसूरत बनाएं।

कमाल का रिजल्ट देता है

मूंगफली का फेस पैक , मिनटों में त्वचा बनेगी मुलायम और चमकदार

सर्दी के दस्तक देते हैं घरों में मूंगफली आनी शुरू हो जाती है। यह सिर्फ सेहत के लिए ही नहीं बल्कि आपके चेहरो के लिए भी काफी फायदेमंद है। भिगोई हुई मूंगफली का फेस पैक बनाकर आप अपनी त्वचा को पोषण दे सकते हैं। मूंगफली में मौजूद विटामिन ई, ओमेगा-3 फैटी एसिड, और एंटीऑक्सीडेंट्स त्वचा को पोषण देकर नमी बनाए रखते हैं और इसे दमकाने में मदद करते हैं। इसे घर पर बनाकर उपयोग करें और महंगे केमिकल प्रोडक्ट्स से बचें। आइए जानते हैं भिगोई हुई मूंगफली से फेस पैक बनाने और उपयोग करने का तरीका।

भिगोई हुई मूंगफली से फेस पैक बनाने की विधि

- मूंगफली को 5-6 घंटे या रातभर पानी में भिगो दें।
- भीगी हुई मूंगफली को मिक्सर में डालकर बारीक पेस्ट बना लें।
- इसमें शहद और दूध (या दही) मिलाएं। यदि चाहें तो कुछ बूंदें गुलाबजल भी मिला सकते हैं।
- इस पेस्ट को अच्छी तरह से मिलाकर स्मूद फेस पैक तैयार करें।
- तैयार फेस पैक को पूरे चेहरे और गर्दन पर समान रूप से लगाएं।
- 15-20 मिनट तक इसे सूखने दें, हल्के गुनगुने पानी से चेहरे को मसाज करते हुए पैक हटाएं।
- अंत में चेहरे को ताजे पानी से धो लें और मॉइश्चराइज़र लगाएं।

मूंगफली फेस पैक के फायदे

- मूंगफली में मौजूद प्राकृतिक तेल त्वचा को गहराई से मॉइश्चराइज़ करता है।
- मूंगफली के छोटे कण स्क्रब की तरह काम करते हैं, जो डेड स्किन सेल्स को हटाकर त्वचा को साफ और चमकदार बनाते हैं।
- इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स त्वचा की उम्र बढ़ने के लक्षणों को कम करने में मदद करते हैं।
- मूंगफली में मौजूद फैटी एसिड त्वचा को पोषण देकर एक्ने और दाग-धब्बे कम करने में सहायक होते हैं।
- दूध या दही त्वचा को मुलायम और लचीला बनाता है।

सावधानियां

1. मूंगफली से एलर्जी होने पर इस फेस पैक का उपयोग न करें।
2. हमेशा फेस पैक को ताजा बनाएं और तुरंत इस्तेमाल करें।
3. सप्ताह में 1-2 बार इसका उपयोग करें।
4. इस्तेमाल से पहले चेहरे पर पैच टेस्ट जरूर करें।

घर पर बनाएं आंवले खट्टी-मिठी डाइजेस्टिव गोली

आंवला एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन सी से भरपूर होता है। आंवला इम्यूनिटी बूस्ट करने में कारगर साबित हो सकता है। आंवले के सेवन से हेल्थ ठीक रहती है। आंवले का जूस पीने से शरीर हेल्दी है। आंवले को डाइट में शामिल करने से पाचन संबंधी समस्याओं में लाभदायक होता है। आप भी अपने घर पर बेहद आसान तरीके से डाइजेस्टिव खट्टी-मीठी गोलियां बनाएं। इसे बच्चे से लेकर बड़े भी खूब खाना पसंद करेंगे।

आंवले की खट्टी-मीठी गोली बनाने के लिए सामग्री

- 500 ग्राम आंवला
- एक कप गुड़
- सेंधा नमक स्वादानुसार
- काला नमक एक चम्मच
- काली मिर्च पाउडर एक चम्मच
- भुना जीरा एक चम्मच
- आधा कप पिसी चीनी
- एक चौथाई चम्मच हींग
- नींबू का रस

आंवले की खट्टी-मीठी गोली बनाने की विधि

- इसके लिए आप आंवले को अच्छे से धो लें। इसके बाद कूकर में उबाल लें।
- उबले आंवले को कूकर से निकालें और ठंडा होने के लिए रख दें। जब ये ठंडे हो जाएं तो आवले की गुठली को निकाल दें।
- अब आप आंवलों को मिक्सी में डालकर पीस लें और पेस्ट तैयार कर लें। ध्यान रहे कि आंवला बारीक पीसा हुआ। पीसने में पानी का थोड़ा इस्तेमाल करें।
- इसके बाद पैन गर्म करें और एक कप गुड़ डालें। इसके साथ ही पिसा हुआ आंवले का पेस्ट भी जरुर डालें।
- धीरे-धीरे मिक्स करते हुए आप इसे भूनें। गैस को धीमा ही रखें फिर अब इसमें सारे मसाले डाल दें। भुना हुआ जीरा, काली मिर्च, हींग, काला नमक, सेंधा नमक सब डाल दें, फिर इसे अच्छे से भूनें।
- आप इसे जब तक चलाएं कि ये गाढ़ा ना हो जाए। जब गाढ़ा हो जाए तो इक्ट्ठा तो गैस को बंद कर दें और इसे ठंडा होने दें।
- प्लेट पर पिसी चीनी डालें और तैयार आंवले की छोटी गोली बनाएं और पिसी चीनी को इस पर लपेटें।
- तैयार है आपकी डाइजेस्टिव खट्टी-मीठी आंवले की गोली।

सेहत के लिए वरदान औषधीय गुणों से भरपूर ये फल

शरीफे को सीताफल के नाम से भी जाना जाता है। अंग्रेजी में इस फल का नाम कस्टर्ड एप्पल है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस फल में एक से बढ़कर एक औषधीय गुणों को अच्छी खासी मात्रा पाई जाती है। यही वजह है कि इस फल को ओवरऑल हेल्थ के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद माना जाता है। शरीफे में विटामिन सी, पोटैशियम, विटामिन ए, कॉपर, फॉस्फोरस, फाइबर और कैल्शियम जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। आइए इस फल से मिलने वाले कुछ कमाल के हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में जानते हैं।

फैट बर्न करने में कारगर

अगर आप अपने बढ़ते हुए वेट पर काबू पाना चाहते हैं तो इस फल का सेवन करना शुरू कर दीजिए। पेट की चर्बी को कम करने के लिए इस फल को खाने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा शरीफे में पाए जाने वाले तमाम तत्व आपकी गट हेल्थ को भी सुधार सकते हैं। पेट से जुड़ी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए इस फल का सेवन किया जा सकता है।

कंट्रोल करे बीपी-शुगर

इस फल को खाकर आप अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। यही वजह है कि इस फल को हार्ट के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद माना जाता है। इतना ही नहीं इस फल में पाए जाने वाले तत्व आपके ब्लड शुगर लेवल को काबू करने में भी कारगर साबित हो सकते हैं। यानी शरीफे को सही तरीके से और सही मात्रा में कंज्यूम कर डायबिटीज को मैनेज करने में भी मदद मिल सकती है।

इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाए

रेगुलरली इस फल का सेवन कर आप अपने इम्यून सिस्टम को काफी हद तक इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके अलावा शरीफा आपके दिमाग को तेज और मजबूत बना सकता है। इस फल का सेवन कर आप अपनी बोन हेल्थ को भी काफी हद तक स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। शरीफे में पाए जाने वाले तत्व आपकी सेहत के साथ-साथ आपकी स्किन के लिए भी वरदान साबित हो सकते हैं।

इन दालों के ज़्यादा सेवन से बढ़ सकती है पेट में गैस की समस्या

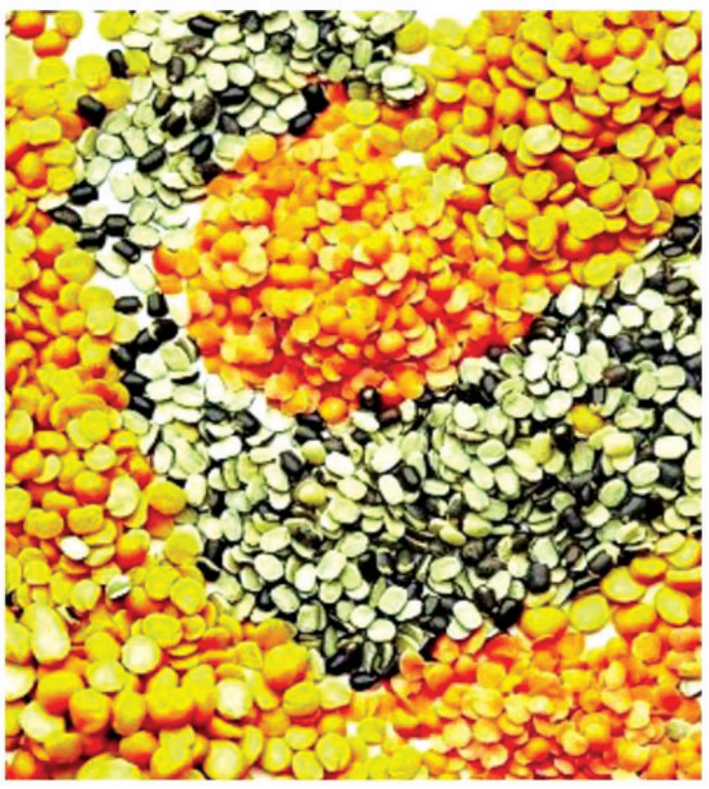

ज़्यादातर लोगों को खाने के बाद पेट फूलने या ब्लोटिंग की समस्या होने लगती है। पेट फूलने के बाद कई बार खट्टी डकार या जलन होने लगती है। ऐसी स्थिति में लोग बेहद परेशान हो जाते हैं। बता दें ब्लोटिंग या गैस के पीछे दाल का सेवन भी हो सकता है। आपको जानकर हैरानी होगी लेकिन कुछ दाल का सेवन करने से पेट में गैस बनने लगती है। ऐसे में जो लोग ब्लोटिंग या गैस की समस्या से पपरेशान होते हैं उन्हें इन दालों का सेवन नहीं करना चाहिए। चलिए हम आपको बताते हैं पेट को फूलने से बचाने के लिए आपको किन दाल को नहीं खाना चाहिए?

चना दाल

चने की दाल सेहत के लिए बेहद फायदेमंद है। लेकिनप्रोटीन और फाइबर से भरपूर यह दाल पेट में गैस बनाती है और ब्लोटिंग की समस्या को तेजी से बढ़ाती है। ऐसे में जिन लोगों को गैस की समस्या होती है उन्हें इस दाल को कम खाने की सलाह दी जाती है।

उड़द की दाल

गैस की संसय से परेशान लोगों को काली उड़द की दाल नहीं खानी चाहिए। यह दाल आसानी से पचती नहीं है। ऐसी में इस दाल का सेवन करने से कब्ज, पेट में गैस, ब्लोटिंग की परेशानी हो सकती है।

मसूर की दाल

मसूर दाल भी पेट की कई परेशानियों का कारण बनती है। इसे खाने से ब्लोटिंग और गैस की समस्या बढ़ सकती है।

गैस की समस्या से छुटकारा पाने के लिए इन चीज़ों का भी रखें ध्यान-

खाना चबाकर खाएं-खाने के छोटे-छोटे टुकड़े बड़े टुकड़ों की तुलना में पचाने में आसान होते हैं, जिससे यह संभावना कम हो जाती है कि रात का खाना आपके पेट में ज़्यादा देर तक रहेगा।

हाइड्रेटेड रहें-आपको गैस और ब्लोटिंग का सामना न करना पड़े इसलिए अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखें। ज़्यादा पानी पीने से आपके जीआई ट्रैक्ट में चीज़ें ठीक से काम करती हैं।

ज़्यादा न खाएँ- बहुत ज़्यादा खाने से पाचन तंत्र ओवरलोड हो जाता है इसलिए खानपान में होने वाले बदलावों के प्रति सचेत रहें। आपका शरीर एक हद तक आपके खाने के हिसाब से खुद को ढाल लेता है। लेकिन अगर आप अचानक अलग-अलग तरह के खाद्य पदार्थ खाने लगते हैं, तो पाचन तंत्र इस बदलाव को संभालने में संघर्ष करता है।

दाल में घी मिलाकर खाना चाहिए या फिर नहीं

घी में पाए जाने वाले तमाम पौष्टिक तत्व आपकी ओवरऑल हेल्थ को काफी हद तक बूस्ट कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि घी को डाइट में शामिल करने का सही तरीका क्या है? कुछ लोग रोटी में घी लगाकर खाते हैं, तो कुछ लोग दाल में घी मिक्स कर खाना पसंद करते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आयुर्वेद के मुताबिक दाल में घी मिलाकर सेवन करना आपकी सेहत के लिए ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। दाल में महज एक चम्मच घी मिलाकर खाएं और खुद-ब-खुद पॉजिटिव असर देखें।

अगर आप दाल में घी डालकर खाएंगे तो आपकी गट हेल्थ को काफी हद तक सुधारा जा सकता है। कब्ज और अपच जैसी पेट से जुड़ी बीमारियों को दूर करने के लिए इस तरह से घी का सेवन किया जा सकता है। सही मात्रा में घी कंज्यूम करने से आप अपनी वेट लॉस जर्नी को भी आसान बना सकते हैं। दाल में घी मिक्स कर खाने से आपकी हड्डियों को मजबूती मिलेगी जिससे आप जोड़ों के दर्द की समस्या का शिकार बनने से बच सकते हैं।

मजबूत बनाए इम्यून सिस्टम

अगर आपकी इम्यूनिटी कमजोर है तो आपको दाल में घी मिक्स करके जरूर खाना चाहिए। इस तरीके से घी को अपने डाइट प्लान में शामिल करके आप अपने इम्यून सिस्टम को काफी हद तक मजबूत बना सकते हैं। दिल की सेहत के लिए भी घी में पाए जाने वाले तत्व फायदेमंद साबित हो सकते हैं। शरीर की थकान और कमजोरी दूर करने के लिए भी घी को दाल में मिलाकर कंज्यूम किया जा सकता है।

गौर करने वाली बात

घी आपकी ब्रेन हेल्थ को भी इम्प्रूव कर सकता है। हालांकि, बेहतर परिणाम हासिल करने के लिए घी को लिमिटेड मात्रा में ही कंज्यूम करना चाहिए। इसके अलावा आपको घी की शुद्धता की जांच भी कर लेनी चाहिए। मिलावटी घी कंज्यूम करने से आपकी सेहत पर पॉजिटिव की जगह नेगेटिव असर भी पड़ सकता है।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

धनखड़ के खिलाफ विपक्ष ने पेश किया अविश्वास प्रस्ताव

नईदिल्ली। विपक्ष ने मंगलवार को उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया, जिससे यह भारत के संसदीय इतिहास में इस तरह की पहली कार्रवाई बन गई। सूत्रों के अनुसार, इस प्रस्ताव पर 71 सांसदों ने हस्ताक्षर किये। सभी इंडिया ब्लॉक पार्टियों द्वारा हस्ताक्षरित, जिसमें समाजवादी पार्टी भी शामिल हैं। हालांकि, टीएमसी ने वॉकआउट कर लिया। बताया जा रहा है कि टीएमसी ने इसपर कोई फैसला नहीं लिया है। हालाँकि, तकनीकी रूप से इस सत्र में प्रस्ताव को मंजूरी मिलना संभव नहीं है क्योंकि इसके लिए 14 दिन के नोटिस की आवश्यकता होती है और शीतकालीन सत्र समाप्त होने में केवल 8 दिन बचे हैं। धनखड़ लगातार विपक्षी गुट के नेताओं को राज्यसभा में उनके आचरण और लगातार व्यवधानों के साथ सदन को चलने नहीं देने के लिए फटकार लगाते रहे हैं। इस बीच, कई विपक्षी सांसदों ने मंगलवार को संसद परिसर में अदानी मुद्दे पर प्रदर्शन किया।

राहुल गांधी पर किरेन रिजिजू का तंज

नईदिल्ली। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने मंगलवार को कांग्रेस नेता और विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर उस वक्त निशाना साधा, जब उनकी पार्टी ने सोमवार को एडमैटर को लेकर संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। किरेन रिजिजू ने एक्स पर लिखा कि राहुल गांधी को तमाशा करने और प्रधानमंत्री को गाली देने में आनंद आता है लेकिन अन्य सांसदों के लिए उन लोगों के प्रति जिम्मेदारियां हैं जिन्होंने उन्हें चुना है। उसे बस यहां तमाशा करना है और फिर अपनी छुट्टियों का आनंद लेने के लिए विदेश जाना है। एक अन्य पोस्ट में, रिजिजू ने संसद के बाहर राहुल गांधी के विरोध प्रदर्शन का वीडियो पोस्ट किया और उद्धृत किया कि कांग्रेस नेता को लोगों की समस्याओं की परवाह नहीं है क्योंकि उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। उन्होंने लिखा कि समाजवादी पार्टी, टीएमसी, राज्यसभा में सभी कांग्रेस सांसद, लोकसभा में कुछ कांग्रेस सांसद और कई पार्टी सांसद वास्तव में संसद की बहस और चर्चा में भाग लेने के इच्छुक हैं।

दिल्ली दंगे के आरोपी ताहिर हुसैन को ओवैसी ने दिया टिकट

नईदिल्ली। असदुद्दीन ओवैसी की ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहाद-उल-मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) ने आगामी दिल्ली चुनाव में मुस्तफाबाद निर्वाचन क्षेत्र से निष्कासित आप पार्षद ताहिर हुसैन की उम्मीदवारी की घोषणा की। हुसैन को 2020 के दिल्ली दंगों से संबंधित आरोपों का सामना करना पड़ा था। ओवैसी ने इस कदम की पुष्टि करते हुए कहा कि एमसीडी पार्षद ताहिर हुसैन एआईएमआईएम में शामिल हो गए और आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव में मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र से हमारे उम्मीदवार होंगे। इस घोषणा की भाजपा नेता कपिल मिश्रा ने आलोचना की है। उन्होंने कहा कि ओवैसी ने खुद को अंकित शर्मा की हत्या के लिए जिम्मेदार व्यक्ति के साथ जोड़ लिया है, जिसके घर में बम और पत्थर पाए गए थे और जिसने दिल्ली में सैकड़ों हिंदुओं को मारने का प्रयास किया था। उन्होंने आगे कहा कि ओवैसी को याद रखना चाहिए कि अगर ताहिर हुसैन के नाम पर दिल्ली में एक और दंगा हुआ तो उसका परिणाम उनकी सात पीढ़ियां याद रखेंगी।

आम आदमी पार्टी ने क्यों बदली मनीष सिसोदिया की सीट?

नईदिल्ली। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले एक उल्लेखनीय घटनाक्रम में आम आदमी पार्टी के कद्दावर नेता, पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जंगपुरा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। इससे पहले वह लगातार पटपड़गंज से जीतते आ रहे हैं। हालांकि, पार्टी ने इस बार उनके सीट को बदल दिया है। इस बदलाव के पीछे कई बड़ी वजह बताई जा रही है। 2013 से सिसौदिया द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाने वाला पटपड़गंज आप के लिए महत्वपूर्ण चुनावी जीत का स्थल रहा है। हालाँकि, उनकी हालिया कानूनी परेशानियों, विशेष रूप से दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले के संबंध में, ने पार्टी की रणनीति को प्रभावित किया होगा। जमानत मिलने से पहले सिसोदिया ने कई महीने हिरासत में बिताए, जिससे उनकी अपने पूर्व निर्वाचन क्षेत्र में वापसी पर संकट मंडरा रहा था। आप के अंदरूनी सूत्रों का सुझाव है कि यह कदम सत्ता विरोधी लहर से निपटने और पूरी दिल्ली में अपनी स्थिति मजबूत करने की एक बड़ी चुनावी रणनीति का हिस्सा है।

14 दिसंबर को हो सकता है महायुति कैबिनेट का विस्तार

मुंबई। मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस की सरकार द्वारा 9 दिसंबर को महाराष्ट्र विधानसभा में विश्वास मत हासिल करने के बाद, अब सभी की निगाहें महायुति गठबंधन के बहुप्रतीक्षित कैबिनेट विस्तार पर हैं। 16 दिसंबर से शुरू होने वाले शीतकालीन विधानसभा सत्र से पहले 14 दिसंबर को विस्तार की घोषणा होने की उम्मीद है। सूत्र बताते हैं कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) का केंद्रीय नेतृत्व नए मंत्रिमंडल के लिए स्वच्छ छवि बनाए रखने पर कायम है। सूत्रों के मुताबिक ऐसी अटकलें हैं कि पिछली कैबिनेट में कई दिग्गज नामों को उनके खराब प्रदर्शन और प्रतिष्ठा के कारण बाहर किया जा सकता है। महाराष्ट्र में आगामी महायुति गठबंधन कैबिनेट विस्तार में कई मौजूदा मंत्रियों को उनके कथित खराब प्रदर्शन या खराब प्रतिष्ठा के कारण बाहर किए जाने की उम्मीद है। शिवसेना (एकनाथ शिंदे गुट) से तीन प्रमुख मंत्रियों को हटाए जाने की संभावना है।

कांग्रेस को राष्ट्रीय जनता दल ने दे दिया गच्चा

ममता बनर्जी को दी जाए इंडिया गठबंधन की कमान : लालू

पटना। राजद प्रमुख लालू प्रसाद ने मंगलवार को कहा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी को इंडिया ब्लॉक का नेतृत्व करने की अनुमति दी जानी चाहिए। उनकी यह टिप्पणी बनर्जी द्वारा भाजपा विरोधी गठबंधन की कमान संभालने की मंशा व्यक्त करने के कुछ दिनों बाद आई है। प्रसाद ने यह भी कहा कि अगर इंडिया ब्लॉक की एक प्रमुख सहयोगी कांग्रेस को बनर्जी को विपक्षी मोर्चे के नेता के रूप में स्वीकार करने में कोई आपत्ति है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।

राजद प्रमुख ने कहा कि ममता बनर्जी को इंडिया ब्लॉक का नेतृत्व करने की अनुमति दी जानी चाहिए। विपक्षी गुट के नेता के रूप में उन्हें स्वीकार करने के लिए कांग्रेस के आरक्षण के बारे में पूछे जाने पर, लालू ने कहा कि कांग्रेस के विरोध से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उन्हें इंडिया गुट का नेतृत्व करने की अनुमति दी जानी चाहिए। इससे पहले, लालू के बेटे और वरिष्ठ राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा था कि उन्हें बनर्जी सहित इंडिया गुट के किसी भी वरिष्ठ नेता के गठबंधन का नेतृत्व करने पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इस बात पर जोर दिया कि निर्णय आम सहमति से होना चाहिए। महाराष्ट्र और हरियाणा में कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन की हार के बाद खलबली मची हुई है। टीएमसी और ममता बनर्जी इसके लिए कांग्रेस पर सवाल खड़े कर रही है। टीएमसी का दावा है कि ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करना चाहिए। इसी को लेकर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद इंडिया ब्लॉक की कोई बैठक नहीं हुई है, इसलिए नेतृत्व परिवर्तन का सवाल ही नहीं उठता। एक बैठक होने दीजिए और अगर ममता बनर्जी चाहें तो उन्हें नेतृत्व का दावा करने दीजिए। इस बारे में कोई चर्चा नहीं हुई है।

लालू के बयान के बाद शिवसेना-यूबीटी ने कही विचार करने की बात

मुंबई। सत्तासीन एनडीए को चुनौती देने के लिए बना इंडिया गठबंधन अब तक पूरी तरह एक साथ नहीं जुट पाया है। ऐसे में अब इस गठबंधन में कांग्रेस के नेतृत्व को लेकर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। हाल ही में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की नेता ममता बनर्जी ने इस गठबंधन के नेतृत्व की इच्छा जताई थी। इसके बाद से ही इंडिया के अधिकतर राजनीतिक दलों के नेताओं ने इस पर गंभीरता से विचार करने की बात कही है। गठबंधन में सहयोगी दल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) के अध्यक्ष शरद पवार ने समर्थन करते हुए ममता बनर्जी को एक सक्षम नेता बताया है। वहीं विपक्षी गठबंधन के एक अन्य घटक राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेता तेजस्वी यादव ने इस संबंध में आम सहमति पर जोर दिया। शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे के नेता और सांसद संजय राउत ने मंगलवार को इंडिया गठबंधन के नेतृत्व के सवाल पर कहा, राहुल गांधी के नेतृत्व पर कोई सवाल नहीं उठा रहा है। वे हम सबके नेता हैं। इंडिया गठबंधन के बारे में अगर हमारे कुछ साथी चाहे तृणमूल हो, चाहे लालू जी, अखिलेश जी हो, उनकी एक अलग राय बनती है। हम सबने मिलकर इंडिया गठबंधन बनाया है। अगर कोई नई बात रखना चाहता है और इंडिया गठबंधन को ताकत देना चाहता है, तो उसपर विचार होनी चाहिए।

अडानी-सोरोस मुद्दे पर भाजपा-कांग्रेस में टकराव

■ नहीं चल सके दोनों सदन

नईदिल्ली। संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है। हालांकि, शीतकालीन सत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच संग्राम जबरदस्त तरीके से देखने को मिल रहा है। इस संग्राम की वजह से दोनों सदनों की कार्यवाही नियमित नहीं चल पा रही है। आज भी सोरोस और अडानी मुद्दे पर दोनों सदनों में हंगामा हुआ जिसकी वजह से दोनों सदनों के कार्यवाही को दिन भर के लिए स्थगित करना पड़ा। राज्यसभा में मंगलवार को पूर्व विदेश मंत्री एस एम कृष्णा के निधन पर शोक वयक्त किया गया और उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहे कृष्णा का सोमवार को देर रात बेंगलुरू स्थित उनके आवास पर निधन हो गया। विपक्षी गठबंधन (इंडिया) के कई घटक दलों के सांसदों ने अदाणी समूह से जुड़े मुद्दे पर मंगलवार को काले रंगे के झोले लेकर विरोध प्रदर्शन किया।

लोकसभा की कार्यवाही

लोकसभा में विभिन्न मुद्दों पर विपक्षी सदस्यों के शोर-शराबे के कारण मंगलवार को भी प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं चल सका और कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद दोपहर करीब 12.17 बजे दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद परिसर में कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों के विरोध प्रदर्शन के तौर-तरीकों को अशोभनीय तथा प्रतिपक्ष के बड़े नेताओं के आचरण को संसदीय परंपराओं को प्रतिकूल बताया और कहा कि सभी को संसद की गरिमा, मर्यादा और प्रतिष्ठा को बनाए रखना चाहिए।

दोपहर 12 बजे सदन की बैठक पुन: शुरू होने पर पीठासीन सभापति दिलीप सैकिया ने आवश्यक कागजात सदन के पटल पर प्रस्तुत कराए। केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्वानंद

सोनोवाल ने 'वाणिज्य पोत परिवहन विधेयक, 2024' हंगामे के बीच ही प्रस्तुत किया। सैकिया ने विपक्ष के सदस्यों से कार्यवाही चलने देने का आग्रह करते हुए कहा, ''आपके कारण सदन नहीं चल रहा, ऐसा संदेश नहीं जाना चाहिए।'' संसदीय कार्य मंत्री किरेन रीजीजू ने कांग्रेस को आड़े हाथ लेते हुए कहा, ''आपके शर्मनाक व्यवहार की वजह से सदन की गरिमा को ठेस पहुंची है, इसके लिए आपको माफी मांगनी चाहिए।'' उन्होंने कहा कि कांग्रेस के अमेरिकी कारोबारी जॉर्ज सोरोस और देश विरोधी ताकतों से क्या रिश्ते हैं, पता चलना चाहिए और इसके लिए विपक्षी दल को सदन में माफी मांगनी चाहिए।

राज्यसभा की कार्यवाही

विपक्षी गठबंधन 'इंडिया' के घटक दलों ने जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति पद से हटाने के लिए प्रस्ताव लाने संबंधी नोटिस मंगलवार को सौंप दिया। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने संसद परिसर में संवाददाताओं को बताया कि करीब 60 सांसदों के हस्ताक्षर वाला नोटिस राज्यसभा सभापति के सचिवालय को दिया गया है। सूत्रों का कहना है कि विपक्षी दलों ने नोटिस देने के लिए अगस्त में ही जरूरी संख्या में हस्ताक्षर ले लिए थे, लेकिन वे आगे नहीं बढ़े क्योंकि उन्होंने धनखड़ को ''एक और मौका देने'' का फैसला किया था, लेकिन सोमवार के उनके आचरण को देखते हुए विपक्ष ने इस पर आगे बढ़ने का फैसला किया।

राज्यसभा में मंगलवार को सत्ता पक्ष और विपक्ष ने सोरोस और अदाणी के मुद्दों पर जोरदार हंगामा किया, जिसके बाद उच्च सदन की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के सदस्यों ने कांग्रेस तथा उसके नेताओं पर विदेशी संगठनों और लोगों के माध्यम से देश की सरकार तथा अर्थव्यवस्था को अस्थिर करने की कोशिश का आरोप लगाया और इस मुद्दे पर चर्चा कराने की मांग करते हुए हंगामा किया। कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्ष ने अदाणी समूह से जुड़ा मुद्दा उठाते हुए इस पर चर्चा कराने की मांग की और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तथा सरकार के खिलाफ नारेबाजी की।

बिरला ने सांसदों को दी मर्यादा बनाए रखने की नसीहत

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मंलगवार को सदन में कहा कि संसद एक पवित्र स्थल है। इस भवन की उच्च गरिमा, प्रतिष्ठा और मर्यादा है। इसी भवन में हमने आजादी प्राप्त की है। यह दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की सर्वोच्च प्रतिनिधि संस्था है। इस संस्था में लोगों की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं को पूरा किया जाता है। सहमति-असहमित हमारे लोकतंत्र की परंपरा रही है, जो संविधान बनते समय भी हमने अभिव्यक्त की थी।

उन्होंने कहा, मेरा आपसे आग्रह है कि हमें संसद की गरिमा बनाए रखनी चाहिए। पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं कि संसद परिसर में जिस प्रकार के प्रदर्शन किए जा रहे हैं, जिस प्रकार के नारे, पोस्टर और मुखौटों का उपयोग किया जा रहा है, वह न सिर्फ अशोभनीय है, बल्कि हमारी नियम प्रक्रियाओं और संसदीय परंपराओं के अनुरूप भी नहीं है। मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इसमें प्रतिपक्ष के बड़े नेताओं का आचरण-व्यवहार भी संसदीय व्यवहार के अनुकूल नहीं है।

इस पर कांग्रेस और कुछ विपक्षी दलों के सदस्यों ने टोका-टोकी करते हुए कहा कि अध्यक्ष को सत्तापक्ष का भी नाम लेना चाहिए। इस पर बिरला ने कहा कि चाहे सत्तापक्ष हो या प्रतिपक्ष हो, सभी दलों के लोग संसद की गरिमा, परंपरा, मर्यादा और प्रतिष्ठा को बनाए रखें। मर्यादित आचरण रखेंगे तो जनता में सकारात्मक संदेश जाएगा। इस लोकतंत्र के मंदिर के प्रति लोगों की बहुत गहरी आस्था और विश्वास है। आजादी के 75 वर्ष में हमने यहां चर्चा, संवाद और तीखी आलोचना देखी है। यह यहां की परंपराएं रही हैं।

उन्होंने सांसदों से अपील की कि आप सकारात्मक सहयोग करें। जो मुद्दे हैं, उन पर आप आकर चर्चा करें। सत्तापक्ष से प्रतिपक्ष के लोग बैठकर चर्चा करें, सदन को चलाने का प्रयास करें। प्रश्नकाल का महत्वपूर्ण समय होता है। मुझे आशा है कि आप सकारात्मक सहयोग करेंगे।

इससे पहले विपक्षी नेताओं ने काले रंग का झोला लेकर संसद भवन परिसर में प्रदर्शन किया। झोले पर उद्योगपति गौतम अदाणी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर बनी हुई थी। इससे एक दिन पहले ही नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पीएम मोदी और अदाणी का मुखौटा पहने दो कांग्रेस सांसदों का प्रतीकात्मक साक्षात्कार करते हुए सरकार और प्रधानमंत्री पर निशाना साधा था। कांग्रेस सांसद शिवाजी कलगे ने प्रधानमंत्री मोदी और मणिकम टैगोर ने गौतम अदाणी का मुखौटा पहन रखा था। कांग्रेस अदाणी समूह के मामले पर सदन में चर्चा करने और जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) गठित करने की मांग कर रही है।

खेल
प्रमुख समाचार

ऑस्ट्रेलिया से क्लीन स्वीप से बचने की कोशिश करेगा भारत

नईदिल्ली। पहले दो मैच में करारी हार से आहत भारतीय महिला टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बुधवार को यहां होने वाले तीसरे और अंतिम एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में क्लीन स्वीप से बचने और अगले साल होने वाले 50 ओवरों के विश्व कप से पहले अपनी कमजोरियों को दूर करने की कोशिश करेगी।

सात बार के विश्व चैंपियन आस्ट्रेलिया ने अभी तक तीन मैच की श्रृंखला में पूरी तरह से दबदबा बनाए रखा है जबकि भारत ने तीनों विभाग बल्लेबाजी, गेंदबाजी और क्षेत्ररक्षण में खराब प्रदर्शन किया है। दूसरे वनडे में रिकॉर्ड 122 रन की हार से भारत की कमजोरी का पता चलता है। इस मैच में भारतीय बल्लेबाजों ने टुकड़ों में अच्छा प्रदर्शन किया लेकिन टीम किसी भी समय 372 रन के लक्ष्य तक पहुंचने की स्थिति में नहीं दिखी।

भारत को सबसे अधिक निराश उसकी दो स्टार बल्लेबाजों कप्तान हरमनप्रीत कौर और उप कप्तान स्मृति मंधाना ने किया है। मंधाना ने अक्टूबर में न्यूजीलैंड के खिलाफ शतक जड़ा था लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले दो मैच में वह केवल 17 रन ही बना पाई है। इस सलामी बल्लेबाज की निगाह फॉर्म में लौटने पर टिकी होगी। हरमनप्रीत अपनी अच्छी शुरुआत को बड़े स्कोर में बदलने में नाकाम रही है। उन्होंने दो मैच में 57 रन बनाए हैं।

भारतीय टीम इस साल के शुरू में टी20 विश्व कप मेंजल्दी बाहर हो गया था और तब से हरमनप्रीत की बल्लेबाजी और कप्तानी पर नजर रखी जा रही है। लगातार खराब प्रदर्शन के कारण टीम से बाहर की गई शेफाली वर्मा की अनुपस्थिति में भारतीय टीम ने कुछ अलग संयोजन आजमाए लेकिन उसकी तरफ से अभी तक रिचा घोष ही अच्छा प्रदर्शन कर पाई है। रिचा ने दूसरे वनडे में 54 रन बनाए जो वर्तमान श्रृंखला में किसी भारतीय बल्लेबाज का सर्वोच्च स्कोर है।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

सेंसेक्स 81,510 और निफ्टी 24,610 पर बंद

नईदिल्ली। एशियाई बाजारों में तेजी के बीच भारतीय शेयर बाजार मंगलवार को मामूली बढ़त के साथ खुले। हालांकि, भारी उठापठक के बाद बाजार लगभग सपाट बंद हुआ। अमेरिकी और भारत के इन्फ्लेशन के आंकड़े जारी होने से पहले निवेशक सतर्क रुख अपना रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये आंकड़े रीपो रेट में कटौती के समय को प्रभावित कर सकते हैं। तीस शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स मंगलवार (10 दिसंबर) को मामूली तेजी के साथ 81,575.96 अंक पर खुला। पूरा दिन हरे और लाल निशान में झूलने के बाद अंत में सेंसेक्स 1.59 अंक की मामूली बढ़त लेकर 81,510 पर बंद हुआ। इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (ह्स्श्व) का निफ्टी-50 भी 0.04 प्रतिशत या 8.95 अंक की मामूली गिरावट लेकर 24,610.05 पर लगभग सपाट बंद हुआ। एक्सपर्ट्स का मानना है कि पिछला सप्ताह अच्छा प्रदर्शन करने के बाद इस सप्ताह बाजार में थोड़ी मायूसी देखी जा रही है।

महंगाई-ग्रोथ में संतुलन बहाल करना आरबीआई के लिए जरुरी

नईदिल्ली। निवर्तमान आरबीआई गवर्नर शक्तिकान्त दास ने कहा कि महंगाई और ग्रोथ में बैलेंस बहाल करना आरबीआई के सामने सबसे जरूरी कार्य है। दास ने अपने फेयरवेल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (सीबीडीसी) में अपार संभावनाएं हैं; यह भविष्य की मुद्रा है। रिजर्व बैंक के 25 वें गवर्नर शक्तिकांत दास का छह वर्ष का कार्यकाल मंगलवार को समाप्त हो रहा है। सोमवार को सरकार ने संजय मल्होत्रा को नया आरबीआई गवर्नर नियुक्त किया है। फिलहाल राजस्व सचिव का पद संभाल रहे मल्होत्रा 11 दिसंबर से पद संभालेंगे। निवर्तमान आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि नए आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा के पास व्यापक अनुभव है, यकीन है कि वह अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे। वित्त मंत्रालय और आरबीआई के बीच पिछले छह वर्षों में समन्वय सबसे बेहतर रहा।

नई आयकर व्यवस्था लागू करने में मल्होत्रा की महत्वपूर्ण भूमिका

नई दिल्ली। आरबीआई के नए गवर्नर संजय मल्होत्रा अपने काम करने के तरीकों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पसंदीदा नौकरशाहों में गिने जाते हैं। उन्होंने 2024 का बजट बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। उनका शुमार वित्तीय मामलों में सुधारवादी और मजबूती से काम करने वाले अफसरों में होता है। आम सहमति बनाने में माहिर मल्होत्रा ने नई आयकर व्यवस्था को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनके पास वित्त से जुड़े कामकाज संभालने का लंबा तजुर्बा है। रिजर्व बैंक का कामकाज सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देखते हैं। मल्होत्रा के पास इसका भी अनुभव है। इसलिए, वह आरबीआई गवर्नर की रेस में सबसे आगे रहे। आरईसी लि. चेयरमैन-एमडी रह चुके मल्होत्रा के के कार्यकाल में वेतनभोगी वर्ग को राहत देने वाली नई प्रत्यक्ष कर व्यवस्था लागू हुई। अप्रत्याशित लाभ कर भी उन्हीं के कार्यकाल में हटाया गया।

नए साल से चार फीसदी तक महंगी होंगी गाड़ियां

नई दिल्ली। उच्च खाद्य महंगाई से परेशान लोगों को नए साल से गाड़ियां खरीदने के लिए जेब अधिक ढीली करनी पड़ेगी। कच्चे माल की लागत और महंगाई में वृद्धि को आंशिक रूप से कम करने के लिए वाहन निर्माता कंपनियां एक जनवरी से गाड़ियों के दाम बढ़ाने जा रही हैं। मारुति सुजुकी इंडिया ने परिचालन खर्च और इनपुट लागत बढ़ने से वाहनों की कीमत चार फीसदी तक बढ़ाने का फैसला किया है। कीमतों में बढ़ोतरी मॉडल के हिसाब से होगी।?हालांकि, लागत का अधिकतर हिस्सा कंपनी खुद वहन करेगी। कंपनी ने कहा, अतिरिक्त खर्चों को वहन करना अब संभव नहीं है। ह्युंडई मोटर इंडिया एक जनवरी से गाड़ियों की कीमत 25,000 रुपये तक बढ़ाएगी। कंपनी के मुख्य परिचालन अधिकारी गर्ग ने कहा, कच्चे माल की बढ़ती कीमतें, रुपये की कमजोरी और महंगे परिवहन की वजह से कीमतों में वृद्धि जरूरी हो गई है।

दुनिया में भारत की बढ़ती अहमियत

डॉ. जयंतीलाल भंडारी

यकीनन दुनिया में भारत की आर्थिक अहमियत बढने के एक के बाद एक नए-नए परिदृश्य उभरकर दिखाई दे रहे हैं। पिछले माह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 से 21 नवंबर तक ब्राजील, नाइजीरिया और गुयाना के पांच दिवसीय दौरे के दौरान जहां जी-20 शिखर सम्मेलन में भुखमरी और गरीबी के खिलाफ एकजुटता विषय पर प्रभावी संबोधन दिया, वहीं नाइजीरिया और गुयाना पहुंचकर इन देशों के साथ व्यापार बढ़ाने की सार्थक वार्ताएं की। यह भी महत्वपूर्ण है कि प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा जी-20 शिखर सम्मेलन से इतर ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, ब्राजील, सिंगापुर, इंडोनेशिया, पुर्तगाल, नॉर्वे और स्पेन समेत कई देशों के नेताओं के साथ की गई 31 द्विपक्षीय और अनौचारिक वार्ताओं में भारत का रणनीतिक महत्व उभरकर दिखाई दिया है। इसमें कोई दो मत नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी भारत के वैश्विक व्यापार और निर्यात बढ़ाने के मद्देनजर विदेश दौरों में द्विपक्षीय व्यापार वार्ताओं की रणनीति लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। खास तौर से पिछले छह महीनों में इस रणनीति से द्विपक्षीय व्यापार के अच्छे अध्याय दिखाई दिए हैं। गत 13 से 15 जून को इटली में विकसित देशों के संगठन जी-7 के शिखर सम्मेलन में विशेष आमंत्रित देश के रूप में भारत की अहमियत दिखाई दी है। इस मौके पर सम्मेलन में शामिल प्रमुख देशों के राष्ट्र प्रमुखों के साथ भारत की द्विपक्षीय वार्ताएं लाभप्रद रही हैं।

भारत के लिए सबसे ठोस लाभ जी-7 की उस प्रतिबद्धता से उपजा, जिसमें कहा गया कि भारत-पश्चिम एशिया-यूरोप आर्थिक गलियारे (आईएमईसी) को बढ़ावा दिया जाएगा। इस गलियारे के निर्माण की घोषणा

गत वर्ष 2023 में भारत में जी-20 शिखर बैठक के समय की गई थी। यह भी कोई छोटी बात नहीं है कि गत 9 जुलाई को 22वें भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में मास्को में भारत और रूस के बीच बहुआयामी संबंधों की संपूर्ण श्रृंखला की समीक्षा के बाद भारत और रूस ने द्विपक्षीय कारोबार को 2030 तक 100 अरब डॉलर तक बढ़ाने, व्यापार में संतुलन लाने, गैर-शुल्क व्यापार बाधाओं को दूर करने और यूरेशियन आर्थिक संघ (ईएईयू)-भारत मुक्त व्यापार क्षेत्र की संभावनाएं तलाशने का लक्ष्य रखा है। दोनों देशों ने राष्ट्रीय मुद्रा का इस्तेमाल कर एक द्विपक्षीय निपटान प्रणाली स्थापित करने और पारस्परिक निपटान प्रक्रिया में डिजिटल वित्तीय उपकरणों को लाने की योजना बनाने की बात कही है। यह बात महत्वपूर्ण है कि मोदी ने जहां 21 सितंबर को अमेरिका में आयोजित क्वाड लीडर्स सम्मेलन में भाग लेकर इस संगठन की भारत के लिए उपयोगिता बढ़ाई, वहीं 22 सितंबर को न्यूयार्क में मोदी और जो बाइडेन के बीच हुई बातचीत में कोलकाता में एक सेमीकंडक्टर प्लांट स्थापित करने का करार हुआ है। इसी प्रकार 10 अक्टूबर को लाओस के वियनतियाने में आयोजित आसियान-भारत शिखर सम्मेलन में आसियान देशों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक के बाद जो बयान जारी किया है, उसके मुताबिक ये देश इस समूचे क्षेत्र में चीन की बढ़ती आक्रमकता से असहज और परेशान हैं तथा भारत के साथ आर्थिक, कारोबारी व सुरक्षा संबंधों का नया दौर आगे बढ़ाएंगे। उल्लेखनीय है कि रूस के कजान में 22 से 24 अक्टूबर तक आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का भारत ने रणनीतिक लाभ लिया। भारत और चीन के बीच पांच साल बाद अहम द्विपक्षीय वार्ता हुई। मोदी ने इस वार्ता के बाद कहा कि भारत और चीन के बीच संबंध महत्वपूर्ण हैं। निस्संदेह दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा और भारत का रणनीतिक महत्व लगातार बढ़ रहा है। 22 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी ने जर्मनी के स्टटगार्ट में आयोजित 'न्यूज-9 ग्लोबल समिट' को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये संबोधित करते हुए कहा कि पूरी दुनिया भारत के रणनीतिक महत्व को स्वीकार कर रही है और यह पिछले 10 वर्षों में अपनाए गए 'सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन' मंत्र के कारण संभव हुआ है। 21वीं सदी में तीव्र विकास के लिए भारत में प्रगतिशील और स्थिर नीति-निर्माण की व्यवस्था लाई गई।

विकसित छत्तीसगढ़ बनाने सहकारिता क्षेत्र की होगी बड़ी भूमिका : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री ने सहकारिता विभाग के चयनित युवाओं को सौंपे नियुक्ति पत्र

रायपुर। हमारी सरकार पूरी पारदर्शिता के साथ शासकीय नौकरियों में भर्तियां कर रही है। पिछले एक साल में ही 9 हजार से अधिक पदों पर हमने भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। प्रदेश के आम युवाओं का सपना अब पूरा हो रहा है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने राजधानी रायपुर के न्यू सर्किट हाउस में सहकारिता विभाग के विभिन्न पदों पर चयनित 334 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपते हुए पारदर्शिता के साथ भर्ती का यह संकल्प दोहराया। उन्होंने चयनित अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं देते हुए कर्तव्यनिष्ठा और ईमानदारी के साथ अपना दायित्व निर्वहन करने के लिए प्रेरित किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने रायगढ़ जिले के तमनार और जशपुर जिले के बगीचा में अपेक्स बैंक की दो नवीन शाखा, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक रायपुर की नवीन शाखा गढ़पुलझर और सिरपुर का वर्चुअल शुभारंभ और अपेक्स बैंक के नवीन शाखा भवन जशपुर का वर्चुअल लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने शहीद वीर नारायण सिंह के बलिदान को नमन करते हुए अपने संबोधन की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि शहीद वीर नारायण सिंह ने अपना सम्पूर्ण जीवन मानव कल्याण के लिए समर्पित किया। उन्होंने अनाज के भंडार लोगों के लिए खोल दिए, परोपकार की यही भावना हम सभी के भीतर होनी चाहिए। साय ने अमूल का उदाहरण देते हुए युवाओं को सहकारिता का महत्व समझाया। उन्होंने कहा कि केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने अपने प्रवास के दौरान सहकारिता को लेकर अमूल्य सुझाव दिये, जिसे हम कार्यान्वित कर रहे हैं। साय ने कहा कि सहकारिता का संबंध किसानों से है और हमें साथ मिलकर उनके जीवन में समृद्धि लानी है। उन्होंने सहकारी और अपेक्स बैंक की नई शाखाएं खुलने पर क्षेत्र के किसानों को अपनी शुभकामनाएं दी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित छत्तीसगढ़ बनाने में सहकारिता की भी बड़ी भूमिका होगी और इसमें आप सभी का योगदान अग्रणी रहेगा। श्री साय ने कहा कि अब प्रदेश के युवाओं के मन में प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर भय या संशय नहीं होना चाहिए, अब किसान, मजदूर के बेटे-बेटियों की प्रतिभा को सम्मान मिलेगा।

सहकारिता का क्षेत्र कितना महत्वपूर्ण है, यह आप सभी को समझना होगाः केदार

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सहकारिता मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि प्रदेश सरकार दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ मोदी की गारंटी को पूरा करने का काम कर रही है। उन्होंने सभी चयनित युवाओं को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सहकारिता का क्षेत्र कितना महत्वपूर्ण है, यह आप सभी को समझना होगा। किसानों के जीवन को खुशहाल बनाने की दिशा में आप सभी काम करें।

1 साल में 19 विभागों में भर्ती प्रक्रिया पारदर्शिता प्रारंभ कर दीः चौधरी

वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने चयनित युवाओं को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि पिछले 1 साल के भीतर 19 विभागों में भर्ती प्रक्रिया पारदर्शिता के साथ प्रारंभ कर दी गई है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार हमारी सरकार पारदर्शिता के साथ अपनी जिम्मेदारी निभा रही है, आप सभी अपनी सेवा भी इसी ईमानदारी के साथ करें और आम आदमी के जीवन को खुशहाल बनाने समर्पित होकर कार्य करें। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा सहकारिता विभाग के फील्ड ऑफिसर कार्यालय सहायक, समिति प्रबंधक समेत 334 पदों पर भर्ती परीक्षाएं आयोजित की गई थी। चयनित अभ्यर्थियों के लिए आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में आज मुख्यमंत्री ने उन्हें नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर चयनित अभ्यर्थियों और उनके परिवार में खुशी का माहौल था।

प्रदेश का अन्नदाता साय सरकार की धान खरीद नीति से खुशहाल है

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं प्रदेश प्रवक्ता संदीप शर्मा ने धान खरीदी को लेकर कांग्रेस द्वारा किए गए धरना-प्रदर्शन को कांग्रेस का एक और सुपर फ्लॉप शो बताते हुए कहा है कि कांग्रेस ऐसी लाख सियासी ड्रामेबाजी कर ले, लेकिन वह प्रदेश के किसानों को अपने झूठ से कतई गुमराह नहीं कर पाएगी। श्री शर्मा ने कहा कि प्रदेश का एक-एक अन्नदाता किसान आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाली भाजपा की प्रदेश सरकार की धान खरीद नीति से खुशहाल है। धान खरीदी को लेकर कांग्रेस अपने शासनकाल के धत्कर्मों पर पर्दा डालने के लिए अब किसानों को उकसा कर प्रदेश में अराजकता लाने की नाकाम कोशिश कर रही है।

भाजपा प्रदेश प्रवक्ता संदीप शर्मा ने कहा कि कांग्रेस बारदाना, टोकन और तौल को लेकर मिथ्या प्रलाप करने में लगी है। कांग्रेस को यह नहीं भूलना चाहिए कि उसके शासनकाल में धान खरीदी में समितियों में तौल को लेकर व्यापक स्तर पर गड़बड़ी की शिकायत पूरे प्रदेश से आ रही थी। श्री शर्मा ने कहा कि किसानों पर डण्डे बरसाने वाले, किसानों के घरों में छापे मरवाकर धान जब्त करके किसानों के आत्मसम्मान को

रौंदने वाले, गिरदावरी के नाम पर खेत का रकबा मनमाने कम करने वाले कांग्रेसियों की सरकार ने अपने पिछले शासनकाल में लगभग 650 किसानों को आत्महत्या के लिए विवश किया था। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार छत्तीसगढ़ वर्ष 2019 और 2020 में किसानों की आत्महत्या के मामले में देश में छठवें स्थान पर था। श्री शर्मा ने कहा कि कांग्रेस की भूपेश सरकार हर साल बारदाना के नाम पर केंद्र सरकार पर ही ठीकरा फोड़ने में लगी रहती थी।

आज बारदाने का संकट भी नहीं है और तुहँर हाथ तुहँर टोकन एप के जरिए किसानों ने हजारों टोकन स्वयं काट लिए हैं। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता संदीप शर्मा ने कहा कि राज्य की भाजपा सरकार बिना किसी अवरोध और अप्रिय प्रसंग के सुव्यवस्थित रीति से प्रदेश के किसानों का प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीद रही है और समर्थन मूल्य तथा अंतर की राशि का एकमुश्त भुगतान निर्धारित समय सीमा के भीतर कर रही है।

पिछले साल के 130 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी के विरुद्ध इस वर्ष प्रदेश की भाजपा सरकार ने 160 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य रखा है, जो कि पिछले साल से 30 लाख टन अधिक है। इस वर्ष छत्तीसगढ़ में 27.60 लाख (पिछले साल की तुलना में डेढ़ लाख से अधिक) किसानों ने अपना पंजीयन कराया है और रकबा के हिसाब से पिछले साल की तुलना में इस वर्ष किसानों ने लगभग 3.80 लाख एकड़ अधिक भूमि का पंजीयन कराया है।

धान खरीदी में अव्यवस्था दूर करने कांग्रेस ने ब्लॉकों में दिया धरना

रायपुर। किसानों को धान बेचने में हो रही परेशानी तथा धान खरीदी केंद्र में फैली अव्यवस्था को दूर करने टोकन, भुगतान, तौलाई, सोसायटी में जाम की स्थिति के निराकरण करने एवं बारदाने की कमी दूर करने, एकमुश्त भुगतान की मांग को लेकर कांग्रेस ने प्रदेश के सभी ब्लॉकों में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। मा. राज्यपाल से अनुरोध किया कि धान खरीदी की परेशानी दूर करने के लिये सरकार को निर्देश देवे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने मोहला मानपुर जिले मानपुर के दुर्गा चौक में धरने में शामिल हुये। उन्होंने कहा हम लगातार किसानों की परेशानियों को दूर करने के लिये सरकार से आग्रह कर रहे हम लोग धान खरीदी केंद्रों में गए वहां पर किसानों को परेशान किया जा रहा। सरकार की मंशा साफ नहीं है वह किसानों से पूरा धान नहीं खरीदना चाह रही। बारदानों का संकट है, टोकन नहीं मिल रहा, इलेक्ट्रॉनिक कांटे से ज्यादा मात्रा में धान लिया जा रहा, इन सबको लेकर हमने बार-बार सरकार को चेतावनी दिया। सरकार के कान में जूं तक नहीं रेंग रही। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि मुख्यमंत्री कहते है एकमुश्त पैसा दे रहे जबकि पूरे प्रदेश में मात्र 2300 की दर में भुगतान हो रहा। वादा किया था पंचायतों में काऊंटर खोलकर धान का 3100 रू. एकमुश्त भुगतान करेंगे। मैं मुख्यमंत्री को चुनौती देता हूं प्रदेश के कितने पंचायतों में काऊंटर खोलकर किसानों का भुगतान कर रहे, बताये साहस है तो एक पंचायत का नाम बता दें। हमारे सभी ब्लॉकों से अलग-अलग मा. राज्यपाल जी को ज्ञापन भेजा है। किसानों की समस्या दूर करने के लिये हस्तक्षेप करने को कहा है।

आज केबिनेट की बैठक के बाद पखांजूर जाएंगे

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय 11 दिसम्बर को नवा रायपुर में केबिनेट की बैठक के बाद वहां से हेलीकॉप्टर से पखांजूर जाएंगे। मुख्यमंत्री पखांजूर के पुराना बस स्टैण्ड एवं नेता जी सुभाषचंद्र बोस स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। जारी कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री श्री साय पूर्वान्ह 11 बजे से मंत्रालय, महानदी भवन में केबिनेट की बैठक में भाग लेने के बाद दोपहर 2 बजे पुलिस मुख्यालय हेलीपेड नवा रायपुर से हेलीकॉप्टर से पखांजूर जाएंगे। मुख्यमंत्री वहां की पुराना बस स्टैण्ड में स्वर्गीय असीम राय जी की प्रतिमा का अनावरण करने के बाद नेताजी सुभाषचंद्र बोस स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में विकास कार्यो का लोकार्पण एवं शिलान्यास और आम सभा को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री पखांजूर से संध्या 5 बजे रायपुर लौट आएंगे। मुख्यमंत्री श्री साय शाम 5 बजे रायपुर के भाटागांव अंतर्राज्जीय बस टर्मिनल में नवनिर्मित को-वर्किंग स्पेस आरंभ एवं इनोवेशन सेंटर इनोवेट का लोकार्पण करेंगे।

नई तकनीक से सुलझेंगे भूमि संबंधी विवाद, भू-स्वामियों को मिलेगा भू-आधार कार्ड

रायपुर। छत्तीसगढ़ में राजस्व प्रशासन में नई तकनीकों के माध्यम से नवाचार शुरू किया गया है। इसी तारतम्य में राजस्व प्रशासन को चुस्त-दुरूस्त करने जियो-रिफ्रेसिंग का कार्य तेजी से किया जा रहा है। इस नई तकनीक के लिए राज्य सरकार ने 150 करोड़ रूपए का प्रावधान करने के साथ-साथ राजस्व से जुड़े अमलों की व्यवस्था और उनके प्रशिक्षण की रणनीति बनाई गई है। जियो-रिफ्रेसिंग से भू-स्वामियों को जमीन संबंधी विभिन्न विवादों से मुक्ति मिलने के साथ-साथ राज्य में किसानों द्वारा लगाई गई फसल का डिजिटल क्रॉप सर्वे होने से ई-गिरदावरी में आसानी होगी। जियो रिफ्रेसिंग के माध्यम से भूमि के नक्शों के लिए खसरा के स्थान पर यू.एल. पिन नंबर दिया जाएगा। इसके साथ ही भूमिधारक को भू-आधार कार्ड भी मिलेगा।गौरतलब है कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने राज्य में सुशासन के लिए पारदर्शी और बेहतर प्रशासन के लिए शासकीय काम-काज में अधिक से अधिक आईटी का उपयोग करने के निर्देश सभी विभागों को दिए हैं। मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप राजस्व मंत्री श्री टंकराम वर्मा ने राजस्व अधिकारियों को भूमि के जियो-रिफ्रेसिंग का कार्य तेजी से पूर्ण कराने के निर्देश दिए हैं। जियो रिफ्रेसिंग तकनीक में छोटी से छोटी भूमि का लांगीट्यूड और एटीट्यूड के माध्यम से वास्तविक भूमि का चिन्हांकन करना आसान हो जाएगा।

छत्तीसगढ़/राजधानी

प्रमुख समाचार

स्थानीय निकायों में ओबीसी को 50 प्रतिशत आरक्षण देने का दावा झूठा

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में नगरीय निकायों में आरक्षण को लेकर जारी अध्यादेश छत्तीसगढ़ की बहुसंख्यक आबादी जो अन्य पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनके साथ अन्याय है। भाजपा से जुड़े लोग विज्ञापन बोर्ड पर ओबीसी को 50 प्रतिशत आरक्षण देने का दावा कर रहे हैं जो सरासर झूठ है। हक़ीक़त यह है कि आरक्षित सीटों की कुल संख्या ही अधितकम 50 प्रतिशत है, इसमें एससी, एसटी, अल्पसंख्यक और ओबीसी सभी के आरक्षण शामिल हैं। सरकार ने आरक्षण की अधिकतम सीमा 50 प्रतिशत की है, जहां एससी-एसटी की आबादी 50 फीसदी से ज्यादा है, वहां पिछड़ा वर्ग को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी मूलत: आरक्षण विरोधी है। छत्तीसगढ़ में जब ये विपक्ष पक्ष में थे, तो राजभवन की आड़ में विधानसभा से सर्वसम्मति से पारित आरक्षण विधेयक लटकाए रखें। आरक्षित वर्गो को उनकी हिस्सेदारी के अनुसार आरक्षण का लाभ देने के लिए पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार के द्वारा 2 दिसंबर 2022 को सर्वसम्मति से पारित, छत्तीसगढ़ नवीन आरक्षण विधेयक विगत 2 वर्ष से अधिक समय से आज तक राजभवन में लंबित है।

समस्याओं को कांग्रेस ने घेरा सभी 10 जोन मुख्यालयों को

रायपुर। शहर कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में मंगलवार को राजधानी के सभी 10 जोन मुख्यालयों का घेराव किया गया। नगर निगम से संबंधित आ रही समस्याओं के निराकरण के लिए नगर निगम के आयुक्त को ज्ञापन भी इस दौरान सौंपा गया। ज्ञापन में मांग की गई कि आवास सर्वे में धरसा, अस्थाई पट्टा, नहरपार, तालाबपार के निवासियों को लाभ मिलेगा की नहीं, बड़े कॉम्प्लेक्स, बड़े मकान के टैक्स छोड़कर गरीब और मध्यम वर्ग पर गलत टैक्स लगाने और दबाव बनाने जैसी समस्या, गौठान एवं गोबर खरीदी बंद करने से सैंकड़ों गाय मरने की रिपोर्ट, भाजपा के नेताओं द्वारा अवैध निर्माण, अवैध प्लाटिंग को बचाने की बात, पार्षदनिधि की समस्त वार्डों में पिछले साल से भाजपा सरकार बनने के बाद भी अभी तक राशि ना दे पाने का विरोध, भूमिपूजन की ड्रामेबाजी करने बाद अभी तक अधिकांश काम सभी वार्डों में प्रारंभ नहीं करने और भाजपा नेताओं के ठेकों में बंदरबांट होने का विरोध, विधायकों एवं सांसद द्वारा नगर निगम के रोजाना कार्यों में अनावश्यक हस्तक्षेप करने का विरोध, भाजपा सरकार के बनने के बाद बढ़ते अवैध निर्माण पर नियंत्रण ना कर पाने का विरोध कर कांग्रेस पार्टी ने सभी जोन मुख्यालयों में जाकर

इंडिगो फ्लाइट में बम की झूठी खबर देने वाला शख्स निकला अफसर

रायपुर। पिछले महीने नागपुर से कोलकाता जाने वाली इंडिगो की उड़ान में बम होने की अफवाह फैलाने के आरोप में गिरफ्तार किये गये व्यक्ति की पहचान खुफिया ब्यूरो (आईबी) के एक अधिकारी के रूप में हुई है। राजधानी रायपुर में अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 14 नवंबर को अनिमेष मंडल नामक व्यक्ति ने चालक दल को विमान में बम होने की जानकारी दी थी जिसके बाद विमान को छत्तीसगढ़ के रायपुर हवाई अड्डे पर आपात स्थिति में उतारा गया था। विमान में 187 यात्री सवार थे। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि विमान की जांच के बाद बम की धमकी झूठी निकली, जिसके बाद मंडल को कथित तौर पर गलत सूचना देने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था। मंडल के वकील फैजल रिजवी ने संवाददाताओं को बताया कि उनके मुवक्किल 'आईबी' में डीएसपी रैंक के अधिकारी हैं, जो नागपुर में तैनात हैं तथा वह निर्दोष हैं। रिजवी का कहना था कि वह सूचना साझा करने का अपना काम कर रहे थे। हालांकि, पुलिस ने कहा है कि स्थानीय पुलिस और आईबी की संयुक्त दल ने मंडल से पूछताछ की थी और उनके द्वारा साझा की गई जानकारी फर्जी पाए जाने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। रिजवी ने कहा कि 14 नवंबर को विमान में सवार होने के बाद मंडल को अपने स्रोत से बम के बारे में जानकारी मिली, जिसे उन्होंने विमान के चालक दल के सदस्यों को बताया था।

युवा क्रिकेटर आदित्य ने विजय मर्चेंट ट्रॉफी में खेली शतकीय पारी

रायपुर। हिमाचल प्रदेश के शिमोगा में खेले गए अंडर-16 विजय मर्चेंट ट्रॉफी तीन दिवसीय क्रिकेट में छत्तीसगढ़ की ओर से ग्राम देमार (पाटन) के आदित्य वर्मा ने शतकीय पारी खेली। मैच ड्रा रहा, लेकिन छत्तीसगढ़ को पहली पारी में बढ़त के आधार पर 3 अंक मिले। छत्तीसगढ़ की टीम ने हिमाचल को पहली पारी में 87 रन पर समेट दिया। वहीं, छत्तीसगढ़ की बल्लेबाजी शानदार रही। ओपनर आदित्य वर्मा और आलराउंडर रुद्र शुक्ला ने शतकीय पारी खेली। छत्तीसगढ़ ने 119 ओवर में 7 विकेट पर 388 रन बनाकर पारी घोषित कर दी। आदित्य वर्मा, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ओएसडी रहे आशीष वर्मा के सुपुत्र हैं। आदित्य के अंडर-16 विजय मर्चेंट ट्रॉफी क्रिकेट में चयन और शानदार प्रदर्शन करने पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, नगर पंचायत पाटन के अध्यक्ष भूपेन्द्र कश्यप, जनपद पंचायत पाटन के उपाध्यक्ष देवेंद्र चन्दवंशी ,ब्लाक अध्यक्ष महेंद्र वर्मा, हेमंत देवागन, राजेश ठाकुर, जिला पंचायत के उपाध्यक्ष अशोक साहू, अपेक्स बैंक के पूर्व डायरेक्टर राकेश ठाकुर, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक दुर्ग के पूर्व अध्यक्ष जवाहर वर्मा, पूर्व मंडी अध्यक्ष अश्वनी साहू, पूर्व जिला पंचायत सदस्य जयश्री वर्मा, जनपद सदस्य खिलेश मार्कण्डेय, संजय यदु, त्रिभुवन यदु ने हर्ष व्यक्त करते हुए आदित्य वर्मा को बधाई दी है और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है।

कृषि विश्वविद्यालय में जुटेंगे देश भर के कृषि अर्थशास्त्री

रायपुर। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर में कृषि अर्थशास्त्र अनुसंधान संघ, नई दिल्ली का तीन दिवसीय 32वां वार्षिक सम्मेलन 11 से 13 दिसम्बर, 2024 तक ''उच्च, सतत और समावेशी विकास के लिए कृषि का डिजिटलीकरण'' विषय पर आयोजित किया जा रहा है। सम्मेलन का शुभारंभ कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी मंत्री श्री रामविचार नेताम करेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता वित्त, वाणिज्यिक कर, आवास और पर्यावरण, योजना तथा आर्थिक एवं सांख्यिकी मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी करेंगे। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. गिरीश चंदेल, नाबार्ड छत्तीसगढ़ के मुख्य महाप्रबंधक डॉ. ज्ञानेन्द्र मणि, कृषि अर्थशास्त्र अनुसंधान संघ, नई दिल्ली के अध्यक्ष डॉ. पी.के. जोशी, कृषि अर्थशास्त्र अनुसंधान संघ, नई दिल्ली के सम्मेलन अध्यक्ष डॉ. पी.एस. बिरथल एवं राष्ट्रीय जैव स्ट्रैस प्रबंधन संस्थान, बरौंडा, रायपुर के निदेशक डॉ. पी.के. घोष उपस्थित रहेंगे। कृषि अर्थशास्त्र अनुसंधान संघ, नई दिल्ली एक पंजीकृत सोयायटी है जो 1987 में अस्तित्व में आई और वर्तमान में भारत और विदेश में इसके 1200 से अधिक आजीवन सदस्य हैं। संघ कृषि अर्थशास्त्र, नीति विश्लेषण और ग्रामीण विकास में गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान को बेहतर बनाने में योगदान देता है।

जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन और विकास कार्यों की करेंगे मॉनिटरिंग

प्रदेश के सभी 33 जिलों में प्रभारी सचिव नियुक्त

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में जनकल्याणकारी कार्यक्रमों के क्रियान्वयन और विकास कार्यों की मॉनिटरिंग के लिए प्रभारी सचिव नियुक्त किए गए हैं।

संबंधित जिले के प्रभारी सचिव, जिले में संचालित योजनाओं और विकास कार्यों की सतत् मॉनिटरिंग करेंगे, ताकि विकास कार्यों को गति दी जा सके। प्रभारी सचिव प्रतिमाह कम से कम एक बार अपने प्रभार जिले का भ्रमण कर विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे और अपने भ्रमण के संबंध में एक संक्षिप्त टीप प्रतिमाह मुख्य सचिव को प्रस्तुत करेंगे। सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार अपर मुख्य सचिव रेणु जी पिल्ले को धमतरी जिला का प्रभारी सचिव नियुक्त किया गया है। इसी प्रकार अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू को दुर्ग, मती ऋचा शर्मा को रायपुर, मनोज कुमार पिंगुआ को बिलासपुर जिला, प्रमुख सचिव मती निहारिका बारिक को महासमुंद जिले का प्रभारी सचिव नियुक्त किया गया है।

प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा को जांजगीर चांपा, सचिव रोहित यादव को कोरबा, सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह को बस्तर, सचिव परदेशी सिद्धार्थ कोमल को बलौदाबाजार-भाटापारा, सचिव अविनाश चंपावत को राजनांदगांव, सचिव प्रसन्ना आर. को कबीरधाम, सचिव अम्बलगन पी. को जशपुर, सचिव सु आर शंगीता को सारंगढ़- बिलाईगढ़, सचिव रजत कुमार को रायगढ़, सचिव राजेश सुकुमार टोप्पो को नारायणपुर, सचिव एस. प्रकाश को कोरिया, सचिव अंकित आनंद को बालोद, सचिव डॉ. सी. आर. प्रसन्ना को बेमेतरा, सचिव भुवनेश यादव को सूरजपुर, सचिव एस. भारतीदासन को मुंगेली जिले का प्रभारी सचिव नियुक्त किया गया है।

सचिव सु शम्मी आबिदी को कांकेर, सचिव हिमशिखर गुप्ता को गरियाबंद, सचिव मो. कैसर अब्दुलहक को गौरला-पेण्ड्रा-मरवाही, सचिव यशवंत कुमार को बलरामपुर-रामानुजगंज, सचिव भीम सिंह को कोण्डागांव, सचिव मती शिखा राजपूत तिवारी को खैरागढ़-छुईखदान-गंडई, सचिव नरेन्द्र कुमार दुग्गा को सुकमा, आयुक्त मती किरण कौशल को सक्ती, संचालक सौरभ कुमार को दंतेवाड़ा, संचालक सुनील कुमार जैन को सरगुजा, विशेष सचिव जयप्रकाश मौर्य को मोहला-मानपुर-अम्बाग? चौकी, विशेष सचिव सारांश मित्तर को बीजापुर और प्रबंध संचालक रमेश कुमार शर्मा को मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले का प्रभारी सचिव नियुक्त किया गया है।

श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में शोध कार्य के एक्सचेंज प्रोग्राम की पहल

रायपुर। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में शोध गतिविधियों को बढ़ावा देने एवं नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत विधार्थियों को नवाचार से परिचित कराने विभिन्न संस्थाओं से एम यू किया जा रहा है।विश्वविद्यालय की प्राध्यापक डॉ गुंजन जैसवानी ने बताया कि इसी क्रम में दाऊ वासुदेव चंद्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय के साथ एम ओ यू किया गया,जिसमे दोनों विश्वविद्यालय के मध्य शोध कार्य के लिए संयुक्त परियोजना कार्य के साथ विधार्थियों के इंटर्नशिप को बढ़ावा दिया जाएगा। दोनों संस्थाओं के विषय विशेषज्ञों का लाभ विधार्थियों को सतत रूप से मिलेगा।

विश्वविद्यालय के रिसर्च डायरेक्टर डॉ धनेश कुमार जोशी ने जानकारी देते हुए बताया कि विश्वविद्यालय में आयोजित दो दिवसीय इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में कामधेनु विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ आर आर बी सिंह एवं श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉ ए के झा ने एम ओ यू में हस्ताक्षर किए।इस अवसर पर अपने उद्बोधन में कुलपति डॉ आर आर बी सिंह ने कहा कि शोध कार्य का महत्व आज के समय में आवश्यक ही नहीं महत्वपूर्ण हो गया है।राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत अब विधार्थियों को किताबी ज्ञान के साथ साथ प्रायोगिक कार्य,कौशल विकास और इंटर्नशिप अनिवार्यत: करनी होगी,जिससे वे सीखेंगे भी और कौशल विकास के जरिए उन्हें रोजगार के अवसर का लाभ मिलेगा। एम ओ यू के माध्यम से नवीन आधुनिकतम उपकरणों का लाभ सभी विधार्थियों को मिलता है। कुलपति डॉ ए के झा ने भी कहा कि यह एम ओ यू मिल का पत्थर साबित होगा।हमारे विधार्थियों को कामधेनु विश्वविद्यालय की आधुनिक प्रयोगशालाओं एवं विशेषज्ञों का लाभ मिलेगा।जिससे परस्पर जान का आदान प्रदान हो सकेगा। प्रो.जोशी ने बताया कि विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में देश के विभिन्न क्षेत्रों से 300 से अधिक शोधपत्र प्रस्तुत किया गए।पोस्टर प्रेजेंटेशन के माध्यम से भी शोध पत्र की प्रस्तुति दी गई। श्रेष्ठ शोध कार्य को प्रोत्साहित करने

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.